सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा | सोमवार, तिथि 15 मार्च, 2021 (ई०)

द्वितीय सत्र | 24 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11:00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, गांव में...

अध्यक्ष: अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली...

अध्यक्ष : अनुमति के बिना आप उठे कैसे ? पहले बैठिये, पहले बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : सुना जाय महोदय...

अध्यक्ष : सत्यदेव बाबू, बैठ जाइये । फिर हम अनुमति देंगे तब उठिएगा ।

श्री सत्यदेव राम : नया-नया कपड़ा पहनकर आत्महत्या किये हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, एक आदमी बोलेंगे । आप बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : क्या स्थिति रही कि नया-नया कपड़ा पहनकर एक परिवार के पांच सदस्य सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली, यह आर्थिक तंगी का मामला था...

अध्यक्ष : आपका कार्यस्थगन आया है, उचित समय पर उठाइएगा । बैठ जाइये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यह गंभीर मामला है, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए...

अध्यक्ष : कार्यस्थगन आपने दिया है, उचित समय पर उठाइएगा, बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-'क'-38 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उत्तर नहीं आया हुआ है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव : लेकिन उत्तर नहीं आया हुआ है महोदय, यह आसन के संज्ञान में...

अध्यक्ष : उत्तर पढ़ दिया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 12 जिलों में 66 कांडों में 35.49 करोड़ रुपये से अधिक गबन के संबंध में निबंधक सहयोग समिति का पत्र, पत्रांक-432, दिनांक-25.01.2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुआ । पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक-383, दिनांक-10.03.2021 द्वारा इस संबंध में संबंधित जिलों से अद्यतन कार्रवाई से संबंधित स्थिति की मांग की गई है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि इस संबंध में अब तक 09 जिलों-(गया, नालंदा, पूर्णिया, भोजपुर, बक्सर, सुपौल, कटिहार, बांका एवं शेखपुरा) से 38 कांडों का अद्यतन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुआ है । कुल 31 अभियुक्त आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त हैं । इन कांडों में कुल 16 अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया है । 04 अभियुक्तों के विरूद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है ।

शेष काण्डों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा रही है और कांडों का अनुसंधान यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास जारी है ।

3- उपर्युक्त कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आसन से बार-बार निदेश होता है कि विभाग को ऑनलाइन जवाब देना चाहिए । महोदय, ये पहले से प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने ठीक है अभी ही जवाब दिया है । महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं, ये भी स्वीकार किए हैं कि 35 करोड़ के लगभग इसमें घोटाला हुआ है । महोदय, माननीय मंत्री जी का भी जवाब है । हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि यह मामला 2011-12 से चल रहा है और 2017-18 के बीच का मामला है । महोदय, एक तो हम जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने इसका ऑडिट कराया है कि नहीं कराया है, दूसरा महोदय, निबंधक रजिस्ट्रार ने पत्र डी0जी0पी0 को बहुत पूर्व में ही लिखा था और उसका भी करीब-करीब 8 साल हो गया । महोदय, माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि यह सत्ता संरक्षित ये लूट हुई है, जिसको आपने इतने लंबे समय से बचाने का काम किया, यदि इसमें जांच प्रोपर नहीं हो रही है तो सरकार सी0बी0आई0 से जांच कराना चाहती है इसको ? महोदय, इतना लंबा समय 8 साल लग जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि रजिस्ट्रार से दिनांक-25.01.2021 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुआ और दिनांक-10.03.2021 द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के एस0पी0 को और जिला पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए कहा गया और मैंने विस्तृत कहा कि 09 जिलों में 38 कांडों का अद्यतन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है । कुल 31 अभियुक्त आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त हैं । इन काडों में कुल 16 अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया है । 4 अभियुक्तों के विरूद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है । 3 महीना पहले ही को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने भेजा है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, स्पष्ट नहीं हुआ । महोदय, हमने कहा कि यह वर्ष 2017-18 में ही एफ0आई0आर0 हुई है, महोदय । प्रश्न में है, आप देखिए । प्रश्न में ही है वर्ष 2017-18 में ही एफ0आई0आर0 हुआ है...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप सुन लीजिए न पहले । आप पहले अपने प्रश्न को पढ़िये न । क्या यह बात सही है कि सूबे में किसानों से धान और गेहूं की खरीद के लिए मिली सरकारी राशि में से राज्य के 13 जिलों के पैक्स एवं व्यापार मंडलों ने 35 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया । क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011-12 वाला । वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2017-18 के बीच उस संबंध में कोई रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को प्राप्त नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमने कहा कि इतने इतने दिनों से मामला लंबित है, माननीय मंत्री जी ने इसका कभी कोई ऑडिट कराया है कि कितने का ये शेष और जिलों में है, पूरे बिहार के और जिलों में है कि जो प्रश्नाधीन जिला है, उसी में है ? पूरे राज्य में यह ऑडिट कराकर जांच कराये हैं कि इसमें और कितने की गड़बड़ी है ?

अध्यक्ष : ये सुझाव है आपका ?

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, सुझाव नहीं है । हम प्रश्न के माध्यम से जानना चाहते हैं...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप जरा बैठिए न । ये को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट से पूछिए, गृह विभाग ऑडिट कराने के लिए नहीं है....

अध्यक्ष : ठीक है, अलग से प्रश्न ले आइएगा ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और सरकार जवाब दे रही है...

अध्यक्ष : गृह विभाग से जवाब है, आपका ...

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : गृह विभाग को उतना ही से मतलब है...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, स्थगित कर दीजिए इस प्रश्न को, को-ऑपरेटिव विभाग को...

अध्यक्ष : आप अलग से ले लीजिए इसका जवाब । इस प्रश्न का जवाब तो ये दे दिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार में इतनी बड़ी लूट हो गयी और सत्ता संरक्षित में यह लूट हुई है । महोदय, यदि सक्षम नहीं है बिहार पुलिस तो इसकी सी0बी0आई0 से जांच करवा दीजिए । यदि सरकार सक्षम नहीं है, महोदय, ये ऑडिट क्यों नहीं कराइएगा, पूरे बिहार का...

अध्यक्ष : आप अलग से प्रश्न ले आइए ।

श्री ललित कुमार यादव : ये वर्ष 2011-12 से मामला है...

अध्यक्ष : श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : ये वर्ष 2011-12 से मामला है और 8 साल हो गया महोदय, इसको ऑडिट क्यों नहीं सरकार कराना चाहती है...

अध्यक्ष : आज लगातार आप तीन बार बोलेंगे और अवसर आयेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक प्रश्न का जवाब तो हो जाय...

अध्यक्ष : एक चीज ललित जी, एक मिनट ।

श्री ललित कुमार यादव : सरकार कह रही है कि माकूल जवाब देगी सदन में...

अध्यक्ष : ललित जी, एक मिनट ।

श्री ललित कुमार यादव : सरकार ये जवाब माकूल नहीं...

अध्यक्ष : आप जो बोले, देखिए । सदन आपलोगों की गंभीरता से कितना गंभीर है कि आज 6 विभाग का अल्पसूचित है । 8 प्रश्न हैं, जिसमें से 7 का जवाब आया है और 5 विभागों ने 100 परसेंट जवाब दिया है । एक विभाग ने 2 में 1 का जवाब दिया है तो आप चाहते हैं कि सभी के जवाब सदन पटल पर आ जायं ।

श्री ललित कुमार यादव : उसी का ऑडिट हुआ ...

अध्यक्ष : चलिए । दूसरा प्रश्न आपका है, पूछिए...

श्री ललित कुमार यादव : सरकार बताना नहीं चाहती है तो स्थगित प्रश्न का भी ऑनलाइन जवाब...

अध्यक्ष : कह तो दिए कि...

श्री ललित कुमार यादव : आप कह रहे हैं 100 परसेंट जवाब आया है महोदय...

अध्यक्ष : आप देख लें कि...

श्री ललित कुमार यादव : स्थगित प्रश्न का नहीं आया है, 15 दिन से ऊपर का यह प्रश्न है...

अध्यक्ष: नहीं जवाब...

श्री ललित कुमार यादव : नहीं आया है ।

अध्यक्ष : अभी 100 परसेंट वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, निर्वाचन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, उद्योग विभाग ।

श्री ललित कुमार यादव : इसको स्थगित कर दीजिए महोदय...

अध्यक्ष : नहीं, एक बार स्थगित हो चुका है । अब आगे श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार कह रही है...

अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न आपका है श्री ललित कुमार यादव ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम सरकार से पूछ रहे हैं...

अध्यक्ष : अब दूसरा प्रश्न लें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आसन का निदेश...

अध्यक्ष : श्री ललित कुमार यादव, दूसरा प्रश्न ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-48 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक ।

प्रश्नगत वाहन का निबंधन संख्या- BR21G-5263 है, जो बस है। लेकिन लिपिकीय भूलवश G के स्थान पर लॉगबुक पर D अंकित हो गया है, जिस वजह से यह वाहन MParivahan app पर बस के स्थान पर M/Cycle प्रदर्शित हो रहा है । यह वाहन कुल 42 दिनों के लिए अधिग्रहित रही है एवं इस वाहन द्वारा कुल 3144 किलोमीटर का परिचालन हुआ है । इसके विरूद्ध इस बस में 870 लीटर डीजल की आपूर्ति की गई है । केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए प्रयुक्त इस बस द्वारा चार जिलों (पटना, नालंदा, नवादा एवं बेतिया) में परिचालन किया गया है एवं कंपनी कमांडर के द्वारा लॉगबुक को सत्यापित भी किया गया है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक ।

लोकसभा चुनाव, 2014 के अवसर पर पटना जिला अर्द्धसैनिक बल की 43.1 कंपनी, बी0एम0पी0 बल की 22 कंपनी एवं वज्रगृह सुरक्षा के लिए दो प्लाटुन CISF का उपयोग किया गया था । इस प्रकार उक्त अर्द्धसैनिक बलों के ठहरने के लिए कुल 2426951 (चौबीस लाख छबीस हजार नौ सौ इक्यावन रुपये) मात्र व्यय किये गये।

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 में 126 कंपनी अर्द्धसैनिक बलों के लिए चयनित वेण्डरों द्वारा जिला के सभी प्रखंडों में कार्य किया गया जिसके विरूद्ध 42 करोड़ के विपत्र समर्पित किया गया, जिसे जिला स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है, जांचोपरांत ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा भुगतान किया जायेगा । विदित हो कि उक्त कार्य के विरूद्ध किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया ।

3- गठित कमिटी के जांचोपरांत ही विपत्रों की भुगतान की कार्रवाई की जाती है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ये सरकार का जवाब है कि लिपिकीय भूल के कारण ये हुआ है । लिपिकीय भूल के कारण, जिसके कारण लिपिकीय भूल हुई, उस पर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा हुई है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, निर्वाचन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, चूंकि उत्तर में सबकुछ स्पष्ट है कि गाड़ी संख्या थी BR21G-5263, उसके स्थान पर भूलवश लिखा गया BR21D, G के बदले D लिखा गया था जो दोपहिया का था लेकिन समय पर वह डिटेक्ट हो गया और जो असली गाड़ी नंबर था जो BR21G-5263 है, वह सही मायने में बस का है और उसमें सबकुछ डाला हुआ है महोदय, ये सब कुछ आजकल ऑनलाइन होता है । जो M Parivahan app है, वह बस के लिए ही है और उसमें जितना 3144 किलोमीटर परिचालन हुआ है और चूंकि समय पर यह भूल पकड़ ली गई थी और ऑफिस के द्वारा ही भूल पकड़ी गई थी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में ये है लेकिन हम कह रहे हैं कि ये कह रह हैं कि लिपिकीय भूल है इनके उत्तर में तो ये जो लिपिकीय भूल हुई, इसके लिए कोई जिम्मेवार थे, तो उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ?

...क्रमशः...

टर्न-2/मुकुल-राहुल/15.03.2021

क्रमशः

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि 42 करोड़ के विपत्र की जांच का फलाफल क्या हुआ, इसके बारे में भी मंत्री जी बताएं ? अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बिहार के केवल 8 जिलों में जांच करायी है या पूरे

बिहार में जांच कराये हैं ? अगर ये सारे जिलों की जांच कराये हैं तो अन्य जिलों की क्या स्थिति है इसके बारे में बतायें ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो मूल रूप से पटना जिला से संबंधित है और माननीय सदस्य ने जो 42 करोड़ की बात की है और उसके भुगतान के संबंध में जानना चाहा है तो हमने कुछ उत्तर में भी यह स्पष्ट किया है और हम सदन को बताना चाह रहे हैं कि जो 42 करोड़ का विपत्र पटना समाहरणालय में समर्पित किया गया है उसकी जांच त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा की गई है और फिर एक दूसरी जांच भी चल रही है जो अलग-अलग प्रखंडों से, जहां-जहां केन्द्रीय पारा-मिल्ट्री फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया था, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से भी इसका फिर से सत्यापन कराया जा रहा है तब ही भुगतान होगा और सरकार ने स्वयं इसकी जांच प्रारंभ की है और सदन को बताते हुए इसमें कोई दोराय नहीं है कि यह जो 42 करोड़ रुपये की राशि है यह अभी तक की जांच में ही काफी कम हुई है और हम लोग और इसकी गहराई से जांच करा रहे हैं और सदन को हम बताना चाहते हैं कि जब तक इसकी पूरी जांच नहीं कर ली जायेगी, अभी तक एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया है और जांच में जो सही पाये जायेंगे उन्हीं का भुगतान होगा ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को देखा जाय । हमने कहा कि ...

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष का भी प्रश्न है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, उनका प्रश्न है लेकिन समय भी काफी है । महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने बिहार के अन्य जिलों की भी जांच कराई है या नहीं? यह तो केवल पटना जिला के बारे में है, प्रश्न में भी पटना जिला के अलावे बिहार...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया है कि इसकी जांच की शुरुआत हुई है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में पटना जिला के अलावा पूरे राज्य के बारे में है, ये और जिलों की जांच करवायेंगे कि क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब भी है और सरकार के हित में है और जैसा कि हमने कहा कि पटना में जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसी तरह का निदेश सरकार सभी जिलो को देगी कि पूरी जांच के बाद ही चुनाव से संबंधित किसी विपत्र का भुगतान किया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है, श्री ललित कुमार यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-49 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा अभी तक वर्ष 2020 का आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया गया है, बल्कि अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा संधारित आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में राज्य में औसतन प्रतिदिन 9 हत्या, लूट तथा 4 बलात्कार की घटनाएं घटित हुई हैं ।

विगत 06 माह में (सितम्बर 2020 से फरवरी 2021 लगभग) राज्य में औसतन प्रतिदिन 8 हत्या, 6.15 लूट तथा 3.73 बलात्कार की घटना घटित हुई है ।

जिला पुलिस द्वारा ठोस सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है । अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी, लूटे सामानों की बरामदगी तथा गंभीर कांडों में त्वरित विचारण करा कर घटना में शामिल अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है । राज्य के नागरिकों में भय का माहौल नहीं है और अपराध एवं विधि-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित है ।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है । आप पूरक पूछिये और पूरक जरा छोटा पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, 20 मिनट कर्णांकित समय है ।

अध्यक्ष: अब कहां समय है ? आप अपनी बात को शॉर्ट कीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हत्या, लूट और बलात्कार की घटना, सरकार ने भी कबूल किया है कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और जो प्रश्न में पूछा गया है वह सही है और सरकार ने भी इस बात को माना है । हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कौन सा ब्लू-प्रिंट तैयार किया है या सरकार अपने स्तर पर कौन सी ठोस कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जिला पुलिस द्वारा ठोस सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है । अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी, लूटे सामानों की बरामदगी तथा गंभीर कांडों में त्वरित विचारण करा कर घटना में शामिल अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है । राज्य के नागरिकों में भय का माहौल नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि राज्य में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं और उनको रोकने में सरकार विफल है । हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि सत्ता संरक्षित में कितने लोग आरोपी हैं, उस पर सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है या सत्ता संरक्षित अपराध बढ़ाना चाहती है ?

अध्यक्ष: अब जवाब हो गया है । श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-50 (श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, क्षेत्र संख्या-128 राघोपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाइयों पर गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु निजी निवेशक को लीज पर चलाने के लिए सरकार के निर्णय के आलोक में वित्तीय सलाहकार, एस0बी0आई0 कैप्स के माध्यम से पांच निविदायें आमंत्रित की गयी थीं । उक्त निविदा प्रक्रियाओं के अन्तर्गत बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 7 इकाइयों को निजी निवेशक को गन्ना आधारित उद्योग अथवा अन्य उद्योग के लिए लीज पर हस्तांतरित किया गया है ।

क्रमांक	इकाई का नाम	निवेशक का नाम	निविदित राशि(करोड़)	जमा की राशि (करोड़)
1.	लौरिया	मेसर्स एच0पी0सी0एल0 बायोफ्यूल्स लि0	45.00	45.00
2.	सुगौली	मेसर्स एच0पी0सी0एल0 बायोफ्यूल्स लि0	50.00	50.00
3.	समस्तीपुर	विनसम इन्टरनेशनल लि0	28.77	28.77
4.	रैयाम	मेसर्स तिरहुत इंडस्ट्रीज लि0	9.11	9.11
5.	सकरी	मेसर्स तिरहुत इंडस्ट्रीज लि0	18.25	9.125
6.	बिहटा	मेसर्स प्रिस्टाइन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0	23.16	11.58
7.	मोतीपुर	इंडियन पोटाश लि0	56.20	28.10

वर्तमान में बिहार राज्य चीनी निगम के 8 बंद इकाइयों (फार्म लैण्ड सहित) को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को Priority Sector की उद्योगों की स्थापना हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई-लौरिया एवं सुगौली हेतु सफल निवेशक मेसर्स एच0पी0सी0एल0 बायोफ्यूल्स लिमिटेड द्वारा चीनी मिल का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है एवं इन इकाइयों में चीनी, कोजेन-सह-विद्युत एवं इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है । सकरी इकाई हेतु सफल निवेशक मेसर्स श्री तिरहुत इण्डस्ट्रीय लिमिटेड द्वारा लीज डीड के शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उनके साथ किये गये एकरारनामा को निरस्त

करते हुये जमा राशि को जब्त कर लिया गया है । रैयाम इकाई हेतु सफल निवेशक मेसर्स श्री तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि0 को चीनी उद्योग की स्थापना नहीं करने के कारण तीन लीगल नोटिस दिया गया है । बिहटा इकाई के सफल निवेशक मेसर्स प्रिस्टाइन मगध इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा आरबिट्रेशन दायर किया गया है । मोतीपुर इकाई के सफल निवेशक इंडियन पोटाश लि0 (आई0पी0एल0) का मामला व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीन है ।

3. उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है, हम मंत्री जी से पूरक सवाल पूछना चाहेंगे । सवाल हमारा था कि वर्ष 2005 के बाद बिहटा सहित जितनी भी चीनी मिलें जो बिहार भर में हैं, क्या उनकी सम्पत्तियों को औने-पौने दाम में निजी क्षेत्रों के लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं ? मंत्री जी का उत्तर मिला है और इसमें उन्होंने 7 इकाइयों का जिक्र किया है, लेकिन डिटेल में समस्तीपुर इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है । अगर उत्तर 2 में देखें तो समस्तीपुर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है । महोदय, दूसरी बात हम यह पूछना चाहते हैं कि उत्तर में डेट भी मेंशन नहीं की गई है कि यह हस्तानांतरण कब किया गया है, कौन से साल किया गया है ? हम चाहेंगे कि मंत्री जी कृपा करके जरा समस्तीपुर के बारे में जानकारी देंगे और तारीख जो है वह भी बताएंगे और साथ में सकरी मेसर्स तिरहुट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो बात है, जो जमा राशि की गई है महोदय, वह 9 करोड़ 125 रुपया है और इन्होंने कार्रवाई हेतु, क्योंकि अब तक कोई और इंडस्ट्री चालू नहीं कर पाए, उसके लिए इन्होंने कहा कि तीन लीगल नोटिस भेजने का काम किया है, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि अब तक आप लोग लीगली नोटिस भेजते रह जाइए 9 करोड़ जमाराशि तो आपने जब्त कर ली है, लेकिन 20 करोड़ का उन्होंने स्क्रैप बेचने का काम किया है तो अब तक इन सभी स्थितियों की वस्तुस्थित क्या है । जो स्क्रैप है वह वहां कायम है या नहीं है या उन लोगों के द्वारा बेच दिया गया है, जो भी है तो महोदय...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, हम यह जानना चाहेंगे और उत्तर में वर्ष 2008 का भी, उस समय मुख्यमंत्री जी के पास ही यह डिपार्टमेंट था...

अध्यक्ष: पूरक पूछ लीजिए, जवाब देंगे । समय नहीं है, समय समाप्त होने वाला है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं । महोदय, मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे । Reliance HPCL to revive 20 sugar mills, यह वर्ष 2008 का

बयान है । महोदय, क्या वर्ष 2008 से अब तक रिवाइव हो ही रहा है ? कोई जिक्र नहीं है ।

अध्यक्षः मानननीय मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः महोदय, नेता प्रतिपक्ष को हम लोगों ने डिटेल में जवाब दिया है और जो समस्तीपुर इंडस्ट्री के बारे में है उसमें हमने समस्तीपुर जो उद्योग है यह Vinissimus International Ltd. Kolkata को इसकी इकाई Vinissimus International Ltd. Kolkata मो0 28.77 करोड़ रुपया में जूट एवं फूड प्रोसेसिंग उद्योग वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स सहित की स्थापना के उद्देश्य से इकरारनामा एवं लीज डील दिनांक-05.03.2021 को स्थानांतरित की गई है । दिनांक-05.03.2021 को समस्तीपुर का है, दूसरा जो है रैयाम के बारे में तो इस इकाई को मैसर्स तिरहुट इंडस्ट्रीज लि0 को 9.11 करोड़ रुपया में हस्तानांतरित की जा चुकी है । रैयाम इकाई का अस्तित्व एवं भूमि का हस्तानांतरण निवेशक को किया जा चुका है । इकाई स्थल पर चीनी मिल अब तक स्थापित नहीं होने के कारण 3 लीगल नोटिस दिए गए हैं । निवेशक द्वारा नोटिस में...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, बाकी का तो जवाब...

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः प्लांट स्थापित करने का उल्लेख किया गया है । महोदय, ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है और स्वयं नेता प्रतिपक्ष न्यायालय से अवगत हैं...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्षः पहले मंत्री जी का जवाब हो जाने दीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः महोदय, स्वयं नेता प्रतिपक्ष न्यायालय की प्रक्रिया से अवगत हैं । अब जो मामला न्यायालय के अधीनस्थ चला जाता है उसमें बिना न्यायालय का प्रतिफल आए हुए सरकार कुछ कर सकती है ?

अध्यक्षः ठीक है बैठिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, उत्तर में साफ-साफ है कि 3 मामले जो हैं, 3 इकाइयों के वे न्यायालय में हैं, सभी का नहीं है । आप कह रहे हैं कि इसी साल मार्च में आप लोगों ने एग्रीमेंट किया, क्या तारीख है आप फिर से थोड़ा दोहराएंगे?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः 05.03.2021 है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः 05.03.2021 को यानी 05 मार्च को जो है, हमारे प्रश्न पूछने से 10 दिन पहले आपके विभाग ने इसको करने का काम किया । इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभाग कितनी तेजी से कार्रवाई कर रहा है, कोई गंभीरता नहीं । महोदय, दूसरी बात इसमें हमने बताने, हमने तो स्क्रैप के बारे में पूछा । जमा राशि 9 करोड़ का

है, स्क्रैप बेच दिया 20 करोड़ का, बाकी का पैसा और बाकी मिलों का जो पैसा है, स्क्रैप है वह कहां गया ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी प्राप्त कर लें ।

टर्न-3/यानपति-अंजली/15.03.2021

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, राज्य सरकार ने जितनी निगम की बंद चीनी मिलें थीं उसकी स्टेट बैंक से इसकी बिटिंग कराई और उस बिटिंग में जमीन और जो स्टेट्स था इस सब के साथ उसका बिटिंग हुआ, उसके आधार पर लीगल तरीके से स्टेट बैंक ने इसका बीट निकाला और जो हाइएस्ट बीट था, उसको दिया गया और जो महोदय...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो हैं, वह मिसगाइड कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, मिसगाइड नहीं कर रहे हैं । यही नियमावली थी । ये स्टेट, जो हम बता रहे हैं तो जो महोदय...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, कैसे मिला यह हम नहीं पूछ रहे हैं, ये स्क्रैप ...

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, यही सिस्टम है, इसमें स्क्रैप का प्रश्न ही नहीं है ।

अध्यक्ष: बैठ जाइये । नेता प्रतिपक्ष स्क्रैप का प्रश्न नहीं है, आप प्रश्न एक अलग से लिखकर भेज दें और आप माननीय मंत्री जी...

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, यह चीनी मिल के बिट का प्रश्न है । तो स्टेट बैंक का...

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: तो शुगर मिल में बदलेगा कैसे ? शुगर मिल का प्रश्न है। शुगर मिल में से स्क्रैप ही गायब हो जायेगा, तो बदलेगा कहां, आप रिवाइव कैसे कीजियेगा ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, स्टेट बैंक ने जो बिट तैयार किया, जो लीगल कॉन्सेप्ट आया उसके हिसाब से सरकार ने इस काम को किया । अब ये जो स्क्रैप का मामला, इसमें स्क्रैप का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, करेक्ट कर रहे हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है बैठ जाइये । बोलिये, आप सब मत बोलिये, जब वह बोल रहे हैं तो सुनिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, यहां एस0बी0आई0 कैप के माध्यम से इन्होंने दिया 7 इकाई को, तो हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वह तो एस0बी0आई कैप के द्वारा आप लोगों ने दिया ।

अध्यक्ष: आपका तो स्क्रैप का मामला है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हम पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा कि एस0बी0आई0 कैप का जिक्र किया, हम कह रहे हैं ठीक है, उसी के द्वारा आपने जो है 7 मिलों को दे दिया, लेकिन जो 7 मिलों को दिया, तो मान लीजिए जो स्क्रैप वहां शुगर मिल में था, आपको तो रिवाइव करना है, तो उसमें आप रिवाइव अब तक नहीं कर पाए? जो स्क्रैप रहता है वह औने-पौने दाम पर जो है आपने पहले शुगर मिल दे दिया और बाकी का मान लीजिए, आपने जमाबंदी जो की है 9 करोड़ रुपये की आपने कार्रवाई की है, जब्त कर लिया, जो जब्त कर लिया लेकिन स्क्रैप तो 20 करोड़ रुपये का था । मेरा सवाल लीज देने का नहीं है...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप इसको दिखवा लें, इसकी जांच करवा लें ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, यह प्रश्न जो है इसमें सवाल ही नहीं उठता है । महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी प्रॉपर्टी को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइये । नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइये । माननीय सदस्य जो प्रश्न करते हैं, पूरक प्रश्न में सदस्य की गंभीरता अगर दिखाई पड़ती है राज्यहित, लोकहित में, तो उसको गंभीरता से लें, उसकी जांच कराएं और जो पदाधिकारी गंभीरता से जवाब नहीं देकर बरगलाने का काम करते हैं, उसपर एक्शन और कार्रवाई की भी बात करें । अब समय खत्म हो गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, अभी सप्लीमेंट्री खत्म नहीं हुआ ।

अध्यक्ष: आपका समय खत्म हो गया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, इन्होंने 7 इकाई का...

अध्यक्ष: अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न चल रहा है...

अध्यक्ष: अब नहीं, समय समाप्त हो गया । 11.20 तक का ही समय था ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री चल रहा है उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाय, उसके बाद तारांकित जो है, वह शुरू होना चाहिए । आपने जो तारीख..

(व्यवधान)

सुन तो लीजिए ।

अध्यक्ष: अब समय हो गया, जांच की बात हो गई है अब इस पर नहीं...

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मेरा तो अधिकार है सप्लीमेंट्री पूछने का...

अध्यक्ष: तीन पूरक आपके हो गये हैं, इसलिए हम आपको बैठने के लिए कह रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, नहीं हुआ है महोदय, कौन से तीन पूरक हैं मंत्री जी से पूछ लीजिए, कौन-से मैंने तीन सप्लीमेंट्री पूछे, तब हो जाता, तब आप अगले तारांकित पर जाइयेगा, जरा पूछ के बताइए कि कौन-से तीन सप्लीमेंट्री हमने पूछे हैं?

अध्यक्ष: आपने तीन बार उठ-उठकर प्रश्न पूछा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हम करेक्ट कर रहे थे एक ही उत्तर का, एक ही सप्लीमेंट्री का...

अध्यक्ष: अच्छा करेक्ट कर लेते हैं, सुन लीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे हैं कि आपने जो तारीख बतायी है केवल एक ही की समस्तीपुर की तारीख बतायी है कि कब एग्रीमेंट हुआ, बाकी आपने सातों की तो बतायी नहीं, है न ?

अध्यक्ष: अलग से तिथि इनको बता दीजियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: नहीं, नहीं अध्यक्ष महोदय...

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, हमने यह स्पष्ट रूप से जिक्र किया है कि स्टेट बैंक के द्वारा खुला बिटिंग हुआ और जो लोग दिये तो स्टेट बैंक ने जो बिटिंग किया, तो उस बिटिंग में जो उसका मूल्यांकन हुआ, तो फैक्ट्री बेच दी गई ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप इनकी बातों को ग्रहण कर लीजिए ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, एस0बी0आई0 से आपने राय-मशविरा करके दे दिया, दिया कब, यही तो पूछ रहे हैं और सब का बताइए न डेट और एग्रीमेंट की तारीख ।

अध्यक्ष: जानकारी नहीं है तो जानकारी ग्रहण कर के बता दीजियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिये...

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमने सबकी डेट बतायी है, सब की डेट बतायी है । महोदय, एक-एक प्रश्न का उत्तर हमने स्पष्ट दिया है और मामला न्यायालय के अधीन है ।

(व्यवधान)

एक-एक प्रश्न का हमने उत्तर दिया है । नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिये कि उसके लीगल कांसेप्ट का जो न्यायालय में प्रक्रिया है, उसकी जवाबदेही हमने साफ लिखा है कि पी0आई0एल0 का मामला व्यवहार न्यायालय में चल रहा है, महोदय ।

अध्यक्षः ठीक है । अब आप एक लाईन में बोलिये नेता प्रतिपक्ष, एक लाईन में ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, हम एक लाईन में बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं । मंत्री जी के पास सातों का डिटेल नहीं है जो इन्होंने हस्तानांतरण किया है...

अध्यक्षः सातों की डिटेल चाहिये, यही न ? मंत्री जी, आप सातों की डिटेल नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध करा दीजियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः सातों की डिटेल हमने दी है । महोदय, प्रश्न में सातों की डिटेल दी है । महोदय, प्रश्न देख लिया जाय...

अध्यक्षः डिटेल की एक कॉपी उपलब्ध करा दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः सातों की डिटेल दी है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय...

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः सातों के डिटेल में लौरिया चीनी मिल...

अध्यक्षः बैठिये, आप खड़े क्यों हैं जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्रीः एच0पी0सी0एल0 को दिया गया है और हमने सातों का जवाब दिया है ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, यह सुशील मोदी जी का भाषण है, इस बजट भाषण में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ऐसे...

अध्यक्षः नहीं, अब दस मिनट पार कर गया । श्रीमती ज्योति देवी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः महोदय, पूरक है...

अध्यक्षः नहीं, अब आपका दस मिनट एक्स्ट्रा समय चला गया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः जवाब में एक ही चीज दुहरायी जा रही है...

अध्यक्षः अब उससे डिटेल में आपको अवगत करायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः समय से मतलब नहीं होना चाहिये महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्षः नियमावली के अनुसार सदन चलेगा न !

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दलः सप्लीमेन्ट्री पूछने का तो अधिकार है...

अध्यक्ष: नहीं, सप्लीमेन्ट्री समय-सीमा के अंदर ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, एक बार जब पिक कर लिया गया तो पिक कर लिया गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अच्छा सुन लीजिये एक मिनट । सब लोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्री जी बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी, पूरक प्रश्न जो नेता प्रतिपक्ष, उठा रहे हैं उसकी जांच करवा कर उत्तर सदन को भेज देंगे । अब तारांकित प्रश्न श्रीमती ज्योति देवी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: एक भी पूरक का...

अध्यक्ष: 10 मिनट एक्स्ट्रा तारांकित का समय चला गया । देखिये, अब तारांकित प्रश्न, माननीय सदस्य का है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, एक पूरक पूछें, उसका भी जवाब नहीं मिला दूसरा पूरक...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सदन के वरीय सदस्य हैं । श्रीमती ज्योति देवी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 1891(क्षेत्र संख्या-228, बाराचट्टी, अ0जा0)</u>

श्रीमती ज्योति देवी: जी, पूछती हूं ।

अध्यक्ष: मंत्री, गृह विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, पहले ये दूसरा पूरक...

अध्यक्ष: जवाब दे देंगे । फिर दुबारा कहेंगे, प्रश्न करेंगे, हमलोग उसको करवा देंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब देने में माहिर हैं । एक मिनट मंत्री जी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब पूरक नहीं, अब समय खत्म हुआ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, एक ही पूरक पूछे थे ।

अध्यक्ष: अब नहीं, 10 मिनट हम आगे बढ़ चुके हैं आपके लिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, नियम यह है कि अगर एक बार क्वेश्चन पकड़ा जाता है जब तक खत्म नहीं होता है तीन पूरक, तब तक वह चलता है ।

अध्यक्ष: नहीं, ऐसा नहीं है ।

(व्यवधान)

आपलोग बैठिये, सरावगी जी, आप बैठिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: इसमें हम बस एक और दूसरा पूरक, जवाब दे दें,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब आगे बढ़ चुके हैं, आगे मंत्री आकर ग्रहण कर लेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: एक मिनट अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष: ठीक है, बोल दीजिये ग्रहण कर लेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, फिर सवाल नहीं पूछेंगे तो इस प्रश्नकाल का क्या मतलब है । हमलोग सदन चलाना चाहते हैं...

अध्यक्ष: अच्छा ये बताइये एक ही प्रश्न में सदन का पूरा समय समाप्त कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

नहीं, जवाब दे दिये हैं, स्थगित का कोई औचित्य हो ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, औचित्य है जवाब ही नहीं आया ।

अध्यक्ष: आप तीन पूरक पूछ चुके हैं ।

(व्यवधान)

देखिये आपने सलाह दी, आसन कह रहा है कि स्थगित नहीं होगा । आपके पूरक का जवाब ये देंगे और सदन को अवगत करायेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष: नहीं अब नहीं, माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक तो पूछ लेने दीजिये, वह जवाब देते रहें या नहीं देते रहें, वह रिकॉर्ड में तो आ जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है, आप बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: बियाडा को जो जमीन दी गयी 20442.41 एकड़, हम जानना चाहते हैं कि कब दी गयी...

(व्यवधान)

पूछने दीजिये ।

अध्यक्ष: बैठ जाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: यह क्या मतलब है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: सदन नियमावली से चलेगा, बैठ जाइये आप सब लोग ।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: बियाडा को जो जमीन...

(व्यवधान)

कान में लगा लीजिये तब न सुनेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, संजय सरावगी जी । आसन का नियम सर्वोपरि है, बैठ जाइये आपलोग । यह गलत है, आप डायरेक्शन मत दीजिये, बैठिये । सब लोग बैठिये । डायरेक्शन कतई कोई नहीं दें, सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष । जब हमने अनुमति दी कि ये पूरक सुना दें और मंत्री जी ग्रहण कर लेंगे बात खत्म हो जायेगी । आप सुनाइये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, बियाडा को इन्होंने जमीन दी । जमीन जो है 20442.41 एकड़ जमीन दी गयी, हम जानना चाहते हैं कि जब भी बियाडा को कोई जमीन दी जाती है तो बाई लॉज कहलाता है, टाइम बाउंड के अंदर...

अध्यक्ष: पूरक पूछिये एक लाइन में ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: महोदय, बता रहे हैं टाइम बाउंड के अंदर उसका...

अध्यक्ष: अलग से बात कर लीजियेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: हम जानना चाहते हैं कि जो...

(व्यवधान)

आप भी गजब हैं । पता नहीं कैसे मंत्री आपलोगों को बना देते हैं ?

अध्यक्ष: कहां भटक गये आप ?

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: जवाब आता नहीं है...

अध्यक्ष: गृह विभाग बोलिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल: क्या मतलब है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

टर्न-4/सत्येन्द्र/15-03-21

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, ये गलत परम्परा शुरू कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष । कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, ये नेता प्रतिपक्ष के अधिकार में नहीं है । ये लगातार मंत्रियों के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं परसों से, ये गलत बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सभी लोग बैठ जायं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने दीजिये । ये लगातार परसों से हमारे मंत्रियों के बारे में लगातार टिप्पणी कर रहे हैं । ये गलत परम्परा की शुरुआत हो रही है सदन में, नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों का भी मान सम्मान है । हम सदन में जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री जी, बैठ जाइए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: हम सदन में अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जलील होने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परसों से चल रही है यह चीज । हमारे मंत्रियों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होगी ।

अध्यक्ष: बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: नहीं नहीं, ये गलत परम्परा है, हमारे मंत्रियों पर नकारात्मक टिप्पणी की जाती है, सदन इस तरह से कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाइए सब लोग ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ..

अध्यक्ष: बैठ जाइए । सब लोग व्यवस्था पर खड़े रहियेगा तो कैसे सुनेंगे ?

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: ये गलत परम्परा लागू की जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठ जाईए ।

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: मंत्रियों के बारे में वे नकारात्मक टिप्पणी परसों से ही कर रहे हैं। हम लोग बैठे नहीं रहेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: एक आदमी बोलेंगे । माननीय नंद किशोर यादव जी बोलेंगे, बाकी लोग बैठिये ।

श्री नंद किशोर यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही बार-बार कहते हैं कि सभी सदस्यों का मान बराबर है । किसी को सदन में किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है और महोदय, नेता प्रतिपक्ष इतने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, मंत्री खड़े होते हैं तो बैठते नहीं है, बार-बार उठ खड़े होते हैं और वे यह कहेंगे कि कैसा आदमी को मंत्री बना दिया, ये तो महोदय सदन का अपमान है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, हर हालत में उनको माफी मांगनी चाहिए । महोदय, आप जानते हैं, ये सदन में हमलोग पहली बार नहीं आये हैं, 26 साल से मैं भी सदस्य हूँ और वे भी सरकार में रहे हैं और सवालों के जवाब कैसे आते हैं मालूम नहीं है और जब आप खुद निर्देश दे रहे हैं, आपने खुद निर्णय दिया है कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है उसका जवाब मंत्री जी दे देंगे । आप सदन की कार्यवाही उठाकर देख लीजिये 26 साल की, इनके शासनकाल का भी देखिये कितनी बार यह कहा गया कि जवाब भेज दिया जायेगा, माना जाता है, क्यों नहीं मानते, उनकी मर्जी से चलेगा सदन, सदन किसी एक सदस्य की मर्जी से नहीं चल सकता है अध्यक्ष महोदय और सबका सम्मान बराबर है, चाहे वह मंत्री हों या नेता विरोधी दल हों या विरोधी दल के मेम्बर हों, कोई व्यक्ति हमारे मंत्रियों का अपमान करें, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, स्वीकर नहीं है । चलाना हो चलायें, न चलाना हो न चलायें लेकिन अपमान बर्दाश्त करके हम सदन नहीं चलने दे सकते हैं, महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपने जो कहा नियम के अनुकूल बात को रखा है और वरीय लोग से, पहले भी हमने कहा है आसन से कि सीखना चाहिए, समझना चाहिए, कोई मूर्धन्य नहीं है । नियम एवं नियमावली के अनुसार ही सदन चलेगा । प्रतिपक्ष भी सत्ताधारी दल के अंग होते हैं इसलिए आपको अवसर दिया लीक से हटकर, अल्पसूचित प्रश्न का समय समाप्त होने के बाद भी 10 मिनट तक पूरक पूछने का हमने अवसर दिया और माननीय मंत्री जी को निर्देशित भी किया कि पूरक प्रश्न की आप जांच करवा लेंगे । गलत जवाब कोई नहीं दे सके, इसकी आप समीक्षा कर लेंगे और मैं आगे से भी आग्रह करूंगा सभी सदस्यों से कि नियमावली का पालन करें, हम समय से बंधे हैं, कई सदस्यों का प्रश्न आया हुआ है, सबको अवसर मिलना चाहिए । ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पर सदस्य भागीदारी कर सकें इसलिए आगे से इसका ख्याल रखें और जो भी किसी के अधिकार क्षेत्र में हनन

करने का प्रयास करते हैं, वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनेगा और ये गलत परम्परा के बारे में कोई भी जिम्मेवारी के पद पर बैठे सदस्य खासकर सदन नेता, नेता प्रतिपक्ष, सत्तारूढ़ दल के सचतेक, उप सचेतक और विरोधी दल के उप सचेतक, दलीय नेता इसका जरूर ख्याल रखें । अब, श्रीमती ज्योति देवी ।

अध्यक्ष: मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: बोलें महोदय, चूंकि आपने एक बार बैठा दिया । विरोधी दल को बैठाते नहीं हैं आप, मंत्रियों को डांट देते हैं, चलिये ठीक है । जवाब तो दिया हुआ है, मांगा गया है एस0पी0 से..

अध्यक्ष: पूरक पूछियेगा या जवाब पढ़ दें ।

श्रीमती ज्योति देवी: महोदय जवाब नहीं है मेरे पास ।

अध्यक्ष: नहीं है, तो पढ़ दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि सहायक थाना, मोहनपुर का पैतृक थाना बाराचट्टी है । सहायक थाना, डोभी का पैतृक थाना शेरघाटी है एवं सहायक थाना, चेरकी का पैतृक थाना बोध गया है । गया जिले के तीन थानों का क्षेत्राधिकार निर्गत करने के संबंध में वांछित प्रतिवेदन की मांग पुलिस मुख्यालय ज्ञापांक 450 एल0-2 दिनांक 05-08-19 के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, गया से की गयी है एवं पत्रांक 34 दिनांक 28-01-21 तथा पत्रांक 73/एल-1, दिनांक 12-3-21 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को स्मारित किया गया है । वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1892(श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0-187, मनेर)

अध्यक्ष: श्री भाई वीरेन्द्र । नहीं हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1893(श्री सुरेन्द्र राम, क्षेत्र सं0-119,गरखा)

अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र राम । नहीं हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1894(श्री सिद्धार्थ पटेल, क्षेत्र सं0-125, वैशाली)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई गोरोल वर्ष 1994-95 से रुग्ण होकर बंद है। बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाइयों पर गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु निजी निवेशक को लीज पर चलाने के लिए वित्तीय सलाहकार SBI Caps के माध्यम से पांच निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं परन्तु गन्ना

आधारित उद्योग हेतु एक भी सफल निवेशक उपलब्ध नहीं हो पाये । वर्तमान में बिहार राज्य चीनी निगम के बंद पड़ी इकाइयों (फार्म लैंड सहित) जिसमें गोरोल चीनी मिल भी सम्मिलित है, को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार(BIADA) को Priority Sector की उद्योगों की स्थापना हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है । यदि किसी निवेशक से गोरौल चीनी मिल एवं ईथनॉल उद्योग चलाने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जायेगा ।

श्री सिद्धार्थ पटेल: उत्तर मुद्रित है, पूरक है मेरा ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री गन्ना उद्योग, पूरक सुन लीजिये ।

श्री सिद्धार्थ पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय केन्द्रीय मंत्री जी की घोषणा को दृष्टिगत रखकर सरकार स्वयं भी लोकहित में ईथनॉल संयंत्र स्थापित कर सकती है । यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार क्यों नहीं ईथनॉल संयंत्र लगाना चाह रही है ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, हमने स्पष्ट किया है कि ये 1994-95 का यह बंद चीनी मिल है, जो गोरोल चीनी मिल है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका ऑक्सन किया गया, इसके सलाहकार, वित्तीय सलाहकार के माध्यम से इसका सब उपबंध किया गया और उसके वाबजूद गोरौल चीनी मिल सम्मिलित था उसके लिए कोई वीटर नहीं आये तो यह प्रोपर्टी बियाडा को गया । अब हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्रीमान् शाहनवाज हुसैन साहब को धन्यवाद देंगे और अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिन्होंने 2007-08 में भारत सरकार को ईथनॉल के लिए लिखा था लेकिन उस समय भारत सरकार जो यू0पी0ए0 की सरकार थी, उसने ईथनॉल की परमिशन नहीं दी गयी, महोदय । अब धन्यवाद है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को जिन्होंने ईथनॉल की परमिशन दी और भारी संख्या में हमारे इन्वेस्टर आ रहे हैं और इसमें हमने लिखा है कि इस बियाडा के भूमि पर ईथनॉल उद्योग चलाने का हमलोग निवेशक को बुला रहे हैं और वहां एक ईथनॉल का उद्योग लगेगा, ऐसा हमने महोदय, स्पष्ट किया है और लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे सरकार के जो भी अधिकारी हैं, ईथनॉल नीति के तहत आगे बढ़े हैं और देश में 20 प्रतिशत ईथनॉल का उत्पादन करना है और महोदय, अभी 5 प्रतिशत हो रहा है और हमारा 5 ट्रिलियन डॉलर का...

अध्यक्ष: जितना पूरक पूछे हैं, जवाब भी उतना ही बड़ा है ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: महोदय, मुद्रा कोष बनाना है इसलिए ईथनॉल की दिशा में हमारी सरकार जो है बढ़ चुकी है और निश्चित तौर पर ईथनॉल का उद्योग लगेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1895 (श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-179, बाढ़)

अध्यक्ष: श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह । माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग । उत्तर संलग्न है।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह: नहीं मिला है ।

अध्यक्ष: नहीं मिला है, पढ़ दीजिये।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव लाने हेतु सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों के समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है ।(क्रमशः)

टर्न-5/मधुप/15.03.2021

...क्रमशः...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है लेकिन वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 407(4), दिनांक-25.10.2019 द्वारा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 31 मार्च, 2021 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश संसूचित है ।

पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अनुमंडल को जिला का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, 2005 में ही पब्लिक मीटिंग में मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट में बाढ़ को जिला बनाया जायेगा । बाढ़ सबसे ओल्डेस्ट सब-डिवीजन है अंग्रेज के जमाने का है, उसके बाद कई ब्लॉक जिला बन गये और कमिटी की बात तो पिछले टेन्योर में माननीय मंत्री जी ने कहा था, 8 साल पहले से कमिटी बनी हुई है, 8 साल पहले कमिटी उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी हुई है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : कह रहे हैं कि 8 साल पहले कमिटी बनाई गई, आज तक कुछ नहीं हुआ तो एक समयसीमा तय कर दें कि बाढ़ को जिला बनाने की योजना है कि नहीं, है तो कबतक ? एक टाइम निश्चित कर दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 31 मार्च तक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किसी तरह के किसी भी क्षेत्राधिकार में परिवर्तन को स्थगित करने का आदेश दिया । अप्रील में माननीय सदस्य चर्चा करेंगे तो देखा जायेगा ।

श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह : कहने का मतलब है कि अगले वित्तीय वर्ष में बन जायेगा जिला ? मैं जानना चाहता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ जिला बन जायेगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैंने यह नहीं कहा । अप्रील में उठायेंगे तो देखेंगे कि क्या किया जा सकता है । (व्यवधान) एक बार तो आप भी बाढ़ को जिला बनाने के आंदोलन के विरोध में थे ।

अभी कोई जिला बनाने का, अनुमंडल बनाने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1896 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-20, चिरैया)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया विधान सभा के पताही अंचल के मौजा पदुमकेर थाना नं0-186, खाता-80, खेसरा-1905, रकवा-2.84 एकड़ खतियान में गैर मजरूआ मालिक दर्ज है, जिसके अंश रकवा में लगभग 10 कब्र बने हुए हैं । उक्त भूमि कब्रिस्तान के रूप में घोषित नहीं है ।

वह कब्रिस्तान की भूमि है ही नहीं, गैर मजरूआ मालिक जमीन है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर कब्रिस्तान है, बार-बार वहाँ पर झंझट होता है। कृपा करके मंत्री जी उसकी घेराबंदी करवा दें ।

अध्यक्ष : आप मंत्री जी से मिलकर लिखकर दे दीजिएगा ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : कबतक हो जायेगा सर ? मंत्री जी कब करेंगे ?

अध्यक्ष : जब आपकी इच्छा हो, दे दीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1897 (श्री गुंजेश्वर साह, क्षेत्र सं0-77, महिषी)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सहारा इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार सुश्री नेहा कुमारी, श्री रवि कुमार पाण्डेय एवं श्री प्रेम चन्द्र राम के परिपक्वता राशि का भुगतान सहारा इंडिया द्वारा कर दिया गया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया पर प्रश्नचिन्ह इस क्वेश्चन के माध्यम से लगाया गया है कि अमुक-अमुक का उनका सर्टिफिकेट कम्पलीट होने पर उनका पैसा नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है । सहारा इंडिया कम्पनी पूरे बिहार में जो निवेशक हैं, मैं मान रहा हूँ अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : पूरक ही मैं पूछ रहा हूँ । सहारा इंडिया पूरे बिहार में हजारों लाभुकों को भुगतान नहीं कर रही है तो क्या सरकार देखवायेगी पूरे बिहार में सहारा इंडिया के मामले को ? यह मैं पूछना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री जी से ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा अगर किसी स्पेसिफिक का नाम बताया जायेगा तो उस संबंध में सरकार देखेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । आप मिलकर बता दीजिएगा ।

श्री संजय सरावगी : ठीक है, अध्यक्ष महोदय । विधान सभा में प्रश्न आ चुका है, बहुत गम्भीर मामला है सहारा इंडिया का । केवल पटना में ही नहीं, सभी सदस्य यहाँ पर हैं, कोई ऐसा जिला नहीं है, मेरे दरभंगा जिला में ही एक बार जाँच करा दें । सहारा इंडिया लाखों लोगों की राशि नहीं दे रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप नाम दीजिएगा, हम उसको देखवा लेंगे ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हजारों नाम हैं, एक-दो नाम नहीं हैं ।

अध्यक्ष : संभावित नाम आप बताइये, पार्टिकुलर कोई एक उदाहरण दीजिए ।

श्री संजय सरावगी : दरभंगा में सहारा इंडिया का दोनार ब्रांच है, उस दोनार ब्रांच का...

अध्यक्ष : आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिएगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार का मामला था । निवेशक का फायदा हो जाता, इसीलिए मैं पूरक प्रश्न कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतना समय देते हैं प्रश्न पर, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है । कह रहे हैं कि आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए । देखवा लेंगे । माननीय मंत्री जी, आप देख लीजिएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1898 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र सं0-165 : मुंगेर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत बरियारपुर प्रखण्ड में संचालित हरिणमार थाना के भवन निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि 6,52,06,600 (छः करोड़ बावन लाख छः हजार छः सौ रू0)मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-1897, दिनांक-01.03.2021 द्वारा प्रदान की गई है। थाना भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हम चाहेंगे कि बाढ़ से पहले सरकार से आदेश भवन बनने का मिल जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1899 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156 : भागलपुर)

अध्यक्ष : श्री अजीत शर्मा । श्री अजीत शर्मा । अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न सं0-1900 (श्रीमती रेखा देवी, क्षेत्र सं0-189 : मसौढ़ी(अ0जा0)

अध्यक्ष : श्रीमती रेखा देवी । श्रीमती रेखा देवी । अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न सं0-1901 (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र सं0-135 : मोरवा)

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू । श्री रणविजय साहू । अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न सं0-1902(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह,क्षेत्र सं0-221:नवीनगर)

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न सं0-1903 (श्री शमीम अहमद, क्षेत्र सं0-12 : नरकटिया)

अध्यक्ष : श्री शमीम अहमद । श्री शमीम अहमद । अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न सं0-1904(श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र सं0-62 : पूर्णियाँ)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि स्मैक आपूर्ति गैंग पर स्थायी रोक लगाने हेतु सीमावर्ती जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है । इस संबंध में पूर्णियाँ जिला में स्मैक/ब्राउन शुगर आपूर्ति करने वाले गैंग के विरूद्ध 06 कांड दर्ज करते हुए 30 ग्राम स्मैक, 1550 ग्राम ब्राउन सुगर, 3806 रूपये नगद, 08 मोबाईल, 03 वाहनों की बरामदगी तथा 22 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है ।

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार सिंह ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अब आगे बढ़ गये । अब बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1905 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-166 : जमालपुर)

अध्यक्ष : श्री अजय कुमार सिंह । नहीं हैं । अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1906 (श्री कुमार शैलेन्द्र, क्षेत्र सं0-152 : बिहपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि कोल्ड स्टोरेज स्थापित की जाती है तो सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में किये गये प्रावधान के तहत सहायता दी जाती है । अभी तक भागलपुर जिला से कोल्ड स्टोरेज स्थापना हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है । यदि कोई उद्यमी इसके लिये आवेदन करता है, तो उसे इस नीति के तहत प्रोत्साहित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक पूछिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट जवाब दिया है कि राज्य सरकार द्वारा कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । इन्होंने अपने जवाब में ही दिया है कि कोल्ड स्टोरेज को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र किसान का है । आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता बहुत ही...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : पूरक पर आ रहा हूँ महोदय, किसान का मामला है, सभी भाग गए हैं, अब तो थोड़ा हमलोगों को समय दीजिए ।

अध्यक्ष : सारा समय आप ही को दे दें ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : हम भाग्यशाली हैं कि हमारे नेता, हमारे मंत्री हैं, भागलपुर के हैं ।

अध्यक्ष : मिलकर क्यों नहीं बतिया लेते हैं ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : मैं अपने मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आप अपने प्रभाव से क्या वहाँ पर किसी बड़े उद्योगपति को बोलकर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपसे बहुत अपेक्षा रखते हैं, आपके क्षेत्र के हैं ये । बताइये ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब तो पूरा बिहार ही क्षेत्र है और यह सही है कि माननीय शैलेन्द्र जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैंने जवाब दिया है लेकिन अपेक्षा जो बिहार के लोगों की है या माननीय सदस्य की अपेक्षा है, उसको लेकर हमारी सरकार पूरी तरह गम्भीर है और हर जिला में उद्योग लगे, इसके लिए इसपर काम शुरू है। ...क्रमशः...

टर्न-6/आजाद/15.03.2021

.... क्रमशः .....

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : और खास तौर पर जो पूरा इलाका बिहपुर से लेकर कोसी के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में उत्पादन होता है । वहां पर कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की जो बात है, सरकार उसको नहीं करती है लेकिन उसके लिए प्रोत्साहन नीति बनी हुई है, जिसके बारे में मैंने जवाब दिया है । लेकिन मक्का से और केला से बहुत ज्यादा है, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने, वहां कोल्ड स्टोरेज बने और वहां के मक्का से इथनॉल बने इसके लिए बहुत सी कम्पनी ने आवेदन दिया है । मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गन्ना विभाग की जो ढ़ाई हजार एकड़ जमीन थी, वह बीयाडा को उद्योग विभाग को ट्रांसफर हुई है और जहां-जहां गन्ना से, मक्का से, चावल की टुकड़ी से इससे हम इथनॉल बनाने पर बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । जल्द ही इसके लिए नई इथनॉल पॉलिसी बनेगी, बिहार पहला राज्य बनेगा जो देश में इथनॉल की पॉलिसी बनायेगा और हर जिले के अन्दर जो किसान हैं, उनको बहुत लाभ होने वाला है और इसके लिए हम जल्दी केबिनेट में जब जायेंगे तो इसकी सूचना हम यहां पर देंगे ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मेरा पूरक का जवाब नहीं मिला ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, डायरेक्ट बता दीजिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मेरा पूरक स्पष्ट है कि अपने प्रभाव से कोल्ड स्टोरेज के लिए किसी उद्योगपति को लाकर कोल्ड स्टोरेज लगवाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : मंत्री तो आपके जिले से ही हैं तो बैठकर, मिलकर बात कर लीजियेगा, प्राथमिकता तो देंगे ही ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि मैंने उद्योग मंत्री बनने के बाद हमारी जो नीति है, उसके तहत जहां भी नया एलाईनमेंट हो रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, जो एन0एच0 आ रहा है, उसके बगल में हम औद्योगिक क्षेत्र

डेवलप करना चाहते हैं । बिहार में टीम हमने पहली बार बिहपुर भेजी क्योंकि बिहपुर से वीरपुर जो सड़क है और एन0एच0 31 के बगल में आद्योगिक क्षेत्र बनाया जाय और वहां पर इथनॉल की भी फैक्ट्री लगे, वहां पर कोल्डस्टोरेज भी बने, मैं उस क्षेत्र से प्रतिनिधि रहा हूँ तो जितनी माननीय सदस्य की चिन्ता है, उससे मैं सहमत होते हुए जरूर वहां उद्योग का जाल उस इलाके, कोसी इलाके में, नवगछिया, बिहपुर और पूरे कोसी इलाके में, पूरे बिहार में बढ़े, कोशिश करेंगे ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री, उद्योग अब केवल भागलपुर के मंत्री नहीं हैं, बिहार के मंत्री हैं । इसलिए आप जरूर चिन्ता कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप पूरे बिहार की चिन्ता करिए और कर भी रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य श्री नन्दकिशोर जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे पहले उद्योग से जुड़े हुए लोगों की बैठक मैंने खुद माननीय नन्दकिशोर जी के घर पर जाकर पटना सिटी के लोगों की भी चिन्ता की है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1907(श्री जय प्रकाश यादव, क्षेत्र सं0-46 नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है ।

निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो सरकार द्वारा प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है, अतएव निजी उद्यमियों को आगे आने की आवश्यकता है । साथ ही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन कर इथनॉल को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में रखा गया है । जिसके तहत इथनॉल उत्पादन की अधिक से अधिक इकाइयां स्थापित होने की संभावना है ।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत अब तक खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में कुल 169 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया जा चुका है । जिसमें से 134 इकाइयां कार्यरत हो चुकी हैं । अररिया जिला में प्रारंभ से अब तक खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में कुल 05 प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति) तथा एक इकाई के प्रस्ताव पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है । वर्तमान में एक इकाई मेसर्स महरबा फोजेन, सिमराहा, फारबिसगंज, अररिया में कार्यरत हो चुकी है ।

जहां तक मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग की स्थापना का प्रश्न है तो उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोतसाहन नीति, 2016 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो उल्लिखित नीति के प्रावधान के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है । साथ ही कृषि विभाग के द्वारा भी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 पूरे राज्य में लागू की गई है, जिसके तहत कृषि आधारित कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना/विस्तारिकरण/आधुनिकीकरण/विविधिकरण की पचीस लाख से पॉंच करोड़ तक की परियोजना के लिए व्यक्तिगत निवेशक के लिए 15 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान, Farmer Producer Company के लिए 25 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, उत्तर अंकित है । हमारा भी प्रश्न मक्का आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने से संबंधित है और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि हम निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था किये हैं तो क्या मैं यह जानना चाहता हूँ कि विशेष पैकेज पर निवेशक कब तक आकर्षित होंगे और कब तक उद्योग हमारे क्षेत्र में लग पायेगा चूँकि पूरा क्षेत्र हमारा मक्का आधारित ही है मंत्री जी ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जवाब इसमें बहुत विस्तार से दिया है, जो ऑनलाइन उनके पास पहुँचा है । जवाब वही है ....

अध्यक्ष : संक्षिप्त में बता दीजिए कब तक ?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : मक्का आधारित उद्योग के लिए फारबिसगंज में पहले से उस इलाके में एक फैक्ट्री की शुरूआत हुई थी जो किन्हीं कारणों से बहुत धीमी गति से काम चल रहा है । मैंने बुलाकर उसके बारे में भी बातचीत की थी और उस पूरे इलाके में मक्का बहुत ज्यादा होता है तो हमारा इरादा है अध्यक्ष महोदय कि हर जिले में जहां किसान मक्का या चावल या गन्ना उपजाते हैं, उस जिले में इथनॉल बेस्ड इन्डस्ट्रीज लगे, हम बिहार को इथनॉल का हब बनायेंगे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो देश के अन्दर तेल खरीदने में डॉलर लगता है, वह बचेगा । 6 प्रतिशत ही अभी हम इथनॉल मिलाते हैं जबकि अमेरिका में 20 फीसदी और ब्राजील में 40 फीसदी इथनॉल मिलाया जाता है । इसलिए बिहार के पास यह बहुत बड़ी ऑपरच्यूनिटी है । जिस तरह से हमारे पास आज खनिज नहीं है लेकिन हमारे किसान गन्ना, मक्का और चावल पैदा करके उसको खनिज की तरह बिहार में योगदान दे रहे हैं तो बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है । जल्द ही आने वाले समय में ....

अध्यक्ष : जल्द ही माननीय सदस्य ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : उद्योग लगाने के लिए आयेंगे और उस इलाके में जरूर इथनॉल की फैक्ट्री लगेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब जल्द ही बोल दिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न और है ......

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामप्रवेश राय । माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

(व्यवधान)

अब आगे बढ़ गये, आप मिल लीजियेगा मंत्री जी से ।

तारांकित प्रश्न सं0-1908 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र सं0-100, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2020 में राज्य में आयी बाढ़ से गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा एवं बरौली प्रखंड में क्रमश: 981.53 एवं 717.95 यानि कुल 1699.48 लाख हे0 गन्ने के फसल की क्षति हुई है । फसल क्षति के आकलन से संबंधित समेकित प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक-996 दिनांक 16.09.2020 के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । उक्त पत्र के आलोक में विभाग को अद्यतन कोई स्वीकृति/राशि प्राप्त नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामप्रवेश राय जी, पूरक पूछिए ।

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि फसल क्षति के आकलन से संबंधित समेकित प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक-996 दिनांक 16.09.2020 के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । उस पत्र के आलोक में विभाग को अद्यतन कोई स्वीकृति राशि प्राप्त नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, 16.09.2020 को ही आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध करा दिया है, लेकिन 4-5 महीने हो गये, आपदा प्रबंधन विभाग ने इसपर क्या किया है, कोई मुआवजा देने का एलान किया है, आदेश दिया है या नहीं दिया है, इसको माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, यह आपदा प्रबंधन विभाग का प्रश्न है फिर भी हमारा जो दायित्व था, उससे हमने आपदा प्रबंधन विभाग को अवगत करा दिया । अब उनका नीतिगत मामला है तो माननीय सदस्य इसके संबंध में अगर आपदा प्रबंधन विभाग से पूछेंगे तो वे इसके बारे में समुचित उत्तर देंगे ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, इसको ट्रांसफर कर दिया जाय ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, इसको ट्रांसफर कर दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपदा प्रबंधन विभाग को स्थानान्तरित किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1909 (श्री फते बहादुर सिंह, क्षेत्र सं0-212, डिहरी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1910 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1911 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र सं0-100, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली को अनुमंडल बनाने से संबंधित औपचारिक घोषणा की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

राज्य में जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/अंचल के पुनर्गठन हेतु ''मंत्रियों के समूह'' का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु ''सचिवों की समिति'' गठित है । सचिवों की समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाईयां के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से ''सचिवों की समिति'' के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-407(4), दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों की सीमाओं में 31 मार्च, 2021 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश संसूचित है ।

बरौली को अनुमंडल का दर्जा देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक पूछिए ।

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर के आलोक में यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जब भी कहीं प्रखंड/अंचल/अनुमंडल/जिला नया बनाने की बात होती है तो इनका एक ही जवाब होता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो मंत्रियों का समूह बनाया है और उसके आलोक में सचिवों की जो समिति बनायी है, यह कब बनायी गयी है और इसकी कभी बैठक इस राज्य में हुई है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कब बनायी है यह तो बहुत पहले से बना हुआ है । अगर आप इसके लिए अलग से प्रश्न करेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स दे देंगे । लेकिन ......

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, इनका ......

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं, माननीय मंत्री खड़े हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 31 मार्च, 2021 तक राजस्व विभाग ने चूँकि जमीन का सर्वे वगैरह का काम चल रहा है, 31 मार्च, 2021 तक कोई भी जिला, प्रखंड, अनुमंडल बनाने पर रोक उन्होंने लगायी है । इसीलिए बैठक होगी भी मंत्री समूह की तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा । सुनिए पूरी बात, 31 मार्च, 2021 तक कोई नया गठन नहीं होगा ।

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं हुआ । मंत्रियों के समूह की बैठक आखिर कब हुई है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बहुत ही स्पष्ट ढंग से जवाब दिये ।

श्री रामप्रवेश राय : यह जवाब नहीं हुआ सर ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में इन्होंने बैठक की चर्चा की है ।

श्री रामप्रवेश राय : अगली बैठक कब होगी ?

अध्यक्ष : बता देंगे, आपलोग मिलकर एक बार, वरीय मंत्री हैं, मिलकर जानकारी ले लेंगे ।

श्री रामप्रवेश राय : ठीक है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

माननीय सदस्यगण, आज 7 विभागों के प्रश्न आये हैं । गृह विभाग का 98 प्रतिशत जवाब आया है, सामान्य प्रशासन विभाग का 100 प्रतिशत जवाब आया है, वित्त विभाग का 100 प्रतिशत जवाब आया है, उद्योग विभाग का 100 प्रतिशत, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का 100 प्रतिशत, गन्ना उद्योग विभाग का 100 प्रतिशत और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का 100 प्रतिशत, सभी प्रश्नों के जवाब 98 प्रतिशत आज आये हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 मार्च, 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री अरूण सिंह, श्री अजय कुमार, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अमरजीत कुशवाहा एवं श्री मनोज मंजिल ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

टर्न-7/शंभु/15.03.21

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर आ गये)

श्री महबूब आलम : महोदय, मजदूरों की मौत हो रही है......

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, वहां आत्महत्या किया है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको बोलने के लिए कह रहे हैं ? जाइये अपनी सीट पर । श्री महबूब आलम । अरे, आप कहां उनको डिस्टर्ब करने लगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, महबूब जी सदन के भी महबूब हैं इसलिए उनपर ध्यान दिया जाय ।

श्री महबूब आलम : महोदय, विगत दिनों सुपौल में एक ही परिवार के पांच लोगों की सामूहिक आत्महत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है । इस घटना के पीछे मूलत: आर्थिक तंगी और कर्ज की बातें उभरकर सामने आयी हैं । यह बात भी सामने आ रही है कि बेटी की शादी के बाद पूरे परिवार को समाज से काट दिया गया था और वह परिवार कई सालों से सामाजिक बहिष्कार झेल रहा था । वे लोग विगत दो वर्षों से अपनी जमीन व घर बेचकर किसी तरह अपना जीवन चला रहे थे । अंतत: जमीन भी खत्म हो गयी और मजबूरन उन लोगों ने आत्महत्या कर ली । यह एक दर्दनाक घटना सभ्य समाज में कलंकित करनेवाली है ।

अध्यक्ष : महबूब आलम जी, साथ में 11 शब्द में आज आपने इतिहास रचा है, तो 11 शब्द वाला भी बोल दीजिए ।

(व्यवधान)

आप उनके क्यों बाधक हैं ? आपके नेता बोल रहे हैं, यह कतई अच्छी बात नहीं है सत्यदेव जी कि आपके नेता बोल रहे हैं और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं । यह सदन में उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, वे सामाजिक बहिष्कार झेल रहे थे आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हो गये । इसके पहले खगड़िया में भी प्रशासनिक लापरवाही के कारण आठ मजदूरों की मौत हुई, आखिर कितनी मौत के बाद सरकार की नींद खुलेगी । वैसे ही महोदय गया के 11 मजदूरों की आगरा में दुर्घटना में मौत हो गयी ।

अध्यक्ष : आप शून्यकाल वाला भी पढ़िये न । आप पहले शून्यकाल वाला पढ़िये । आप अच्छी चीज लिखे हैं, पढ़िये ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री महबूब आलम : महोदय, बिहार में पंचायतों के सरपंच सचिवों का न्यूनतम मानदेय 21 हजार रूपये करने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए बाद में उठाइयेगा । पढ़िये मुकेश जी ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पंचायत शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु शिक्षा विभाग द्वारा संचिका सं0-1247, दिनांक 22.09.2020 को समिति का गठन किया गया जिन्हें एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देना था, परन्तु 6 माह बीत जाने के बाद भी कोई पहल नहीं हुआ । जनहित में पंचायत शिक्षकों के स्थानान्तरण की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अरे बैठिए आप । आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी, पहले आप बैठ जाइये । महत्वपूर्ण बात है, आपसे पहले पांच लोगों की मृत्यु की सूचना दी है, सुनिए ।

(व्यवधान)

अब ऐसे करके सुनाइयेगा तो सरकार नहीं सुन पायेगी ।

माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पांच लोगों की मौत की बात आयी है इसको संज्ञान में ले लें ।

(व्यवधान)

उन्होंने संज्ञान में ले लिया और सर हिला भी दिये । अब आसन से आदेश हो गया ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, दिनांक 13.03.2021 को सीतामढ़ी जिले में हुई ओला वृष्टि से हजारों किसानों की फसल नष्ट हो गयी है । सरकार त्वरित गति से जॉच कराकर मुआवजा भुगतान करे । अविलम्ब जॉच से किसान वाजिब क्षति की प्राप्ति से वंचित नहीं रहे सकें ।

श्री ललन कुमार : महोदय, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र इशीपुर, पीरपैंती जिला भागलपुर को उत्क्रमित कर सरकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की मांग करता हूॅं ।

अध्यक्ष : 18 शब्द में है ललन जी धन्यवाद ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के सनोखर पंचायत के जफरा गांव जो विकास से अछूता आदिवासी बहुल गांव है, जिसका सनोखर से कोई पक्की सड़क संपर्क नहीं है । अतः सरकार से उक्त गांव को पक्की सड़क से जोड़ते हुए समुचित विकास की मांग करता हूॅं ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, जहानाबाद को एन0एच0-110 रोड से अलगना मिश्रा विगहा होते हुए सैदाबाद तक जानेवाली सड़क केन्द्रीय विद्यालय ऐनवां तक बिलकुल जर्जर है । सरकार से मांग है कि मुख्य सड़क से केन्द्रीय विद्यालय तक सड़क निर्माण कराया जाय ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, बिक्रमगंज नगर परिषद् अन्तर्गत शहरी आवास योजना स्वीकृत होने के बावजूद अगर पत्नी के नाम जमीन है तो पति के नाम पर अथवा सिकमी जमीन पर एल0पी0सी0 नहीं बन रहा है । मैं सरकार से मांग करता हूॅं कि उक्त जमीनों का एल0पी0सी0 बनाकर आवास बनाया जाय ।

श्री जयप्रकाश यादव : महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अन्तर्गत रामघाट कोशकापुर पंचायत स्थित झरकाहा चौहान टोला से लसका टोला मेन रोड तक पक्की सड़क की मांग सरकार के माध्यम से करता हूॅं ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, पूर्णियां जिला में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लक्ष्य काफी कम है, जबकि मार्च, 21 तक आवास निर्माण कर गृह प्रवेश करने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित है । अतः मैं सरकार से पूर्णिया जिला में आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करने हेतु मिशन गृह प्रवेश की तिथि विस्तार करने की मांग करता हूॅं ।

अध्यक्ष : चलिये पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

डा0 ललित नारायण मंडल : महोदय, भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन अत्यन्त जर्जर स्थिति में है । इसका यथाशीघ्र नवनिर्माण कराया जाय ।

अध्यक्ष : धन्यवाद 20 शब्द में है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, होली एवं शब-ए-बरात पर्व आसन्न है लेकिन बिहार में शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को जनवरी 2021 के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है । होली एवं शब-ए-बरात पूर्व राज्य के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को जनवरी एवं फरवरी का वेतन अविलम्ब दिया जाय ।

श्रीमती शलिनी मिश्रा : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया विधान सभा क्षेत्र के केसरिया स्तूप में खनन का कार्य वर्षों से चल रहा है, परंतु अभी तक पूरा नहीं हुआ है । अतः इस खनन कार्य को शीघ्र पूरा कराने की मांग करती हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत फुटकर विक्रेताओं को 10,000/-रू0 की राशि ऋण दिये जाने हेतु 420 स्वीकृत आवेदनों में से मात्र 157 को ऋण दिया गया है और 263 लंबित हैं । अतः शेष बचे 263 आवेदकों को अविलम्ब ऋण दिये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत सहार थाना क्षेत्र के गांव नाढी में 27 अगस्त, 2018 को रामाकांत राम की हत्या कर दी गयी थी । अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है । नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग सदन के सामने रखता हूँ ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बेगुसराय जिला के रजिस्ट्री औफिस में वर्ष 1902 से बेगुसराय जिला बनने के पूर्व तक का जमीन निंबधन से संबंधित कागजात जिला मुख्यालय में उपलब्ध नहीं होने से जिलावासियों को काफी कठिनाई होती है । अतः सरकार से मुख्यालय में जमीन निबंधन कागजात उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ ।

टन-8/ज्योति/15-03-2021

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत के पुरानी जोगबनी को जोगबनी से जोड़ने वाली किसलय नदी पर बने पुल एवं मीरगंज के पास अंग्रेज जमाने के बने लोहे के पुल की स्थति बेहद जर्जर एवं खराब है उक्त दोनों स्थानों पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला के इस्लामपुर में जानवरों में खुरहा रोग के प्रकोप से पशुपालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है । इस रोग के प्रकोप से जानवरों ने खाना पीना बंद कर दिया है तथा दुधारू पशु दुध देना भी बंद कर दिए हैं । अतः मैं इस सदन के माध्यम से इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री अरुण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, नगर पंचायत जयनगर के एनर.एच. 105 से एनर.एच. 227 तक आनंदपुर मोहल्ला होकर गुजरने वाली सड़क जर्जर है शीघ्र सड़क निर्माण की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 21 शब्द ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर के नरहन पुल से गंडक बांध पर स्थित पक्की सड़क जो पंचायत नरहन विभूतिपूर, खरियाही भोसवर, पतेलिया, साखमोहन, देसरी के लाखों की आबादी को जोड़ती है कि स्थिति काफी जर्जर है । मैं सरकार से उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूँ ।

श्री आनंद शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपीलीय प्राधिकार, औरंगाबाद द्वारा बारुन प्रखंड अंतर्गत बलराम सिंह, केस नं0 54/2014 वगैरह, कार्यरत 12 शिक्षकों का नियमित वेतनादि भुगतान का पारित आदेश दिनॉंक 07-11-2014 के अनुपालन हो जाने के बाद भी फरवरी, 2020 तक वेतन भुगतान नहीं किया गया अतः आग्रह है कि उक्त शिक्षकों का वेतन आदि का भुगतान शीघ्र कराया जाय ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण कोरोना काल के पश्चात दिसम्बर, 2020 में पुनः चालू हुआ लेकिन नामांकन बंद होने से युवा प्रशिक्षण से वंचित हैं मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कुशल युवा कार्यक्रम को प्रशिक्षण हेतु नया सत्र शुरु कर नामांकन प्रारम्भ किया जाय ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों की और अन्य जरुरी सेवाओं की घोर कमी है साथ ही वहॉं के उपाधीक्षक, पी.एच.सी. प्रभारी और एकाउंटेंट की कार्यशाली में व्याप्त लापरवाही, मनमानी, अनियमितता और दुर्व्यवहार से आम जनता त्रस्त है । उच्च स्तरीय जॉंच कराने की कार्रवाई की जाय ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत राज्य सरकार की प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम बनाने की योजना के तहत जिरादेई प्रखंड के ग्राम- भैंसाखाल स्थित 84 बीघा सरकारी जमीन पर खेल प्रेमियों के हित में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद स्टेडियम बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत सिवान-सिसवन रेल फाटक बंद हो जाने के कारण घंटो घंटो जाम लग जाता है । सिवान से सिसवन पथ निर्माण विभाग की सड़क है । सिसवन रेल ढाला पर रेल ओवर ब्रिज पथ निर्माण विभाग से बनाने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गुरारू रेलवे स्टेशन के दक्षिण में बन रहे रेलवे गुमटी पर फ्लाईओवर विगत 3 वर्षों से अर्द्धनिर्मित हालत में है जिससे रेलवे लाइन पार करने में हमेशा जाम की स्थति और समय की बर्बादी होती है । अतः इसे जल्द से जल्द पूर्ण करवाने की मांग करता हूँ ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य में जीविका के कैडर का मानदेय 750 से 3500 तक है । इसे बढ़ा कर 5000 से 10,000 किया जाय एवं जीविका समूहों कके साथ बैंक लिंकेज 50 हजार है इसे 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ाने की माुंग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यपालक सहायकों के निमित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को लागू करने, नियमित करने, महिला सहायकों को विशेष अवकाश देने, 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय में वृद्धि, सरकारी सेवकों जैसे भत्ता दिया जाए एवं बिहार प्रशसनिक सुधार मिशन सोसाईटी के दिनॉक 05.02.21 के कार्यावली 6,7,8,9 को निरस्त किया जाय ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रफीगंज के पंचायत पोगर के ग्राम कजरा से पोगर तक पथ निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत मौजा जमालकिला में भू-स्वामियों को निमार्णाधीन राष्ट्रीय मार्ग 333(बी.) के लिए अधिगृहित की गई भूमि का मुआवजा सर्किल रेट 15 लाख रुपया प्रति कट्ठा के हिसाब से नहीं दे कर मात्र 15000 रुपये का ही मुआवजा का भुगतान कर भू-स्वामियों को उचित मुआवजा से वंचित किया जा रहा है । अतएव, उक्त भूमि का नियमानुसार मुआवजा भू-स्वामियों को सरकार द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार दिलाया जाय ।

श्रीमती मंजू अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, शेरघटी विधान सभा के अंतर्गत आमस प्रखंड के पंचायत बड़कील चिलिमी के बिशुनपुर टोला मठ पर एवं राम पुर पंचायत के गंगाबिगहा ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई पूरी तरह बाधित है। अतः उक्त स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय का अतिशीघ्र निर्माण किया जाय ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिले के ताजपुर, पूसा एवं मोरवा प्रखंण्ड जो कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की कर्म भूमि रही है, मैं मांग करता हूँ कि तीनों प्रखंडों को मिलाकर ताजपुर अनुमंडल बनाया जाय ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों की सेवा सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग संवर्ग में शामिल करते हुए उनके नियमितीकरण की मांग करता हूँ ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत माँ मुंडेश्वरी धाम परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु प्रसाद बिक्री करने वाले दुकानदारों के लिए स्थाई व्यवस्था न होने से दुकानदार यत्र-तत्र दुकान लगाने को मजबूर हैं । सरकार पर्यटन विभाग/जिला प्रशासन द्वारा स्थाई बंदोवबस्ती के आधार पर दुकान का निर्माण करावे ।

श्री कृष्ण कुमार मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड जहानाबाद ग्राम-धुरुविगहा के लोगों को आजादी के 72 वर्षों बाद भी बरसात के दिनरों में नदी को नाव से पार कर आना जाना पड़ता है । पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, खरीक प्रखंड के ढोढिया दादपुर में एन.एच. 31 से सिंहकुण्ड पैकेज नं. बी0आर0 06R095 सड़क संवेदक की लापरवाही से आम जनमानस को काफी कठिनाई हो रही है । 2010 से ही कई संवेदक बदले गए हैं । डी.पी.आर. रिवाईज्ड कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के बिहटा-विहिया स्टेट हाईवे पर 13 मार्च को बाजार टोला में ढाहे गए 30 गरीबों के घरो का सरकार मुआवजा दे ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 18 शब्द है ।

श्री मुहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 52 बहादुरगंज अंतर्गत महेशबथना वार्ड नं. 4 में कनकई नदी घार मात्र 20 मीटर दूर है । यदि समय रहते कटावरोधक कार्य नहीं किया गया तो सरकार भवन के साथ हजारों परिवार का अस्तित्व मिट जाएगा । मैं सरकार से समय रहते कारगर कदम उठाने की मांग करता हूँ ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर नगर निगम स्थित राजा बाजार-सब्जी मंडी जो जर्जर अवस्था में है । उसे तोड़कर महुमंजिला नया मार्केट बनाने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती वीणा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के महनार नगर परिषद् के फतेहपुर में नहर के ऊपर बांस के पुल होने की वजह से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है तथा वार्ड-06, 08, 19, 20, 21, 27 के लोगों की खेती प्रभावित होती है अतः सरकार वहाँ पक्का पुल का निर्माण करावे ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, बिहार पुलिस सिपाही संवर्ग की मुख्यालय के 20 कि.मी. दूरी पर रहने के पश्चात यात्रा भत्ता देय है । किसी प्रतिष्ठान-थाना या माननीय के यहाँ प्रतिनियुक्त रहने पर सिर्फ 6 माह ही यात्रा भत्ता देय होगा उसके बाद भत्ता देय नहीं है, सभी को यात्रा भत्ता दिया जाय ।

टर्न-9/अभिनीत-पुलकित/15.03.2021

अध्यक्ष: अब शून्यकाल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । श्री कुमार शैलेन्द्र अपनी सूचना पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री कुमार शैलेन्द्र, अरूण शंकर प्रसाद एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (श्रम संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: माननीय अध्यक्ष महोदय, ''श्रम संसाधन विभाग के बजट में से अधिकांश राशि बिहार कौशल विकास मिशन में खर्च होती है । वर्ष 2016 से युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु नॉलेज पार्टनर के रूप में एम0के0सी0एल0 का चयन किया गया, जिसे प्रशिक्षणोपरांत युवाओं को रोजगार की जानकारी के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का प्रावधान भी करना था लेकिन तीन वर्ष तक इसका प्रावधान नहीं कर करोड़ों रुपये प्राप्त किये गये और जनवरी, 2020 में पोर्टल खोला गया । इसके द्वारा लगातार असत्य सूचना देकर विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशियों का गबन किया जा रहा है और 5 वर्षों में मात्र 10 से 20 प्रतिशत छात्रों को ही प्रशिक्षित किया गया है, जबकि के0वाई0पी0 सेंटर को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर पूर्ण भुगतान किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, सरकारी आदेश के बावजूद प्लेसमेंट पार्टल के लिए गलत ढंग से प्राप्त राशि की वसूली आज तक एम0के0सी0एल0 से नहीं की गई है । बिहार में कौशल युवा कार्यक्रम सफेद हाथी साबित हुआ है ।

अत: एम0के0सी0एल0 द्वारा गलत तरीके से बिना कार्य किये ही प्राप्त किये गए भुगतान की वसूली करने, उसे काली सूची में डालने तथा इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमको समय चाहिए ।

अध्यक्ष: मंत्री जी, कब तक समय चाहिए, क्योंकि यह गंभीर मामला है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, जब अगली श्रम संसाधन....

अध्यक्ष: नहीं, नेक्स्ट डे । कल ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, एक दिन और दे दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है, फिर परसों ।

माननीय सदस्य, आज मंत्री जी ने समय लिया है, इसलिए आप परसों पूछियेगा । अब माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री अजय कुमार, अजीत शर्मा एवं अन्य छह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (श्रम संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, ''गया जिला से नौकरी की तलाश में सिरसा, हरियाणा जाने के क्रम में आगरा के समीप सड़क दुर्घटना में सात मजदूरों की मौत हो गयी और तीन घायल हैं । सभी दलित एवं अनुसूचित जाति के हैं । हर साल मजदूरों को पलायन बढ़ता जा रहा है और इस तरह की दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं, किन्तु सरकार पलायन रोकने हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है ।

अत: जनहित में पलायन रोकने, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी तथा मुआवजा दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, गया जिला से सिरसा, हरियाणा जाने के क्रम में आगरा के समीप सड़क दुर्घटना में सात मजदूरों की मृत्यु एवं तीन श्रमिकों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है । राज्य सरकार शोक-संतप्त परिवारों के प्रति पूरी संवेदना रखती है तथा यथासंभव सहयोग पहुंचाने हेतु कृत-संकल्पित है । प्रत्येक मृत श्रमिकों के वैध आश्रितों को तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुदान स्वरूप एक लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, गया के माध्यम से आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिया गया है और आज उनके एकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है । इसके अतिरिक्त बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 के अंतर्गत अर्हता प्राप्त दो मृतक श्रमिकों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपया अतिरिक्त अनुदान की राशि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । शेष पांच मृतक की उम्र 18 वर्ष से कम रहने के कारण योजना से आच्छादित नहीं हैं । मृतक श्रमिकों के पार्थिव शरीरों को जिला पदाधिकारी, आगरा के सहयोग से जिला पदाधिकारी, गया द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से वापस राज्य लाया जा चुका है तथा घायल श्रमिकों का इलाज आगरा, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है । श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार उपलबध कराने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है । राज्य सरकार का प्रयास है कि रोजगार के अभाव में श्रमिकों का पलायन न हो, इस हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं परंतु ऐसा पाया जाता है कि कई बार बेहतर अवसर की तलाश में श्रमिक अन्य राज्यों में भी जाते

हैं । राज्य सरकार युवाओं/श्रमिकों का कौशल संवर्धन कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने हेतु कृत संकल्पित है ताकि उन्हें बेहतर से बेहतर अवसर प्राप्त हो सके ।

श्री अजय कुमारः महोदय, यह आम आपदा के तहत नहीं आता है । इसको उसमें नहीं लेना चाहिये, चूंकि सरकार अगर रोजगार देती तो पलायन नहीं होता । सरकार ने रोजगार नहीं दिया, इसलिए पलायन हुआ । हम सदन से मांग करते हैं कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी सरकार दे, सरकारी नौकरी देने का विचार सरकार रखती है या नहीं ? यह हम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्रीः महोदय, इस मामले में श्रम संसाधन विभाग का जो नीतिगत फैसला है और जो गाईड लाइन है, उसमें नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री महबूब आलमः महोदय, मजदूरों की मौत का मजाक उड़ाया जा रहा है ।

अध्यक्षः महबूब जी, आप बैठिए । महबूब जी, आप वरीय सदस्य हैं, अभी माननीय सदस्य का पूरक खत्म नहीं हुआ है, आप क्यों उठ गये ।

श्री अजय कुमारः महोदय, मेरी सरकार से इससे जुड़ी हुई मांग है कि आमतौर पर जो घटनाएं घटती हैं इसको उसमें न लेकर एक स्पेशल ढंग से देखने का विचार सरकार को रखना चाहिए और मैं मांग करता हूं कि कम से कम पीड़ित परिवार को और कुछ नहीं तो 10 लाख रुपये का मुआवजा सरकार दे । यह हम सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री । एक मिनट, महबूब जी आपका इसमें साईन नहीं है, इसलिए आप नहीं उठिये ।

श्री महबूब आलमः महोदय, लगातार मौतें हो रही हैं ।

अध्यक्षः आप बैठ जाइये, और लोग हैं न । उनके बगल में हैं, उनसे पूछिए ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य का कोई पूरक नहीं है, अगर उनकी यह मांग है तो इस पर सरकार विचार करेगी ।

अध्यक्षः ठीक है, गंभीरता से विचार कीजिए ।

(व्यवधान)

सत्यदेव जी, आपका साईन नहीं है इसलिए आप बैठ जाइये, आपकी कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । सत्यदेव जी गलत परंपरा नहीं लाइये, आप बैठ जाइये । डॉ0 सत्येंद्र यादव का पूरक है, इन्हें पूछने दीजिए ।

(व्यवधान)

आप बैठिए, सत्येंद्र यादव आप पूछें ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से पूरक प्रश्न है कि मजदूरों के परिजनों को नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती ? क्या नियम में संशोधन नहीं हो सकता है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, सत्यदेव बाबू...

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तरीके से प्रश्न कीजिएगा तो सरकार जवाब देगी ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, सत्यदेव बाबू ने इतना शोर किया कि आधा पूरक तो मैं सुन ही नहीं पाया ।

अध्यक्ष: बोलिए, गड़बड़ी तो कर दिए आप ।

एक मिनट, सत्येंद्र यादव जी एक बार फिर से पूरक पूछिए । अब बैठिये, कोई भी माननीय सदस्य बीच में न उठें, इनके पूरक को आप फिर से गड़बड़ा देंगे ।

डॉ0 सत्येंद्र यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि नियमावली में नौकरी का प्रोविजन नहीं है । महोदय, सड़क दुर्घटना में जो मौतें हुई हैं, ये सामान्य मौत नहीं हैं । लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं और सामूहिक तौर पर यह दुर्घटना हुई है । महोदय, सामूहिक तौर पर इस दुर्घटना को मानते हुए सरकार नियम में संशोधन कर उनके परिजनों को नौकरी क्यों नहीं दे सकती है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, मैंने यह पहले ही कहा कि यह इनका सुझाव है कोई पूरक नहीं है, सरकार इस पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष: सरकार विचार करेगी ।

श्री रणविजय साहू: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आपका हस्ताक्षर है, इस सूचना में ?

श्री रणविजय साहू: जी, अध्यक्ष महोदय, आखिर पलायन कब तक रुकेगा ? केंद्र में और राज्य में आपकी लगातार सरकार है । आपको....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री रणविजय साहू: महोदय, पलायन कब तक रुकेगा यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, पलायन रोकने की दिशा में बिहार सरकार गंभीर है । इसी को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट में ही यह निर्णय लिया गया कि आगामी पांच वर्षों में हमलोग 20 लाख रोजगार सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में खड़ा करेंगे ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पलायन शब्द का बड़ा विस्तृत अर्थ है । आप किसी को बाहर जाने से रोक सकते हैं ?

माननीय सदस्य, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री रणविजय साहू: महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि बड़े पैमाने पर हमारे बिहार के श्रमिक भाई नौकरी की तलाश में दूसरे स्टेट में जाते हैं, आखिर पलायन कब रुकेगा ? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों....

अध्यक्ष: रोजगार कब मिलेगा यही पूछ रहे हैं न ? यह पूछिए कि रोजगार के लिए क्या-क्या कर रहे हैं ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, पहले ही मंत्रिपरिषद की बैठक में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले पांच वर्षों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार मुहैया करायेंगे ।

अध्यक्ष: 20 लाख रोजगार मुहैया करायेंगे ।

(व्यवधान)

बैठिए, फिर आप उठ रहे हैं । धैर्य से सुनिये, मंत्री जी बोल रहे हैं । थोड़ी सी आदत सुधारनी पड़ेगी, मंत्री बोल रहे हैं तो सुनिये, फिर आपके विषय को भी मंत्री सुनेंगे ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, यह निर्णय सरकार ने लिया है और अध्यक्ष महोदय, यह पूछना कि पलायन कब तक रुकेगा, यह तो एक आदर्श बात है । पलायन तो कई कारणों से होता है। रोजगार हमने मुहैया कराया है, इस कोरोना काल में भी हमने 69 हजार से अधिक बिहार के अंदर रोजगार मुहैया कराया है । माननीय सदस्य को..

अध्यक्ष: बेहतर ऑप्शन के लिए भी पलायन होता है ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: निश्चित, महोदय, मैंने जवाब में भी दिया है कि कई बार अच्छे अवसर के लिए भी लोग पलायन करते हैं । एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, अच्छे अवसर के लिए भी जाते हैं, तो यह तो एक आदर्श बात हो जायेगी ।

अध्यक्ष: अब माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, विस्तृत विमर्श की जरूरत है । आप बैठ जाइये, सुन लीजिये ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

श्री दामोदर रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये । अवसर अभी आपके पास मौजूद है, प्रश्न डाल सकते हैं, रोजगार पर सरकार सजग है, सदन गंभीर है ।

श्री दामोदर रावत: राजकीय आश्वासन समिति का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 292वाँ प्रतिवेदन, गृह विभाग से संबधित 294वाँ एवं 296वाँ प्रतिवेदन तथा नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित 295वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/हेमन्त-धिरेन्द्र/15.03.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, भवन निर्माण विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	-	56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	55 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	-	03 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	-	01 मिनट
सी0पी0आई0	-	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	01 मिनट

माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

''भवन निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 53,21,40,63,000/-(तिरपन अरब इक्कीस करोड़ चालीस लाख तिरसठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अखतरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिस पर सभी माननीय सदस्य

विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का प्रस्ताव प्रथम है अतएव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:-

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : चार मिनट आपका समय है, इसको कन्क्लूड कर लेना है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, नहीं । बोलने वाले हम दो ही सदस्य हैं । इसीलिए 50-50 है । महोदय, भवन निर्माण विभाग द्वारा जो मांग आज सदन में प्रस्तुत की गयी है और भवन निर्माण विभाग...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको चार मिनट और उनको दस मिनट समय दिया गया है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, वह तो हम लोग समझ लेंगे ।

अध्यक्ष : लिखकर दिया गया है ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, भवन निर्माण विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और परिवहन विभाग की मांग को आप देखेंगे, तो प्रत्येक वर्ष की भांति इनकी मांग सदन में आयी है, सदन के समक्ष आयी है । मांग लेकर भवन निर्माण विभाग के मंत्री जी आये हैं । कुछ इसमें नयापन नहीं है और राज्य के भवन निर्माण के अधीन आने वाले पुराने भवन और माननीय मंत्री जरा....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय शंकर दूबे : तो मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय, महोदय । आसन से निवेदन करना चाहता हूं, यह इसलिए कि भवन निर्माण विभाग, राज्य के पुराने भवन चाहे ब्लॉक हों, थाने हों, अनुमंडल हों, जिले हों उसकी रिपेयरिंग कराने में, नये निर्माण की तो बात ही अलग है, रिपेयरिंग कराने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा है । फिर यह पैसा देने का कोई औचित्य नहीं दिखता है । माननीय मंत्री जी नये विभाग को देख रहे हैं, अपेक्षा थी कि माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी कुछ नये तरीके इजाद करके और राज्य के भवनों को, स्वास्थ्य उपकेंद्रों को, अस्पतालों को, थानों को, ब्लॉक को, अंचल को, थोड़ा रंग-रोगन कराते । लेकिन वैसा दिखता नहीं है, महोदय और नये निर्माण जो हो रहे हैं, मंत्री जी जब बोलेंगे तो बतायें कि जितने प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, जितनी राशि की स्वीकृति हुई है, जो समय कर्णांकित है, उसको पूरा करने का, वह सारी चीजें उस अवधि के अंदर पूरी होती हैं ? महोदय, नहीं होती हैं । इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार पुराने भवनों की मरम्मति

कराये, थाने ठीक से संचालित नहीं हो रहे हैं, थानेदार को रहने की जगह नहीं है, हथियार सुरक्षित नहीं हैं और पूरे राज्य में अग्निशामक यंत्र...

अध्यक्ष : इनका पांच मिनट समय और बढ़ाया जाय ?

श्री विजय शंकर दूबे : जी । महोदय, अग्निशामक यंत्र राज्यभर में....

अध्यक्ष : तो आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : खुले मैदान में, पूरे राज्य में, जहां देखेंगे, ब्लॉक में अग्निशामक यंत्र गाड़ियां....

अध्यक्ष : अब समाप्त कर दीजिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : पड़ी हुई हैं । महोदय, मैं मांग करता हूँ कि उसके रख-रखाव और भवन निर्माण की व्यवस्था की जाय । महोदय, पहले ही लाल बत्ती जला दीजियेगा, तो कैसे काम चलेगा ।

अध्यक्ष : हम तो कह रहे हैं कि अगर आप बोलेंगे तो फिर हम आपके दल से समय काटेंगे ।

श्री विजय शंकर दूबे : हमारे दल के समय में से काट लिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, बोलिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि महाराजगंज....

अध्यक्ष : आपके सामने कह रहे हैं कि समय काट लिया जाय ।

श्री विजय शंकर दूबे : सीवान के अन्य ब्लॉकों का, इंटायर 15-16 ब्लॉक हैं । सभी ब्लॉकों की स्थिति जर्जर है, थानों की स्थिति जर्जर है, इसीलिए माननीय मंत्री जी महाराजगंज ब्लॉक .

अध्यक्ष : दस मिनट ।

श्री विजय शंकर दूबे : और भगवानपुर ब्लॉक के थाने और ब्लॉक की मरम्मति माननीय मंत्री इस साल जरूर करवा दें । थाने और ब्लॉक की स्थिति अत्यंत जर्जर है, पुलिस के रहने की व्यवस्था नहीं है, हथियार सुरक्षित नहीं हैं, महोदय । इसीलिए इन दोनों थानों को मैं, वह हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और इसी प्रकार महोदय, अन्य जो विभाग हैं गिलोटिन में, समाज कल्याण विभाग पर भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक बच्चों के पढ़ाई केन्द्रों पर जो भोजन का प्रबंध किया गया है, वहां मानक के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं मिलता है...

अध्यक्ष : अब चार मिनट उनके लिये रहने दीजिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि इस ओर सरकार, समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जी ध्यान रखेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ और सदन से दरख्वास्त करता हूँ कि इस हुकूमत को, इस विभाग को इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री राजवंशी महतो । आपका दस मिनट समय है ।

श्री राजवंशी महतो : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2021-22 में समाज कल्याण विभाग के प्रस्तावित बजट प्राक्कलन की कुल राशि 81,59,14,76,000/- (ईक्यासी अरब उनसठ करोड़ चौदह लाख छिहत्तर हजार) रुपये के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आसन को धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ, साथ ही साथ विधान सभा क्षेत्र संख्या-141, चेरिया बरियारपुर की आम आवाम को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया श्री लालू प्रसाद यादव जी एवं श्रीमती राबड़ी देवी जी को शत्-शत् नमन करता हूँ, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने, गरीब-गुरबों को जागृत करने तथा अधिकारों के प्रति सजग रहने का उपदेश दिया साथ ही साथ विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि गरीब लोगों की आवाज को विधान सभा और सड़क पर भी जोरदार शब्दों में उठाने का काम करते हैं । इसलिए वह धन्यवाद के पात्र हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-11/सुरज-संगीता/15.03.2021

...क्रमशः...

श्री राजवंशी महतो : महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा पूरक पोषाहार योजना के अंतर्गत सभी कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं को एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार वर्ष 2019-20 1828.11 करोड़ उद्व्यय के विरूद्ध 1194.60 करोड़ व्यय होने का उल्लेख विगत बजट में किया गया था परंतु सच्चाई कुछ और बयां करती है । सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 60.3 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया (खून की कमी) की शिकार हैं, वहीं 63.57 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं फिर भी सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है । यह राशि कहां जाती है, यह सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है । प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना के तहत गर्भवतीधात्री महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषाहार में सुधार लाना एवं गर्भावस्था के समय मजदूरी घाटा की क्षतिपूर्ति हेतु पांच हजार रुपये तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान है परंतु जिनके लिए यह योजना लायी गई है उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं होती है तो इसका लाभ, निर्धन गरीब, बेसहारा महिलाओं को कैसे मिलेगा ? यह योजना सिर्फ कागज पर ही बनती है, धरातल से कोसों दूर है । मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इस योजना का कार्यान्वयन विगत पांच वर्षों से बंद है अर्थात कहने का आशय यह है कि इस योजना का लाभ जब मिल ही नहीं रहा है तो वर्ष 2019-20

में 33 सौ करोड़, वर्ष 2020-21 में 52 सौ करोड़ रुपये का व्यय होना तथ्य से परे है । मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, यह योजना लगभग वर्ष 2014 से ही बंद है या मृतप्राय है तब भी वर्ष 2019-20 में 20 करोड़ 17 लाख वर्ष 2020-21 में 5 करोड़ 25 लाख करोड़ रुपये व्यय दिखाया गया है । इस योजना में भी घोटाला होने की बू आती है इसकी जांच कराने की विशेष आवश्यकता है । परिवार तथा अभिभावक विहीन बच्चों को प्रोत्साहन राशि, महोदय आप अवगत हैं कि निराश्रित, लावारिस, बेसहारा बच्चों को गोद लेने या सरकार पर्यवेक्षण विशेष गृह या कई गैर सरकारी संस्थायें आश्रयगृह में रखे जाते हैं तथा कई गोद लेते हैं तो एक हजार प्रतिमाह अनुदान भत्ता का भुगतान किसको हो रहा है ? यह योजना भी कागजी खानापूर्ति की भेंट चढ़ जाती है, यह भी जांच का विषय है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राज्य भर में साक्षरता दर बहुत ही अल्प है अर्थात अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है । वृद्धजन पेंशन योजना का वोटर आई०डी० कार्ड लगभग 30 से 40 वर्ष पुराना होता है जिसमें उम्र लगभग 60 साल नहीं होती है जिसमें बहुत संख्या में वृद्ध लोग योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं । उम्र के संबंध में जांच कराने के तरीके को विकसित करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें । पूरक पोषाहार योजना 6 माह से 6 वर्ष की आयु के सभी सामान्य व कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों को पोषाहार के लिए 1 करोड़ 14 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किए गये हैं । इन केन्द्रों के बच्चों के फर्जी आंकड़ों का खेल चल रहा है । इन केन्द्रों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण नहीं रहने से यह योजना धरातल से बहुत दूर है । बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला परियोजना पदाधिकारी सब मिलकर कमीशन का खेल खेलते हैं । यहां हमेशा निरीक्षण, पर्यवेक्षण होता तो समुचित बच्चों के कुपोषण में कमी आती तथा योजना सफलीभूत होती । बिहार समेकित सामाजिक सुदृढ़ीकरण योजना, इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए संचालित 101 बुनियादी केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा 87 भवन भी निर्मित हो गये हैं परन्तु बुनियादी केन्द्रों के संचालन हेतु जो मानव बल होना चाहिए उसका इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है तथा जो मानव बल कार्यरत हैं उनके वेतन मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है एवं उनकी छटनी करने की तलवार उनपर लटक रही है । सरकार को बुनियादी केन्द्रों को सशक्त बनाने तथा उसमें रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है तथा जो कार्यरत बल हैं, उसमें जीविकोपार्जन के लिए निर्धारित वेतनमान देय का भुगतान होना चाहिए ।

महोदय, कहने के लिए बहुत बातें हैं । इस विभाग में जो भी योजना चल रही है, उसमें बहुत बड़ा छिद्र है, उसमें जितना भी पानी डालिये वह छोटे-छोटे छिद्रों से बाहर

निकल जाता है । उस छिद्र को ढकने या बंद करने के लिए ताकत चाहिए जिसका अभाव है । मैं पुन: आसन को धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देता हूं । जय हिन्द, जय बिहार ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री मिथिलेश कुमार ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के भवन निर्माण के संबंध में मुझे पक्ष में बोलना है । अध्यक्ष जी, विश्व की विशिष्टतम धरती सीता प्रकट स्थली से, वहां की जनता के आर्शीवाद से, आपके सहयोग से बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं । मिथिला की धरती से आए हैं, वहां की जनता के भी आभारी हैं और फिर मिथिला की धरती से आए हैं तो रामायण की वह पंक्ति याद आती है जैसे ऊर्जा पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया था- ''मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी'' । अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष : मैथिली में बोलिएगा क्या ?

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष जी, यह बजका है लेकिन रामायण की पंक्ति है । अध्यक्ष जी, भवन निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने वर्ष 2005 से आज तक जो अपना पैमाना स्थापित किया, वह पूरे विकसित देशों के पैरामीटर से आगे है । अध्यक्ष जी, बिहार में कई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हैं, कितने प्रखंड स्तर के आई0टी0आई0 सेंटर खोले गए । अध्यक्ष जी, एक प्रखंड का मात्र अगर हम आंकड़ा लें तो अभी वर्तमान में अद्यतन बिहार के 101 प्रखंडों में आई0टी0 सेंटर का निर्माण हो रहा है । आरा में 2 आई0टी0 सेंटर का निर्माण, बांका में 5 का, भभुआ में 3 का, सीतामढ़ी में 2 का, भागलपुर में 3 का, गया में 4 का, जमुई में 4 का, खगड़िया में 4 का, मुंगेर में 3 का, नालंदा में 3 का, नवादा में 1 का, सासाराम में 1 का, शेखपुरा में 2 का, दरभंगा में 4 का, हाजीपुर में 3 का, कटिहार में 5 का, किशनगंज में 3 का, मधुबनी में 1 का, मोतिहारी में 9 का, मुजफ्फरपुर में 1 का, सहरसा में 3 का, शिवहर में 2 का, सीवान में 1 का, अररिया में 1 का ये अद्यतन अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं । अध्यक्ष जी, चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना बनायी है उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में वर्ष 2011, 2012 में एप्रूवल हमको 79.87 करोड़ का मिला था और ...क्रमश:...

टर्न-12/मुकुल-राहुल/15.03.2021

क्रमश:

श्री मिथिलेश कुमार: उसमें हमने जीरो करोड़ एक्सपेंस किया और वर्ष 2012-13 में हमको 61.95 करोड़ का एप्रूवल का मिला था जिसमें हमने 0.23 करोड़ एक्सपेंस किया । वर्ष 2013-14 में 261.18 करोड़ का एप्रूवल मिला था जिसमें हम लोगों ने 47.09 करोड़ एक्सपेंस किया । वर्ष 2014-15 में 992.51 करोड़ एप्रूवल मिला था जिसमें हमने 100.24 करोड़ उपयोग किया । वर्ष 2015-16 में 304.81 करोड़ एप्रूवल मिला था, यह आंकड़ा में इसलिए दे रहा हूं कि यह आंकड़ा तुलनात्मक ढंग से जो लोग देखना चाहते हैं, तुलना करें कि आप इससे पूर्व में कितना उपयोगिता किये हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में उपयोगिता की क्या प्रतिशत बढ़ी है । हमको मालूम है हम जो बोल रहे हैं उसमें एप्रूवल और एक्सपेंस है, ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है, यह संज्ञान में लेकर बोल रहे हैं, तुलनात्मक ढंग से आप सभी लोगों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विकास का आईना दिखाने के लिए और वर्ष 2020-21 में, मैं क्रमश: बोल रहा था, लेकिन अब सीधा सुनना चाहते हैं वर्तमान परिदृश्य तो वर्ष 2020-21 में 783.66 करोड़ का एप्रूवल मिला था और हमने 850 करोड़ का उपयोग किया ।

(व्यवधान)

बिल्कुल कर रहे हैं वह अंडर कंस्ट्रक्शन है । जिले में, सैंक्शन आ रहा है..

अध्यक्ष: आप पढ़ते रहिये, इधर-उधर नहीं भटकिये । आप बोलते रहें ।

श्री मिथिलेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, पॉलिटेक्निक संस्थान के संदर्भ में मधेपुरा, मुंगेर, समस्तीपुर, शेखपुरा, नवादा, अररिया, सीवान, बक्सर, औरंगाबाद और किशनगंज इन 10 जिलों में हमारा पॉलिटेक्निक संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण है । खगड़िया, पश्चिम चम्पारण और भोजपुर इन तीन जिलों में प्रगति पर है । अरवल में पुनर्निविदा की प्रक्रिया में है, जहानाबाद में एक है और नया स्थल स्थानांतरण के संबंध में चर्चा हो रही है । अध्यक्ष जी, बिहार के अभियंत्रण महाविद्यालयों में बख्तियारपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, जमुई, बांका, कैमूर, बेगूसराय, गोपालगंज और अररिया इन 13 जिलों में पूर्ण है और शेखपुरा, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, मुंगेर, लखीसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, शिवहर, किशनगंज, जहानाबाद, अरवल, आरा, सीवान और नवादा में 16 योजना प्रगति पर है । अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का यह आईना है । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आईना सभी क्षेत्रों के विकास का एक अलग पैरामीटर खड़ा करता है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार के अधिकतम जिलों में मैटरनिटी सेंटर का नया भवन निर्माण कराया है, डायलिसिस सेंटर की स्थापना कई जिलों में हो चुकी है और कई जिलों में कार्य प्रगति पर है । सिटी-स्कैन सेंटर का भवन निर्माण भी हमने बिहार के लगभग आधे जिलों में करवा दिया है । शिक्षा के क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना है वह बेमिसाल है वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक का हो, आई0टी0आई0 का हो, मेडिकल कॉलेज का हो सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना भवन निर्माण के माध्यम से हुई है वह बेमिसाल है । सीतामढ़ी जिले में राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय का वर्तमान माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय जी के द्वारा शुरुआत करवाया गया । सदन के माध्यम से सीतामढ़ी की जनता की ओर से उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं । सभापति जी, प्रशासन के क्षेत्र में जिन-जिन जिलों में समाहरणालय भवन का निर्माण नहीं हुआ था वहां समाहरणालय भवन का निर्माण इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में पूरा कर लिया गया है । सभापति जी, विद्युत भवन में जहां-जहां विद्युत भवन के प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण नहीं हुआ था, लगभग 90 परसेंट जिलों में पूरा कर लिया गया है । सभापति जी, प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में लगभग 85 परसेंट भवन का निर्माण करवा दिया गया है । सभापति जी, अनुमंडल स्तर के कार्यालय बिहार के जिन-जिन अनुमंडलों में नहीं था लगभग 90 प्रतिशत अनुमंडलों में हम लोगों ने अनुमंडल कार्यालयों का भवन निर्माण करवा दिया है । सभापति जी...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री मिथिलेश कुमार: सभापति जी, खेल का स्टेडियम भी बिहार के कई जिलों में बनाया गया है, हमारे सीतामढ़ी जिला में जीता-जागता उदाहरण है । सभापति जी, पर्यटन के क्षेत्र में, कई जगह वैशाली में, गया में, सीतामढ़ी में, सीता पर्यटन स्थल विद्यापति के यहां पर कुछ-कुछ पर्यटन का काम सभी जगहों पर जारी है और आगे भी पर्यटन के क्षेत्र में भवन निर्माण विभाग गंभीर संज्ञान लेने वाली है । सभापति जी, भवन निर्माण विभाग के वर्ष 2021 के बजट में उपबंध की कर्णांकित राशि 610 करोड़ है । सभापति जी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कई बड़ी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है...

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार): कृपया सुनिए, बैठ जाइए ।

श्री मिथिलेश कुमारः जिसमें कुछ की विवरणी मैं निम्न प्रकार देना चाहता हूं । सभापति जी, सात निश्चय के अन्तर्गत 317.95 करोड़ की लागत से अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर, सुपौल, जमुई जिसका मैंने वर्णन किया, कार्य पूर्ण किया गया है । सात निश्चय के अन्तर्गत 72.70 करोड़ की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया एवं सिवान का कार्य पूर्ण हो गया है । सभापति जी, 73.92 करोड़ की लागत से महिला आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया...

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आप बैठिए न, आपको भी बोलने का समय दिया जाएगा ।

श्री मिथिलेश कुमारः सभापति जी, यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के महिला सशक्तिकरण अभियान का नायाब और अनूठा उदाहरण है कि हमने महिला आई0टी0आई0 कॉलेज का भी कार्य आरम्भ करवाया है और कार्य पूर्ण किया है । सभापति जी, 61 करोड़ की लागत से पटना में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है । सभापति जी, 59.98 करोड़ की लागत से पी0एम0सी0एच0 में आई0जी0आई0एम0एस0 के भवन का निर्माण कराया गया है, जो अब तक बिहार के लिए अवर्णनीय है । सभापति जी, 633 करोड़ की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी का निर्माण कराया गया है । सभापति जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार से पहले बिहार में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम होगा, ये किसी की परिकल्पना में था क्या ? किसी की परिकल्पना में नहीं था । सभापति जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने यह परिकल्पना की, इसको धरातल पर उतारा कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम किए जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई निर्माण किए जाएंगे...

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आप बैठिए, आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी । अभी आप बैठिए।

श्री मिथिलेश कुमारः सभापति जी, 145 करोड़ की लागत से बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कार्य हुआ । सभापति जी, बोधिष्ठ लोग विश्व के सभी देशों से आते हैं, जापान से आते हैं, चीन से आते हैं, बैंकॉक से आते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का मान बढ़ रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में । सभापति जी, 301.4 करोड़ की लागत से वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण कार्य चल रहा है । सभापति जी, 397 करोड़ की लागत से पटना में ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सांइस सिटी का निर्माण कराया जा रहा है । ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन थे उनको बिहार ने सम्मान दिया । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने

हिंदु-मुस्लिम सिक्ख इसाई,
सब आपस में भाई-भाई ।

कैप्टेन हमीद का वंशज और असफाक उल्लाह का वशंज ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भी बनाया और ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के सम्मान की दृष्टि से बिहार में उनके नाम पर सांइस टैक्नोलॉजी संस्थान का निर्माण भी करवा रही है । यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का आईना है । सभापति जी, 37.61 करोड़ की लागत से बिहार लोक सेवा आयोग के नए भवन का निर्माण कार्य अन्तिम चरण मे है जो आने वाले 4 महीनों में पूर्ण हो जाएगा । सभापति जी, 169.50 करोड़ की लागत से पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है...

(व्यवधान)

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आप बैठिए, आपको बोलने के लिए समय दिया जाएगा ।

श्री मिथिलेश कुमार: सभापति जी, 41.191 करोड़ की लागत से बेतिया में एवं 41.223 करोड़ की लागत से मोतिहारी में 2 हजार क्षमता के प्रेक्षागृह का निर्माण हो रहा है । सभापति जी, 164 करोड़ की लागत से दरभंगा में तारामंडल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । जब बिहार, उड़ीसा, बंगाल एक राज्य था उस समय मात्र कलकत्ता में तारामंडल हुआ करता था । आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने बिहार के दरभंगा जैसे जिलों में तारामंडल के निर्माण की योजना बनाई है यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नायाब, बेनजीर, बेमिसाल उदाहरण है । सभापति जी, 32.98 करोड़ की लागत से सिंचाई भवन और 61.62 करोड़ की लागत से पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन एवं 61.46 करोड़ की लागत से विकास भवन के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

क्रमशः

टर्न-13/यानपति-अंजली/15.03.2021

...क्रमशः...

श्री मिथिलेश कुमार: सभापति जी, 84.49 करोड़ रुपये की लागत से पटना में बापू टावर कार्य प्रगति पर है । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने एक तरफ जहां गुजरात में सरदार बल्लभ भाई पटेल को विश्व स्तर के मानदंड में उनकी मूर्ति को खड़ा कर रही है । वहीं बिहार में बापू टावर का कार्य कर रही है । यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान है । सभापति जी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में सात निश्चय

के तहत बख्तियारपुर, सुपौल, जमुई एवं बांका जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया । राज्य के 24 जिलों में लगभग 9 करोड़ प्रति इकाई की लागत से 101 प्रखंडों में काम हो रहे हैं । राज्य के 10 जिलों में जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है जिसकी प्रति इकाई 1.15 करोड़ रुपये है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): अब आपका समय मात्र दो मिनट रहा है । कन्क्लूड करें ।

श्री मिथिलेश कुमार: सभापति जी, भवन निर्माण, भवन निर्माण जो संपूर्ण आधारभूत संरचनाओं की मातृ व्यवस्था है उस भवन निर्माण में 2005 तक का जो पैरामीटर था, उस 2005 से 2020 के काल खंड का जो पैरामीटर रहा, वह पैरामीटर विश्व के पैमाने पर भारत को विकसित राज्य स्थापित करने में सहायक और मील का पत्थर साबित होगा । यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार भवन निर्माण के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में भारत को विश्व के मानक पर विश्वगुरु के रूप में स्थापित कर के दम लेगा, यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का वायदा है । यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने जो चुनौती है उसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पूरे विश्व में स्थापित करके पूरे भारत को एक नायाब, बेमिसाल, बेनजीर उदाहरण पेश किया है । सभापति जी...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आपका समय मात्र 19 सेकेंड है ।

श्री मिथिलेश कुमार: सभापति जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भवन, ऊर्जा तमाम क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार विश्व के मानदंड पर फिर से भारत को सोने की चिड़िया और विश्वगुरु के रूप...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): कृपया आप बैठ जायं, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मिथिलेश कुमार: में स्थापित करेगा । जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): क्या कहना चाहते हैं बोलिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन: महोदय, बार-बार अध्यक्ष महोदय का नाम लिया जा रहा है जबकि सभापति महोदय बैठे हुये हैं । बीसों बार नाम लिया गया है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): जी बिल्कुल, इसमें सुधार कर लिया जायेगा । बैठिये । अब माननीय सदस्य, श्री राकेश कुमार रौशन जी । आपका समय 15 मिनट है ।

श्री राकेश कुमार रौशन: सभापति महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आपने हमें बोलने का समय दिया और साथ ही साथ अपने क्षेत्र की महान जनता को जो नालंदा जिला के इस्लामपुर विधान सभा क्षेत्र की महान जनता है, जिन्होंने वहां से दूसरी पीढ़ी के रूप में हमको इस सदन में भेजने का काम किया इसके

लिए हम उस महान क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहां तक पहुंचाने में हमें सहयोग किया, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं । महोदय, मैं भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो अनुदान मांग पेश हुआ है उसके कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, कहा जाता है कि 'कंस्ट्रक्शन इज द पीलर ऑफ द सोसायटी' निर्माण जो है समाज का स्तम्भ है और सरकार ने भी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट भाषण लिखित रूप से हमलोगों को प्रस्तुत किया है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विगत 15 वर्षों में भवन निर्माण विभाग ने भवनों के निर्माण में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही दृष्टि से उपलब्धियां हासिल की हैं । विभाग ने राज्य में जमीनी स्तर से लेकर वृहत परियोजनाओं मेगा प्रोजेक्ट्स का निष्पादन किया है और उत्तरोत्तर नवीन निर्माण कार्य कर रहा है । ये माननीय मंत्री जी इस बात को विशेष रूप से अपने भाषण में चर्चा किये हैं महोदय लेकिन जब जमीनी सच्चाई को महोदय देखा जायेगा तो बिहार के अंदर जो भवन निर्माण विभाग के तहत भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का सर्वथा अभाव है, महोदय और इस गुणवत्ता का जो अभाव है उसके लिए वर्तमान सरकार ही दोषी है । वर्तमान सरकार ने पहले यह तय किया था कि जिस विभाग में जो निविदा होती है उस निविदा में 10 प्रतिशत बिलों तक कोई भी संवेदक टेंडर डालकर अपना काम कर सकते हैं वह मान्य होगा । लेकिन अभी महोदय, इसी विभाग के प्रधान सचिव की एक चिट्ठी निकली है जिसमें कहा गया है कि किसी भी विभाग में काम करने के लिये कोई भी संवेदक जितने निचले स्तर पर जा सकते हैं वहां जितने बिलों में टेंडर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं । महोदय, चिट्ठी है हमारे पास उसके जो कंटेंट्स हैं, मैं वह पढ़कर आपको बता देना चाहता हूं । यह नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का । हुजूर, इसमें है कि Provision has been made vide R.C.D. Letter No.- So & So Dated- 06-03-2014 that the minimum rate in all type of tender invited on percentage rate system shall be limited to ten percent below the bill of quantity B.O.Q. Tenders have been more than ten percent below B.O.Q. rates shall be considered eligible. यह पहले व्यवस्था थी हुजूर कि यदि 10 परसेंट से ज्यादा होगा तो इस दस परसेंट के बाद उसका टेंडर मान्य नहीं होगा लेकिन अभी क्या व्यवस्था है । चीफ सेक्रेटरी की यह चिट्ठी है इसमें लिखा

हुआ है कि In this context during a meeting of all works department held under chairmanship of chief secretary of government of Bihar. It is filled that the minimum rate barrier be removed with immediate effect and after one year the pros and cons of the decision will be reviewed. मतलब अब जो है सरकार ने यह व्यवस्था कर दी कि कोई भी संवेदक जितना बिलो है उतना बिलो जाकर के टेंडर डाल सकता है और टेंडर उसका मान्य होगा । कहने का मतलब है कि इस्टीमेट बनाने की जो प्रक्रिया है जो बिल ऑफ क्वांटिटी बनाया जाता है जो उसका स्टैंडर रेट है मैटेरियल का, उसके आधार पर स्टैंडर रेट के आधार पर इस्टीमेट का निर्माण होता है और उसके बाद कोई संवेदक यदि 60 परसेंट बिलो जाकर के कोई काम लेता है किसी विभाग में, इसका मतलब है कि वह गुणवत्ता से समझौता करता है और वह घटिया मैटेरियल डालकर विभाग का निर्माण कराता है और यह सरकार इस संस्कृति को बढ़ावा देती है और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने इसको ही इस्टीमेट घोटाला कहकर सरकार को घेरने का काम किया था कि ये इस्टीमेट बनाकर के सरकार जो है गरीबों के पैसों का सरकार दुरुपयोग कर रही है और सही मायनों में उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है महोदय । आज हमारे अभी सत्तापक्ष के एक साथी बोल रहे थे सरकार की बड़ी-बड़ी उपलब्धियां गिना रहे थे । महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि अभी महोदय इसी विधान सभा का विस्तारित भवन बना है, जो एक्स्टेंशन हॉल है उसकी क्या स्थिति है, आप खुद देख सकते हैं उसके इंटीरियर की क्या स्थिति है, वहां पर बैठने की क्या व्यवस्था है, उसकी गुणवत्ता की क्या स्थिति है । खुद आप मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी समय वह भवन गिर सकता है ऐसी स्थिति है इस विधान सभा के विस्तारित भवन की । इसके अलावा महोदय हम विधायकों के आवास के निर्माण की प्रक्रिया तीन साल से चल रही है महोदय । हमलोग लगातार अखबारों में दूसरे माध्यमों से सुनते रहे कि विधायक आवास का निर्माण कराया जा रहा है लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक विधायक आवास का निर्माण नहीं हुआ है ।

क्रमशः

टर्न-14/सत्येन्द्र/15-03-21

...क्रमशः...

श्री राकेश कुमार रौशनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं सदन में कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है पटेल भवन, जिस पटेल भवन को बनाया है उसके बारे में हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं। माननीय सभापति महोदय को भी पटेल भवन जाने का मौका मिला होगा, महोदय वहां अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है, वहां लोग जो जाते हैं उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और वहां हेलीपैड भी बनाया गया है और जो हेलीपैड बनाया गया है महोदय, उसका अभी तक टेस्टिंग भी नहीं हुआ है कि यदि हेलिकॉप्टर उतरेगा उस मकान पर तो उसकी क्या स्थिति होगी, इसकी कोई टेस्टिंग अभी तक सरकार के द्वारा नहीं करायी गयी है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की स्थिति है । सभापति महोदय, इसके अलावे हमारे दरभंगा में इंजीनियरिंग कॉलेज की बाउंड्री कराने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही घोषणा की थी लेकिन अभी तक दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाउंड्री का निर्माण नहीं कराया गया है । महोदय, वह बहुत पुराना अभियंत्रण महाविद्यालय है, जिसकी स्थिति काफी जर्जर है । महोदय, हमारे नालंदा जिला में जो गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, हमारे माननीय मंत्री, श्रवण बाबू यहां बैठे हुए हैं, वे हमारे ही जिला के हैं, हमारे इस्लामपुर के बगल में खुदागंज बाजार है महोदय, जहां लगभग 10 हजार की आबादी है, खुदागंज बाजार में अस्पताल निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से सात वर्ष पूर्व किया गया लेकिन अभी तक वहां अस्पताल के भवन का निर्माण नहीं हुआ है महोदय और वहां जो हैं डॉक्टर कोई बैठते नहीं है, अस्पताल की स्थिति काफी जर्जर है, जो पहले का जीर्णशीर्ण स्थिति थी वही आज भी है महोदय, तो ये चेहरा है हमारे भवन निर्माण विभाग का महोदय । अब मैं पी0एच0ई0डी0 विभाग पर कुछ बातें आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा, जो पी0एच0ई0डी0 का बजट भाषण प्रस्तुत किया गया था, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बिहार के हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि सुलभ स्वास्थ्य हासिल करने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। इस संबंध में महोदय, मैं सबसे पहले इस बिहार प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी वे सदन के सदस्य नहीं है लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की थी पेयजल की शुद्धता के बारे में, मैं उसको आपको पढ़कर के बता रहा हूँ । हुजूर, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री की स्पीच है माननीय सुशील कुमार मोदी जी की, उन्होंने कहा है कि बिहार के 38 में से 37 जिलों का पानी पीने लायक नहीं है, इनमें फ्लोराईड, आर्सेनिक और आयरन का

संक्रमण है । सरकार के तमाम प्रयासों के वाबजूद राज्य के 31 हजार वार्डों में गुणवत्ता पूर्ण पेयजल की आपूर्त्ति आज भी चुनौती बनी हुई है । वे रविवार को एन0आई0टी0, पटना के सभागार में इंडियन वाटर वर्कर एसोसिएशन के 52वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे । यहां उप मुख्यमंत्री मोदी की स्वीकारोक्ति यह बतला रही है कि राज्य की बड़ी आबादी आज भी संक्रमित पेयजल के कारण गंभीर खतरे के जद में है । उसके साथ ही महोदय संक्रमण का दायरा बढ़ा है, क्योंकि महज कुछ साल पहले तक राज्य के 28 जिले ही पेयजल के संक्रमण के दायरे में थे और ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी का एक्सेप्टेंस है महोदय और उन्होंने इसी में आगे बताया है कि इससे कैंसर, फ्लरोसीस और गैस संबंधी बीमारी जो है बिहार में बढ़ रही है महोदय और अभी जो महोदय दूषित पेयजल की स्थिति है पूरे देश के अंदर महोदय, उसमें बिहार का क्या हालत है महोदय, इस संबंध में कम्परेटिव एफ0एच0टी0सी0 कवरेज स्टेटस जो है 31 दिसम्बर 20 का, उसका आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें कहा है स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने महोदय कि At present more than 32.54 percent rural households in india have tap water connections in their homes. While 15 states/Uts have above national average percentage of tap water connections, 17 states/Uts fall below the national average. Goa has become the first state to become' Har Ghar jal State ' The State of Telangana is also inching closer to achieve 100% 'Har Ghar Jal' Puducherry, Haryana and Gujarat have provided Tap Water Connections in more than 80% of their rural households. ये नेशनल रिपोर्ट है महोदय, इसमें बिहार की जो स्थिति है, बिहार नीचे से दूसरा स्थान पर है महोदय, पूरे देश के अंदर में यानी बिहार के लोगों को अभी भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है और ये सरकार कह रही है कि हम बिहार में 'हर घर नल का जल' योजना चला रहे हैं। 'हर घर नल का जल' योजना का क्या हश्र है स्थिति है महोदय, इसको यदि आप देखेंगे तो बिहार के अंदर जो सात निश्चय योजना के अन्तर्गत 'हर घर नल का जल' योजना चल रही है महोदय इसमें सरकार का एक्सेप्टेंस है महोदय बजट भाषण में कि राज्य में 4095 ग्राम पंचायत के 52142 बार्ड में यह योजना पूर्ण हो चुकी है । ये माननीय मंत्री जी का बजट भाषण में है लेकिन फिर इसी विभाग के विभाग प्रमुख ने कहा, जो पी0एच0ई0डी0 के विभाग प्रमुख हैं, उनका जो स्टेटमेंट है, जो असेसमेंट किये थे मुख्यमंत्री जी पिछले 21 तारीख को उस समय जो ...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): आपका समय अब मात्र दो मिनट है ।

श्री राकेश कुमार रौशन: थोड़ा समय बढ़ा दिया जाय महोदय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): समय तय है न । अभी आप बोलिये, समय है 2 मिनट ।

श्री राकेश कुमार रौशन: इसमें कहा गया था कि 55873 बार्ड में काम अभी पूरा हो चुका है जबकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यह जो स्कीम है, मात्र 52142 वार्ड में पूरा हो चुका है तो महोदय यह जो दोनों आंकड़ा है, स्पष्ट करता है कि सरकार गलत बोल रही है या तो मंत्री गलत बोल रहे हैं या विभाग के प्रमुख गलत बोल रहे हैं तो 'हर घर नल जल' की स्थिति यह है कि पूरे बिहार के अंदर गांव में कहीं भी नल जल का पानी नहीं पहुंच रहा है और जो गुणवत्ता है, उसकी स्थिति यह है कि तीन फीट गड्ढा में पाईप को डालना था 'हर घर नल जल' योजना में लेकिन मैं सदन के माध्यम से सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ कि किसी भी जगह पर, कहीं भी पी0एच0ई0डी0 ने अपने मानक का उपयोग नहीं किया है, कहीं भी तीन फीट गड्ढा खोदकर पाईप नहीं लगाया गया है और न ही नल और टेप लगाया गया है जो विभाग की प्राथमिकता है । इस तरह से महोदय, ये जो पी0एच0ई0डी0 के द्वारा बजट पेश किया गया है, उसमें आप देखेंगे तो सात निश्चय योजना को सिर्फ एक मजाक के रूप में बिहार के अन्दर अभी प्रदर्शित करने का काम किया गया है । आज जो इसकी धरातल पर स्थिति है वह बिल्कुल ही भिन्न है, आज भी गांव के अंदर महोदय मैंने बतलाया है आंकड़े के अनुसार कि 32 प्रतिशत लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है इसलिए इस स्थिति में कैसे महोदय बिहार के लोगों का शुद्ध पानी मिलेगा । इसके बाद महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग जिसका भी आज अनुपूरक बजट पेश किया गया है, इसमें जो समाज कल्याण विभाग है महोदय, इसको यदि आप देखेंगे महोदय तो यह सरकार कहती है कि महिलाओं को, बच्चों को, दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को, समाज के अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार संकल्पित है । महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो खाद्यान्न योजना चल रही है, उसमें स्टैंडर्ड जो लिमिट निर्धारित की गयी है, उसमें बताया गया है कि एक दिन में कितना खाना खाना है । उसमें बताया गया है कि जो 6-9 माह के बच्चे हैं महोदय, उनको 200 ग्राम मुलायम खाना जैसे दाल, चावल, खिचड़ी 1/4 लगभग दो छोटी कटोरी 24 घंटे में देना है, इसी तरह से 9-12 माह और 12-24 माह के बच्चों को देना है ताकि उनको कुपोषण से बचाया जा सके उसको महोदय, किस तरह से उसका हेल्थ डेवलप हो, किस तरह से उसका इम्युनिटी सिस्टम डेवलप हो इसके लिए इतना भोजन उपलब्ध कराना है महोदय लेकिन भारत सरकार ने जो

पैमाना तय किया है, उसके बाद भी यदि आप समीक्षा करेंगे तो बिहार के अन्दर जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा जो निर्धारित किया गया है भोजन की व्यवस्था का, उसका पूरे तौर पर महोदय बिहार में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

सभापति(श्री प्रेम कुमार): अब संक्षिप्त कर लें ।

श्री राकेश कुमार रौशन: इसके अलावे महोदय, सेविका और सहायिका का घोर अभाव है पूरे बिहार में और सेविका और सहायिका के अभाव के चलते इसका योजना पर प्रभाव पड़ रहा है। सभापति महोदय, अभी लगभग 60 हजार पद पूरे बिहार में सेविका और सहायिका का रिक्त है। (क्रमशः)

टर्न-15/मधुप/15.03.2021

..क्रमशः..

श्री राकेश कुमार रौशन : जिसके चलते समाज कल्याण विभाग के अपने जो कार्यक्रम हैं, उसको सही ढंग से धरातल पर क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं । हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग में जो रिक्त पद हैं, उसको भरा जाय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राकेश कुमार रौशन : महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक-दो बात कहकर समाप्त कर दूँगा । हमारे यहाँ आंगनबाड़ी की यह स्थिति है कि जो हमारे यहाँ सी0डी0पी0ओ0 हैं इस्लामपुर में, कभी मुख्यालय में नहीं रहते हैं, वे पटना में रहते हैं, पटना से ही काम करते हैं, कभी मुख्यालय इस्लामपुर में नहीं रहते हैं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया है । माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ।

श्री राकेश कुमार रौशन : एक मिनट, महोदय । एकंगरसराय में सी0डी0पी0ओ0 हैं दूसरे जगह के प्रभार में हैं, वे कभी नहीं आती हैं एकंगरसराय को देखने के लिए ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जायं ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय जी, आपका समय 12 मिनट है ।

(व्यवधान)

हाउस में थे, गये हैं बगल में, आ रहे हैं । सबलोग हैं, माननीय मंत्री भी थे, अभी गये हैं। पूरी सरकार बैठी हुई है ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में एवं सरकार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, जन विकास की बातों को जब भी सदन में रखने का अवसर मिलता है तो मुझे बड़ी सुखद अनुभूति होती है । महोदय, भवन निर्माण विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसका बिहार के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान है । महोदय, आज जब भी बिहार में कहीं जाने का अवसर मिलता है, तो ऊँची-ऊँची सरकारी इमारत एवं भवनों को देखकर लगता है कि हमारा बिहार भी देश के विकसित राज्यों में से एक है । महोदय, इस विकास का सबसे पहला श्रेय अगर किसी को जाता है तो, वह है हमारे नेता और बिहार के विकास पुरूष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी । नीतीश कुमार जी ने ही एक बीमारू और बिखरे हुए बिहार को एकजुट कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है ।

महोदय, 2005 के पहले बिहार में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई0टी0आई0 कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सैनिक स्कूल के भवनों की जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है । महोदय, यह प्रसन्नता का विषय है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जनता का जो सपना था, वह आज साकार होते नजर आ रहा है ।

महोदय, भवन निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कई बड़ी योजनाओं को सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया है जो कि निम्न प्रकार से हैं -

सात निश्चत के अंतर्गत 317.95 करोड़ की लागत से अभियंत्रण महाविद्यालय बख्तियारपुर(पटना), सुपौल, जमुई एवं बॉका का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है ।

सात निश्चय के अंतर्गत 72.70 करोड़ की लागत से राजकीय पौलिटेक्निक अररिया एवं सिवान का कार्य पूर्ण किया गया है ।

73.92 करोड़ की लागत से महिला आई0टी0आई0 किशनगंज और वैशाली एवं पुरूष आई0टी0आई0 नालन्दा, भेलारी(सासाराम) और धमदाहा(पूर्णियॉं) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है ।

61.00 करोड़ की लागत से पटना में बहुद्देशीय प्रकाश पुंज का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

59.98 करोड़ की लागत से पी0एम0सी0एच0 में आई0जी0आई0सी0 के भवन का निर्माण कार्य । साथ-ही, गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट के पंचायत सिपाया में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज का भवन निर्माण कराया जा चुका है ।

महोदय, वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य प्रगति में है :-

633.00 करोड़ की लागत से राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम-सह-खेल अकादमी का निर्माण कार्य । 145.00 करोड़ की लागत से बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण कार्य ।

301.400 करोड़ की लागत से वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण कार्य ।

397.00 करोड़ की लागत से पटना में ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य ।

139.00 करोड़ की लागत से गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य ।

37.61 करोड़ की लागत से बिहार लोक सेवा आयोग में नये भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है ।

169.50 करोड़ की लागत से बेतिया में एवं 41.223 करोड़ की लागत से मोतिहारी में 2000 क्षमता का प्रेक्षागृह का निर्माण ।

164.00 करोड़ की लागत से दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(व्यवधान)

जो हमारी सरकार ने काम किया है, वही न बोलेंगे । 2005 के पहले की बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : बैठे-बैठे नहीं बोलें । शांत रहें । माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखकर बोलें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : 32.98 करोड़ की लागत से सिंचाई भवन, 61.62 करोड़ की लागत से पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन एवं 61.46 करोड़ की लागत से विकास भवन का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है ।

84.49 करोड़ की लागत से पटना में बापू टावर का कार्य प्रगति पर है ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सात निश्चय के तहत बख्तियारपुर (पटना), सुपौल, जमुई एवं बांका जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 20 अन्य जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 5 अन्य जिलों में कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है । अररिया एवं सिवान जिलों में राजकीय पॉलिटेक्निक का कार्य पूर्ण हो गया है । 4 अन्य जिलों में कार्य प्रगति पर है तथा 3 अन्य जिलों में कार्य प्रारंभ

करने की कार्रवाई की जा रही है । प्रत्येक अभियंत्रण महाविद्यालय का मानक प्राक्कलन की राशि लगभग 73.13 करोड़ है एवं राजकीय पॉलिटेक्निक की मानक प्राक्कलन की राशि लगभग 36.35 करोड़ है ।

राज्य के 24 जिलों में लगभग 9.00 करोड़ प्रति इकाई की लागत से प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र एवं 12.00 करोड़ प्रति इकाई की लागत से प्रखंड कार्यालय-सह-आवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

राज्य के 10 जिलों-अररिया, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी), शिवहर, पूर्णियाँ, पश्चिमी चम्पारण(बेतिया), कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा में बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण योजना शुरू की जा रही है जिसकी प्रति इकाई लागत 01.00 करोड़ है । राज्य के 34 जिलों में जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसकी प्रति इकाई लागत 01.15 करोड़ है ।

सात निश्चय योजना के तहत विभिन्न जिलों में महिला एवं पुरूष आई0टी0आई0 का निर्माण प्रगति पर है । प्रत्येक का औसत लागत लगभग 18.00 करोड़ है ।

105.00 करोड़ की लागत से मुंगेर में वाणिकी कॉलेज का निर्माण ।

164.31 करोड़ की लागत से पटना के फुलवारीशरीफ में परिवहन विभाग का वर्कशॉप एवं अन्य भवन का निर्माण कार्य तथा 250.00 करोड़ की लागत से बिहटा में विकास प्रबंधन संस्थान का निर्माण कार्य शुरू किया गया है ।

83.40 करोड़ की लागत से पटना के शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के आवास का निर्माण ।

गर्दनीबाग आवासीय परिसर में 52.76 करोड़ की लागत से माननीय मंत्री आवासन, 443.62 करोड़ की लागत से पदाधिकारी आवासन, 120.43 करोड़ की लागत से तृतीय श्रेणी के कर्मियों हेतु आवासन एवं 249.90 करोड़ की लागत से चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का आवासन की योजना का कार्य प्रगति में है ।

महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ की गयी है:-

186.42 करोड़ की लागत से पटना में नये समाहरणालय भवन का निर्माण ।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का निर्माण ।

पटना संग्रहालय का उन्नयन कार्य ।

राज्य अतिथि गृह, बोधगया का निर्माण कार्य ।

...क्रमशः...

टर्न-16/आजाद/15.03.2021

.... क्रमशः .....

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : साथ ही बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा गरीब परिवार के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी, एडस रोगी, भिक्षुक आदि व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है । इसके तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निम्न योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है ।

महोदय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अन्तर्गत समाज के असंगठित कोटि के असहाय वर्गों के लिए 6 पेंशन योजनाएँ संचालित है, जो निम्न प्रकार है-

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना- राज्य में वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन हेतु एक नयी योजना ''मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना'' विभागीय अधिसूचना सं0-1247 दिनांक 26.02.2019 द्वारा अधिसूचित की गयी है, जिसमें राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो......

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपका समय मात्र दो मिनट बचा है, कृपया कंक्लूड करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : उन्हें 60-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 400/- एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500/-रू0 का मासिक पेंशन दी जा रही है ।

महोदय, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - 60-79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को 400/-रू0 प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध को 500/-रू0 प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी की दर से पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना - बी0पी0एल0 परिवार के 40-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 400/-रू0 प्रति माह प्रति पेंशनधारी को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाता है ।

महोदय, लक्ष्मीबाई(विधवा) पेंशन योजना - बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 400/-रू0 प्रतिमाह प्रति पेंशनधारी को डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाता है ।

महोदय, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना - बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 वर्ष आयु वर्ग में 80 प्रतिशत या .....

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति महोदय, बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना - किसी भी आयु एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता के लिए 400/- रू0, बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री सउद आलम जी, आपका समय 5 मिनट है ।

श्री सउद आलम : सदरे जनाब मोहतरम जी, आज आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ । साथ ही मैं अपने हल्का ठाकुरगंज के आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भारी मतों से जिताकर यहां भेजने का काम किया ।

महोदय, जब भी कोई बजट आने वाला होता है तो सीमांचल के लोग बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार बजट में उनके मसाइल का हल होगा और उनकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आयेंगी । शायद उन्हें सैलाब, बेरोजगारी, पलायन और भुखमरी की मार से कुछ राहत मिलेगी । इस बार भी इस तथाकथित डबल इंजन की सरकार से लोगों की ऐसी ही उम्मीदें वाबिस्ता थीं । इस बजट में सीमांचल के आवाम के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है । लिहाजा आवाम के साथ-साथ मुझे अभी इस बजट के मुताले से बेहतद मायूसी हुई ।

मुस्लिम अकलियत जिनकी हालत बदतर है उनके लिए किसी खास पैकेज का ऐलान नहीं किया गया । अकलियत के लिए वजीरे खजाना को फराक दिली का सबूत देना चाहिए था । उनके मुआशी, सामाजी, तालीमी पसमंदगी को दूर करने के लिए एक कसीर जहती मनसूबे का ऐलान होना चाहिए था ।

मेरा हल्का इंतकाम ठाकुरगंज और उसके इर्द गिर्द फैले हुए सीमांचल के इलाके तालीमी, मुआशी, सामाजी और हिफजाने सेहत के लिहाज से तशविशनाक एक हद तक पसमांदा है । हमारे नेता मोहतरम जनाब लालु प्रसाद यादव की मेहरबानी की वजह से यू0पी0ए0-1 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गयी जिससे कि पूरे इलाके में इल्म की रोशनी फैले । लेकिन आज तक पिछले पंद्रह सालों में नीतीश जी की सरकार ने इसपर आगे कोई पहलकदमी नहीं किया जबकि इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है ।

जानलेवा बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, किडनी और कैंसर की मोहलिक बीमारियों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और वहां इलाज की सहूलियत नहीं के बराबर है । अफसोसनाक सूरत-ए-हाल यह है कि उस पूरे इलाके में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज या मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल नहीं है । सदरे मोहतरम आपके तवस्सुत से

सरकार से मेरा यह मुतालबा है कि किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज और उसके साथ एम्स की तर्ज पर एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए ।

हमारा इलाका महानंदा, कोसी, डौक, मेछी, कंकाई, परवान और बकरा जैसी तेज बहाव वाली तबाहकुन नदियों में घिरा है । हर साल हजारों एकड़ जराअती जमीन और दर्जनों गांव अपना वजूद खो देते हैं । सरकार को नदियों में बॉध बांधने के लिए स्कीम लाना चाहिए लेकिन सरकार सिर्फ प्लास्टिक और चूड़ा बांट कर सैलाब में मदद की खानापूर्ति करती आयी है । गरीबी और पलायन को रोकने के लिए सरकार को वहां इन्डस्ट्रीज लगाने चाहिए ।

सदरे मोहतरम मेरी पार्टी की मेनिफेस्टो में सीमांचल के विकास और बेहतरी के लिए सीमांचलन आयोग के गठन का वायदा किया गया था । हमारे नेता मोहतरम जनाब तेजस्वी यादव जी सीमांचल के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं । जब राजद की सरकार थी तो पूरे सीमांचल से कई एक लोग मंत्री बनते थे । मरहूम तस्लीम साहब का ओहदा सरकार में बहुत बड़ा हुआ करता था । आज हमारे सीमांचल की नुमाइंदगी कहीं नहीं दिखती । जिससे की पूरा इलाका पिछड़ता जा रहा । बिहार में स्कूलों की सबसे बदतर हालत अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है । स्कॉलरशिप सबसे कम सीमांचल के बच्चों को मिलती है । हर एक क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारा इलाका बहत पिछड़ा है । अब भी सड़कें, पुल-पुलिया की भारी कमी है । मैं सरकार की उदासीनता की वजह से मोहतरमे वजीरआला, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा । मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपनी बात खतम करता हूँ । जयहिन्द, जयभारत ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास जी ।

श्री गोपाल रविदास : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सबसे पहले मैं फुलवारी विधान सभा के जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ भाकपा माले जिनके बल पर मैं बिहार विधान सभा में आया हूँ, उनके प्रति भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सभी मित्रों को, सभी माननीय सदस्यों को हम क्रांतिकारी लालसलाम करते हैं ।

सभापति महोदय, अभी आपने देखा कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़ी-बड़ी वकालतें की । सरकार के बजट को लगातार कई सदस्यों ने पढ़ने का काम किया है । हम समझते हैं कि इतिहास में जो ग्लोब्लस का नाम है, जो असत्य बोला

करते थे लगातार, जिस बजट में कई तरह की खामियां हैं लगातार सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बोलकर के ग्लोब्लस को भी झुठलाने का काम किया है ।

सभापति महोदय, जहां तक भवन निर्माण का सवाल है तो भवन निर्माण सरकारी कार्यालय, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और हम ज्यादा दूर कहां जाय, बगल का जो फुलवारी विधान सभा है, महज जहां पर विधान सभा चल रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर है । अभी-अभी जो ताजा रिपोर्ट है, फुलवारी विधान सभा के सभी शिक्षकों को पुनपुन और फुलवारी के सभी माननीय शिक्षकों को जिसमें सभी प्रिंसिपल हैं प्राथमिक विद्यालय से लेकर के मिडिल एवं हाईस्कूल के हेडमास्टर साहेब का बैठक बुलाया, उसमें जो रिपोर्ट आयी है अखबार और टी0वी0 के माध्यम से कि जो डबल इंजन की सरकार प्रचार करती है कि दुनिया ही बदल रहा है, पूरा बिहार बदल रहा है, दुनिया के नक्शे पर बिहार नम्बर-1 पर आयेगा । लगभग 50 ऐसे प्राइमरी एवं उत्क्रमित मिडिल स्कूल एवं 10प्लस 2 विद्यालय हैं, जिनके ब्लिडिंग नहीं है । जर्जर स्थिति में है और पूरे फुलवारी शरीफ के अन्दर स्कूल में चहारदीवारी नहीं है और सूअर एवं कुत्ते घुमते रहते हैं । कई-कई स्कूलों में नालियां बह रही हैं । लगातार सरकार एवं उसके मशीनरी लिखा जाता रहा है लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, यह स्थिति है । यह आईना है और यह बिहार की तस्वीर बताता है । हमारे सम्मानित मित्र कहते हैं कि बिहार को पूरे विश्व के नक्शे पर ले जायेंगे । पहले फुलवारी विधान सभा को राजधानी के नक्शा पर तो ले आइए, यह स्थिति है ।

(व्यवधान)

चरवाहा विद्यालय में तो कम से कम बच्चा पढ़ता था, कम से कम भैंस पर चढ़कर भी बच्चा पढ़ता था लेकिन आज स्थिति यह है कि आज मास्टर लोगों को भी अपमानित होना पड़ रहा है और भाकपा माले के लोग मान और सम्मान के लिए इसकी लड़ाई तेज किये हुए हैं । यह मैं पूरे दावे के साथ, चैलेज के साथ कहता हूँ कि मैदान में चलकर देखिए । जहां तक सामाजिक कल्याण का सवाल है तो आपने देखा कि इसी सत्र में जब हमने सवाल उठाया कि जो नई प्रथा प्रणाली आयी है, इसमें लाखों लोगों की पेंशन काट दी गयी है । मंत्री महोदय जी माननीय मदन सहनी जी से सवाल किया कि उनका पेंशन बनेगा कि नहीं बनेगा तो कहते हैं कि माले वाले की दुकान ही बन्द हो रही है, इनका कार्यालय चलाने का काम करें । कितनी बेशर्मी की बात है और पूरे डंके के चोट पर सरकार कह रही है कि बिहार विकास कर रहा है, यह स्थिति है । यह सभी

लोग जानते हैं कि कन्या विवाह का पैसा पूरे दो साल से लोगों को नहीं मिला है । कबीर अंत्येष्टि का जो पैसा है, कहां जाता है कि मरने पर बांसघाट ओर गुलबी घाट के लिए पैसा दिया जायेगा, वहां के लिए पैसा नदारद है, दो साल से पैसा नहीं मिल रहा है ।

..... क्रमशः .....

टर्न–17/शंभु/15.03.21

...क्रमशः...

श्री गोपाल रविदास : जिन गरीबों के नाम पर पैसा डकारने का काम कर रही है पूरी व्यवस्था यह बड़े शर्म की बात है और उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो बड़े डंके की चोट पर कहते हैं कि बिहार विकास कर रहा है । माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी हालत क्या है आपने देख बाल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मानव विवाद से निपटने के कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की योजना, विधवा पेंशन योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना सबके सब भ्रष्टाचार के दलदल में समा गयी हैं । यह दावे के साथ सरकार नहीं कह सकती है कि हम नीट ऐंड क्लीन स्थिति में बढ़ रहे हैं । आप व्यवहार में धरातल पर जाइये– पटना राजधानी में बैठकर बड़ी–बड़ी वकालत मत कीजिये, गरीबों की हालत क्या है इसको जाकर देखिए, वही आइना है आपको पता लग जायेगा कि बिहार कितना विकास कर रहा है । हमने देखा है कि जिन बिल्डिगों में जर्जर भवनों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पांचवां तक पहाड़ा भी नहीं आ रहा है और कह रहे हैं कि बिहार विकास करेगा । एक भी सरकारी पदाधिकारी के बच्चे उन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं जहां गड़बड़ स्थिति है । आप फुलवारी के कोरियामा में जाकर देख लीजिए वहां स्कूल नहीं है, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते हैं । यह स्थिति है आपके बिहार विकास की । यह आपके लिए आइना है जाकर देख लीजिए । ये तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य पटना में रहते हैं थोड़ा बगल में जाइये जहां पर आपको– आप कहते हैं कि पटना में घुसते हैं तो बड़ा आलीशान बिल्डिग लगता है । अरे, झोपड़ी वाले की क्या स्थिति है, झोपड़ी वाले लगातार कह रहे हैं कि हमारे लिये भवन बनेगा कि नहीं बनेगा ? 40 हजार रू0 उनको नजराना देना पड़ता है । यह स्थिति है शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में ये योजना है....व्यवधान.. गलत बोलते हैं तो जॉच पड़ताल बैठा दीजिए सभापति महोदय, तब उनकी बोलती बंद हो जायेगी और नहीं तो चाइलेंच करके दो सदस्यीय कमिटी बना दीजिए उसमें माले के लोग रहेंगे, भाजपा और जनता दल यू0 के लोग रहेंगे तब उनको पता लग जायेगा । माननीय सभापति महोदय, परिवहन की जो

स्थिति है, परिवहन की स्थिति के बारे में बोल रहे हैं पटना जिला के पालीगंज वाला जो सरकारी बस स्टेंड था उसको तोड़ मरोड़कर कहां लापता कर दिया गया, पता नहीं है और कह रहे हैं बिहार का विकास हो रहा है । जहां फुलवारी से हम जीतकर आते हैं जहां से जनता ने भारी मतों से जिताकर भेजा है- सामंती किला को ढाहकर झंडा फहराकर हमको जिताकर भेजने का काम किया है । वहां बस स्टेंड नहीं है । फुलवारी देश और दुनिया के इतिहास में वहां पर पूरे देश विदेश ही नहीं पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से लोग नमाज अदा करने आते हैं, लेकिन वहां पर बस स्टेंड नहीं है और सरकार कह रही है कि बिहार विकास कर रहा है । वहां पर एक अदना सा बस स्टेंड नहीं है और कह रहे हैं कि परिवहन का वर्कशॉप चल रहा है, कहां पर चल रहा है जगह तो बता दीजिए । हम माननीय मंत्री महोदय से जो विभाग के हैं बताने का काम कीजियेगा कि परिवहन का कहां काम चल रहा है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री गोपाल रविदास : हम उसी क्षेत्र से जीतकर आते हैं कहां बना दिया चुपके-चुपके आपने, कहां चुपके-चुपके आपने बना दिया ? हम उसी क्षेत्र से आते हैं कहां आपने बनाया है ? हम समझते हैं कि मंत्री महोदय उसका जवाब देने का काम करेंगे ।

(व्यवधान)

चलिए, बीमार होइयेगा तो आप ही काम लीजियेगा ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : अब आप संक्षेप करें ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की स्थिति यह है कि डंके के चोट पर सात निश्चय योजना जो है नल जल योजना लगायी जा रही है और पी0एच0ई0डी0 उसमें दो विभागों में बांटा गया है पी0एच0ई0डी0 और जे0वाई0जी0- बाद में बांटा गया पी0एम0जी0वाई0 में और पी0एच0ई0डी0 में जो बड़े लोग हैं वे बड़ा साइलेंटी काम करवा लिये ताकि पैसा नहीं देना पड़ेगा और पी0एम0जी0वाई0 में गरीबों का काम दे दिया गया और 32 रूपया वसूला जा रहा है ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जायं आपका समय समाप्त हुआ । सुश्री श्रेयसी सिंह जी, आपका दस मिनट समय है, प्रारंभ करें ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में और सरकार के बजट मांग के पक्ष में आज मैं सदन में सबसे पहला भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ । सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को सादर प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और आज इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में लाकर खड़ा किया है ।

आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमारे दल के सचेतक को और साथ ही सभापति महोदय आसन को तहेदिल से धन्यवाद कहती हूँ कि सदन का बहुमूल्य समय मुझे आवंटित किया है अपने विचारों को सामने रखने के लिए । सभापति महोदय, किसी भी सरकार के लिए आधारभूत संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है । इन संरचनाओं के सामाजिक महत्वपूर्ण भवन है जिसके संबंध में आज मांग प्रस्तुत की गयी है । इसमें भी कटौती प्रस्ताव दिया गया है जो आश्चर्यजनक है । विपक्ष को तो समर्थन करना चाहिए कि जितने अधिक भवनों की आवश्यकता है उनका निर्माण सरकार पूरा करे । एक ठोस बुनियाद पर ही सशक्त और संपन्न राज्य का निर्माण हो सकता है । आज हमारी सरकार और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी की राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए और साथ ही साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रयासरत हैं । अन्य आई0टी0आई0 एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया है और साथ ही अन्य कॉलेजेज का निर्माण होने जा रहा है। अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि किस तरह से पुरूष एवं महिला आई0टी0आई0 कॉलेज और अभियंत्रण विश्वविद्यालय बांका, जमुई, सुपौल और बख्तियारपुर का निर्माण कार्य पूरा किया गया है । महोदय, बेहद प्रसन्नता होती है न सिर्फ एक सदस्या होने के नाते बल्कि एक एथलीट होने के नाते कि इस बार 633 करोड़ की लागत से राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऐकेडमी और साथ ही एक खेल ऐकेडमी का निर्माण कार्य प्रगति पर है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 397 करोड़ की लागत से पटना में ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साइंस सिटी और 164 करोड़ की लागत से दरभंगा में तारामंडल का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में पटना में 186 करोड़ की लागत से एक नया सेक्रेटेरियट भवन का निर्माण किया है । बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण एवं पटना में संग्रहालय के उन्नयन कार्य हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गयी है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में भवन निर्माण विभाग का कुल प्राक्कलन 5321.41 करोड़ है । सभापति महोदय, मेरा मानना है कि भवन निर्माण विभाग की परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है । किसी भी विभाग की परियोजना में हम शिकायत आने पर ही उसकी जॉच करते हैं और दोषी पाये जाने पर उसपर कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन भवन निर्माण और माननीय मंत्री से यही आग्रह है कि परियोजनाओं का महत्व देखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन परियोजनाओं की देखरेख पूरी सक्रियता से हो । साथ ही जमुई में एस0सी0/एस0टी0 और अल्पसंख्यक आवास विद्यालय के लिए जमीन आवंटित है । मैं माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूँगी कि इसके भवन निर्माण का कार्य भी जल्द शुरू किया जाय ।

महोदय, परिवहन विभाग की बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत के साथ चयनित लाभुकों को वाहन की खरीद पर खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकतम एक लाख अनुदान के भुगतान का प्रावधान किया गया है ।

क्रमशः

टर्न-18/ज्योति/15-03-2021

क्रमशः

सुश्री श्रेयसी सिंह : जिसमें जमुई में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 751 लाभुकों को लाभान्वित कर युवाओं को रोजगार दिया गया है । पूरे बिहार में 35 हजार लोगों को इसके तहत लाभ देकर रोजगार दिया गया है । वाहनों के ऑन लाईन निबंधन और चालक अनुज्ञप्ति का ऑन लाईन आवेदन एवं प्रशिक्षकों को अनुज्ञप्ति हेतु ऑन लाईन टेस्ट की व्यवस्था भारत के प्रधान मंत्री मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के डिटिजल बिहार के सपने को साकार करती नजर आती है । केन्द्र की योजनाओं को राज्य भी पूरी ताकत से लागू कर रहा है और यही वास्तविकता में एक डबल इंजन सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है । हवा में जब सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है तो वह वाहनों के कारण से होता है । सिर्फ हमारा राज्य ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से आज लड़ रहा है और आज हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है । प्रदूषण जॉच केन्द्र की स्थापना, इस प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है । यही नहीं चलन्त वाहन जॉच केन्द्र का भी प्रावधान किया गया है । साथ ही 15 वर्ष से अधिक सभी पुराने सरकारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है । पटना में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की शुरुआत की गयी है । पटना सिटी बस सर्विस में ज्यादा से ज्यादा ऐसी बसों की जरुरत है ताकि शहर और उसके आस पास बढ़ रहे प्रदूषण की रोक थाम हो सके । मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस नेटवर्क का जाल पूरे प्रदेश में बिछा दिया जाय ताकि लोगों को अच्छी परिवहन सेवा के साथ-साथ प्रदूषण से भी निजात मिले । माननीय सदस्यों को यह भी बता दूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में बस स्टॉप भी बनाया जा रहा है जिसमें कि जमुई में ही 18 बस स्टॉप स्वीकृत किए गए हैं । मैं मंत्री जी से यही मांग करती हूँ कि जमुइ- पटना रूट पर सरकारी डिलक्स बस सर्विस शुरू की जाय साथ ही जमुई नगर परिषद स्थित टेम्पो स्टैण्ड पर्याप्त नहीं है जिसके कारण जाम और

अन्य समस्यायें उत्पन्न होती हैं अत: एक स्थायी बस स्टैण्ड और टेम्पो स्टैण्ड का इंतजाम किया जाय साथ ही नगर परिषद क्षेत्र स्थित बस स्टैण्ड का भी विस्तार किया जाय । सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्ध जनों एवं समाज के अन्य वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है जिसका मुख्य उद्देश्य इन सबों की समेकित उन्नति एवं विकास के लिए संविधान के विभिन्न अधिनियमों, राज्यादेश एवं नियमावली की नीतियों के अनुसार कार्य योजनायें एवं कार्यक्रम तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना है । समाज कल्याण विभाग में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वृद्धजन पेंशन लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन एवं अन्य पेंशन का लाभ सभी लाभुकों के खातों में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है । अभी बात हो रही थी किस तरह से इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब नहीं होता था तब बिचौलिए के द्वारा जनता का, सरकार का पैसा लूटा जाता है लेकिन आज भ्रष्टाचार का सवाल रहा ही नहीं चूँकि यह पैसा डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक एकाउंट में जा रहा है । मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों के सम्मानपूर्ण जीवन यापन हेतु राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो रही है जिन्हें केन्द्र, राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है उन्हें 60 से लेकर 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए ...

सभापति(श्री प्रेम कुमार): मात्र दो मिनट आपका समय बचा है ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : 4 सौ रुपये, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500 रुपये मासिक पेंशन दिया जा रहा है । अन्य सभी योजनायें जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर आती है उनकी जानकारी सरकार पहले भी दे चुकी है इसको दुहराने की जरुरत नहीं है । सभापति महोदय, भाषण की समाप्ति पर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जितना भी थोड़ा बहुत राजनीतिक ज्ञान मुझे प्राप्त है वह हमारे स्वर्गीय पिता दिग्विजय सिंह के द्वारा और मॉ पुतुल कुमारी के द्वारा प्राप्त हुआ है । हमारे माता-पिता अक्सर इसी श्लोक को कहा करते थे :

''अयं निज: परो वेति गणना लघु चेतसाम्,
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।''

अर्थात, यह तुम्हारा है, यह मेरा है, यह सोच रखने वाले का चित भी संकुचित होता है जबकि उदार चित रखने वाले लोगों के लिए यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है । पक्ष और विपक्ष एक ही हिस्से के दो पहलू है । एक के बिना

दूसरा अधूरा है अत: नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के माननीय सभी सदस्यों को, यह कहना चाहूंगी कि आपकी सकारात्मक भूमिका इस सदन को बल देगी और प्रदेश को सशक्त बनाने में सहयोगी होगी । आशा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्म निर्भर भारत बनाने की मुहिम और नीतीश कुमार जी के शीर्ष नेतृत्व में एक विकसित बिहार बनाना जो हम सभी का सपना है, वह साकार होगा । बहुत बहुत धन्यवाद। जयहिंद, जय बिहार ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री फते बहादुर सिंह जी, आपका पांच मिनट है ।

श्री फते बहादुर सिंह : धन्यवाद महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, नेता, प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का जो हमें इस योग्य समझे और मैं धन्यवाद देता हूँ डिहरी विधान सभा की जनता का जिन्होंने हमें सदन में भेजने का काम किया । सभापति महोदय, भवन निर्माण के लिए सत्ता पक्ष के द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए । हमारे डिहरी में रामा रानी महिला उच्च विद्यालय है दो साल पहले भवन निर्माण विभाग के द्वारा भवन का निर्माण हुआ और आज उस भवन की यह स्थिति है कि उस भवन में न डर से उसमें टीचर जा रहे हैं, न बच्चे जा रहे हैं और भवन हिल रहा है । इससे साबित यह होता है कि जो सत्ता पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है वह केवल कागज और कलम पर ही सीमित है । और 10 प्लस 2 के जितने भी विद्यालय हैं जो 10 से प्लस 2 हुआ है लगभग लगभग 60 परसेंट विद्यालयों में भवन नहीं है और भवन के अभाव के कारण बच्चों का ऐडमिशन नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

आप सर्वे करा लीजिये दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगी । जॉच करा लीजिये ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : आपलोग शांति बनाये रखिये ।

श्री फते बहादुर सिंह : महोदय, समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट पर मुख्यमंत्री जी लिखते हैं -महिलाओं के विकास के बिना हमारे राज्य का विकास संभव नहीं है । सभापति महोदय, यह कैसा महिलाओं का विकास है ? हमारे राज्य में आशा की महिलाएं मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर हैं । आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिका 100 रुपया और डेढ़ सौ रुपया प्रति दिन पर काम करने के लिए विवश हैं । बोल देना और कर देना दोनों में काफी अंतर है । महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं आपके माध्यम से जो आंगनबाड़ी की जो सेविका हैं जिनको

5 हजार रुपया प्रति माह दिया जाता है मैं उनको 10 हजार रुपया प्रति माह देने के लिए मांग करता हूँ । क्रमशः

टर्न-19/पुलकित-अभिनीत/15.03.2021

(क्रमशः)

श्री फते बहादुर सिंहः महोदय, जो आशा की महिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हैं, उनके लिए भी वेतन निर्धारण की मांग मैं करता हूं । समाज कल्याण विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा है। महोदय, हमारे डेहरी नगर की जो सी0डी0पी0ओ0 हैं वे हर सेविका से प्रतिमाह तीन हजार रुपया लेने का काम करती हैं । महोदय, जो सेविका सी0डी0पी0ओ0 को प्रतिमाह तीन हजार रुपया मंथली दे रही हैं वह पोषाहार से ही काट कर दे रही हैं । महोदय, अभी किराये का पैसा आया हुआ है, किराये का पैसा देने के लिए, फार्म जमा करने के लिए सेविकाओं से 6-6 हजार रुपया सी0डी0पी0ओ0 के द्वारा लिया जा रहा है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आपका समय मात्र दो मिनट बचा है ।

श्री फते बहादुर सिंहः महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि पूरे बिहार में बाल विकास परियोजनाओं की सरकार के माध्यम से जांच करायी जाय । महोदय, बजट भाषण में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने एक शायरी कही थी कि-

''रख हौसला वो मंजर भी आयेगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आयेगा ।
थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आयेगा ।।''

महोदय, 'मजबूत इरादों को लेकर हम आपके साथ खड़े हैं, लगी है प्यास लेकर ग्लास खड़े हैं, हम तो पलक बिछाये इंतजार कर रहे हैं विकास के समंदर का,' बस इतना बता दीजिए कि वो विकास का समंदर कब आयेगा ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): कृपया बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री फते बहादुर सिंहः धन्यवाद महोदय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, मुहम्मद इजहार असफी जी । आपका समय चार मिनट है।

श्री मुहम्मद इजहार असफी: माननीय सभापति महोदय, भवन निर्माण विभाग के कटौती प्रस्ताव पर अपना विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हूं और आपने मुझे बोलने का जो समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

महोदय, कोचाधामन की जनता ने मुझे बड़ी उम्मीद और आशा के साथ इस सदन में चुनकर भेजने का काम किया है । महोदय, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए मैं हमेशा क्षेत्र के मुद्दों को सदन में उठाने का काम करूंगा और इस पर आपका विशेष तवज्जो चाहूंगा । महोदय, राज्य और देश की समुचित विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है परंतु सरकार का इस दिशा में कोई कारगर पहल देखने को नहीं मिल रहा है । महोदय, बहुत से स्थानों पर भवनों का निर्माण बहुत पहले हुआ है परंतु अभीतक ये संचालित नहीं हुए हैं । महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोचाधामन में अनारकली और मौधो में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का भवन कुछ वर्ष पूर्व ही बन कर तैयार है परंतु उक्त स्वास्थ्य केंद्र अभी तक संचालित नहीं हुआ है । महोदय, भवन निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी के कारण कुछ वर्षों में ही भवन की स्थिति जर्जर हो जाती है ।

महोदय, अभी पूरे राज्य में नल-जल योजना का काम चल रहा है परंतु काम की गति अत्यंत धीमी होने के कारण अभी तक काम पूर्ण नहीं हो पाये हैं । महोदय, जिस वार्ड में काम पूर्ण हो चुका है, पाईप लिकेज, पाईप टूटने, जल आपूर्ति में बाधा, जल गुणवत्ता में कमी की शिकायतें आये दिन आती रहती हैं । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें जो दोषी पाये जायं, चाहे वे संवेदक हों या अभियंता उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए । महोदय, नल-जल योजना में भूमिदाता भी काफी कन्फयूजन में हैं । इन्हें कहा गया था कि आप जमीन दे दीजिये यहां पर टंकी बनायेंगे और आपको एक सरकारी स्टाफ के तौर पर पैसा दिया जायेगा, उसका भी खुलासा आज तक नहीं हुआ है । मुआवजा मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है । महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोचाधामन अंतर्गत बिशनपुर में एक पशु चिकित्सा केन्द्र है, जिसके भवन की स्थिति काफी जर्जर है । महोदय, किशनगंज जिले में एक भी राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स अकादमी नहीं है । महोदय, वृद्धजनों की पेंशनों का मामला जब से ऑनलाइन किया गया है तब से बहुत सारे वृद्ध एवं ....

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, आप संक्षेप करें । आपका एक मिनट बचा हुआ है ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी: विधवाओं और हैंडीक्राफ्ट लोगों की पेंशन रुकी हुई है । महोदय, अमौर और बैसा प्रखंड के कार्यालयों की स्थिति भी काफी जर्जर है और न जाने उन कार्यालयों की छतें कब पदाधिकारी लोगों पर गिर जाय, वहां पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है । महोदय, आपने हमें क्षेत्र की बातों को सदन में उठाने के लिए टाइम दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्या, श्रीमती ज्योति देवी जी ।

श्रीमती ज्योति देवी: माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता माननीय मांझी साहब को धन्यवाद देती हूँ, सूबे के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्या, आपका तीन मिनट का समय है ।

श्रीमती ज्योति देवी: महोदय, लोकतंत्र के मंदिर में भेजने वाली अपने विधान सभा की जनता को मैं नमन करती हूँ । सभापति महोदय, आज भवन निर्माण विभाग के बजट के अवसर पर मुझे बोलने का समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, भवन निर्माण विभाग के अनुदान की मांग के पक्ष में मैं अपनी बातों को रखने के लिए खड़ी हुई हूं । विकास एक अनुभूति है जिसे देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है । आज बिहार के चारों ओर जब आप नजर उठाकर देखेंगे तो सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत बड़ी-छोटी इमारतें जो दिखाई देती हैं, वह भवन निर्माण विभाग की ही होती हैं । उन आलिशान इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ रहा बल्कि सज-संवर रहा है और कहीं न कहीं पूरे देश, दुनिया के पर्यटकों की नजर बिहार की तरफ आकर्षित हो रही है । महोदय, मैं गया जिला के बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र की प्रतिनिधि हूँ । यहां के हर गांव की सबसे सुंदर अधिकांश इमारतें भवन निर्माण विभाग के द्वारा बनवाई गई हैं । एक तरफ विभाग के द्वारा 633 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 145 करोड़ की लागत से बोधगया में महाबोधि संस्कृति केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है । महोदय, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और सभी क्षेत्र के विकास के लिए भवन निर्माण विभाग का अपना अलग महत्व है । अब जब साइंस सिटी के निर्माण की बातें उठी हैं तो हमने तय किया है कि पटना को साइंस सिटी की आवश्यकता है, इसलिए हमने यहां ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के नाम पर साइंस सिटी की मंजूरी दी है, जिसका निर्माण भी भवन निर्माण विभाग कर रहा है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में

सर्वांगीण विकास हो रहा है । महोदय, बिहार के सभी विभागों की बगियों को सजाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(क्रमशः)

टर्न-20/हेमन्त-धिरेन्द्र/15.03.2021

...क्रमशः...

श्रीमती ज्योति देवी : मैं थोड़ी-सी बात कह देना चाहती हूं । सदन से हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, हमारी देश-दुनिया से, हम लोगों को जो भेजने वाले हैं, हमारी जनता हम सबको देखती है । हम लोगों का यही दायित्व है कि यहां से अच्छा संदेश अपने क्षेत्र के लोगों को दें । अभी हाउस में दो-तीन दिन से जो सिलसिला चल रहा है, हमारी जनता इससे काफी नाखुश है । हम कहते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ...

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती ज्योति देवी : तो मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि...

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री प्रेम शंकर प्रसाद जी ।

श्रीमती ज्योति देवी : जनता ने हमें यह भरोसा दिया है कि आप हमारा सर्वांगीण विकास करेंगे । अगर विकास नहीं हो रहा है, तो हम अपने अंदर टटोलकर देखें कि कहीं हमारे अंदर तो मनोवृत्ति की कमी नहीं है, जो हम सही से काम नहीं कर पा रहे हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य श्री प्रेम शंकर प्रसाद जी, आपका समय मात्र पांच मिनट है ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले तो मैं अपनी बैकुण्ठपुर विधान सभा क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं साथ ही अपने जिला के जो भी शुभचिंतक हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं सबसे पहले सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट नल-जल योजना है, उस पर बोलना चाहता हूं । सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल-जल योजना, इसमें कितनी घोर अनियमितता चल रही है, हमको लगता है कि हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो । आप क्षेत्र में चले जाइये, तो हर जगह जहां भी पाईप बिछाया गया है, वहां पर गड्ढा है । कोई ऐसा इलाका नहीं है, जहां इसमें अनियमितता नहीं पायी गयी हो । सरकार के नियम में दिया गया है कि जहां भी पाईप बिछाने के लिए गड्ढा करना है, वहां फिर से रोड को

पुनर्स्थापित करना है, पी0सी0सी0 करना है, डबल पी0सी0सी0 करना है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ । उसके बाद रख-रखाव की बात है, आये दिन पेपर में आपने देखा होगा कि गोपालगंज में हुआ है, मोतिहारी में भी हुआ है, पानी भरता है, टंकी फट कर गिर जाती है, उसका स्ट्रक्चर गिर जाता है । पता नहीं सरकार का ध्यान कहां है, जबकि यह सरकार की मुख्य योजना है, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है । उसके बावजूद भी रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है । महोदय, इसके पहले जो भी काम हो रहा था पी0एच0ई0डी0 का नल-जल में, वहां जी0आई0 पाईप लगता था, अब प्लास्टिक का पाईप लग रहा है, जिसकी वजह से पाईप फट जा रहा है । तीन-चार महीने भी यह योजना नहीं चल रही है और धराशायी हो जा रही है । महोदय, यह योजना कई वार्डों में अभी तक चालू भी नहीं हुई है । हमारे गोपालगंज जिला में, हमारे बैकुण्ठपुर विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसे वार्ड बाकी हैं, जहां नल-जल योजना अभी तक चालू भी नहीं हुई है । उसके बाद सरकार का प्रोजेक्ट था कि इस योजना से हर घर में पानी जायेगा, सब लोग स्वस्थ होंगे, पानी पियेंगे, लेकिन हकीकत है कि इस पानी से गाय-भैंस धोयी जाती हैं, गाड़ी धोयी जाती है, खेत की पटौनी होती है । यह स्थिति है सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की । मैं सरकार का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस पर एक टीम गठित करे, टीम गठित करके इस योजना को सुदृढ़ करे ताकि गरीब जनता के पास इसका लाभ पहुंच सके । दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आंगनबाड़ी की बात करना चाहता हूं । महोदय, हमारे यहां आंगनबाड़ी की स्थिति, हमारे जिला में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं, जहां सी0डी0पी0ओ0 नहीं है । हमारे गोपालगंज जिला में बहुत ऐसे ब्लॉक हैं जहां सी0डी0पी0ओ0 नहीं है, बी0डी0ओ0 को चार्ज दिया गया है या सी0ओ0 को चार्ज दिया गया है । बी0डी0ओ0 के पास डेवलपमेंट का इतना वर्क रहता है कि साथ-साथ वह दोनों काम नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंगनबाड़ी के जो भी सेंटर हैं, वह सुचारू रूप से नहीं चल पाते हैं, उनकी देखरेख नहीं हो पाती है । मैं सरकार का ध्यान उस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं । पहले टी0एच0आर0 के माध्यम से लाभुकों के पास पैसा पहुंचता था, सरकार का वह माध्यम अच्छा था । लेकिन टी0एच0आर0 का जो अब माध्यम आया है उससे किसी भी लाभुक को पैसा नहीं जाता है, जिसकी वजह से उसमें घोर अनियमितता होती है । माननीय महोदय ने जो बताया वह सही बताया, हमारे यहां भी हर आंगनबाड़ी सेंटर से कमीशन लिया जाता है । महोदय, अब आप बताइये कि जिस सेंटर से कोई तीन हजार रुपये कमीशन दे, सरकार पैसा दे रही है गरीब लाभुकों को खिलाने के लिए और वहां लोग सेंटर से पैसा लेते हैं ।

सभापति(श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, आपका समय मात्र दो मिनट बचा है ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो भी इनकी योजनायें हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, केवल पेपर-पेन पर हैं, धरातल पर नहीं हैं । इनके पास योजनायें बहुत हैं, वित्तीय वर्ष में पैसा बहुत देते हैं, लेकिन उस चीज को सही ढंग से, सही तरीके से पेश नहीं किया जाता है, सही तरीके से उस पर अमल नहीं हो पाता है । महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आंगनबाड़ी की जो भी सेविका और सहायिका हैं, उनका मानदेय बढ़े । मानदेय के साथ-साथ जो, एक तो सी0डी0पी0ओ0 लूटते हैं, उसके साथ-साथ एक सुपरवाईजर को भी सरकार ने बहाल कर दिया लूटने के लिये । पहले कमीशन दो हजार लगता था, अब सुपरवाईजर आ गया है तो तीन हजार कमीशन हो गया है, महोदय । यह जाँच का विषय है, इसकी जाँच की जाय और जहां भी आंगनबाड़ी सेंटर भवन नहीं हैं, वहां भवन का निर्माण किया जाय । कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है, जहां गैर-मजरूआ सरकार की जमीन नहीं है, उस जमीन पर भवन का निर्माण किया जाय । हमारे बैकुण्ठपुर क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं, जहां आंगनबाड़ी भवन विहीन हैं । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाय । जय हिन्द । जय भारत ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, श्री आबिदुर रहमान जी । आपका समय छः मिनट है ।

श्री आबिदुर रहमान : माननीय सभापति महोदय, यह सदन जब से इसकी ईंट की शुरूआत हुई, तब से हमारे परिवार के कोई-न-कोई सदस्य चुन कर यहां आते रहे हैं और मैं धन्यवाद राहुल जी को और सोनिया जी को करता हूँ । मैं धन्यवाद उस जनता को, अररिया के वासियों को देता हूँ, जिन्होंने मुझे जिताकर भेजा है और मैं सरकार के विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूँ । सात निश्चय के तहत जो हर घर नल योजना स्कीम चलाई गई, इसको हमलोगों ने अमली जामा भी पहनाया है, यह फ्लॉप साबित हुआ और इतना ही नहीं, बम्बई से, हैदराबाद से और दिल्ली से जितने भी ठेकेदार थे, सब को लाकर यहां पर बैठा दिया गया । जितने भी नौजवान थे, उनलोगों को यहां पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और इतना ही नहीं, यहां के लोगों को काम दिया जाता ताकि उन लोगों को रोजगार ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती । आज इसी के तहत चाहे वह मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे यहां हो, चाहे वह मुंगेर में हो, जितने भी मीनार बनाये गये, आज वह मीनार लेट गये, सो गये उस मीनार का कोई भी उपयोग नहीं हुआ । मकड़ी के जाल की तरह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पी0एच0ई0डी0) के जाल को बिछा दिया गया, आज भी उसको सात निश्चय के तहत, जहां भी रोड चौड़ीकरण हुआ, मकड़ी के जाल

की तरह उस स्कीम को उठा कर फेंक दिया गया । आज भी गांव में चले जायं और पूछें किसी से 75 प्रतिशत जहां भी स्कीम हैं, सारी फेल हैं । मैं एफिडेविट कर के देता हूँ, एक गिलास पानी मांगने पर पानी भी नहीं मिलता है । आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और यह करते हैं । जहां तक आंगनबाड़ी का सवाल है, वह तो आमतौर पर सरकार का कमाऊ बेटा है, कमाऊ बेटा से ही पटना से लेकर जिला तक सब की कमाई होती है, वह कमाई सब लोग मिलकर खाते हैं । उसी तरह से भवन निर्माण का, आज भी जितने स्कूल हैं, आज भी हमारे क्षेत्र में 20 स्कूल ऐसे हैं, जहां आसमान की छत के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं । बातें तो बहुत लंबी-लंबी करते हैं लेकिन आज भी उठाकर देखें पूरे बिहार में 300 स्कूल ऐसे हैं जो कि भूमिहीन हैं, भूमि है लेकिन मकान नहीं है । आज भी ऐसे-ऐसे स्कूल बने हुए हैं, जहां पर मकान बने हुए हैं, ढांचा बना हुआ है लेकिन बच्चे उसमें पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि कब उसके ऊपर गिर जाय । जब भूकम्प आयेगा, वे मरने से वंचित नहीं रह सकते हैं और इतना ही नहीं, आज बाढ़ हमारे क्षेत्र में दस्तक दे चुकी है अप्रील के पहले सप्ताह से । आज तक कोई विचार नहीं हो रहा है । यह माइनॉरिटी का ऐरिया है, आज हम लोग चाहे बांडो पोखरिया के पुल का मामला हो, चाहे मेहसा कोल घाट के पुल का मामला हो, चाहे समता का मामला हो, चाहे मोहनपुर का मामला हो, सारी फाईल को पेंडिंग में डाल दिया गया है, क्योंकि यह माइनॉरिटी का ऐरिया है, इसलिए इसकी अनदेखी की जा रही है और तरह-तरह से अनदेखी की जा रही है । जहां तक बांध, पुल, पुलिया का सवाल है, आज नहीं खड़ी होंगी, तो लोग तीन महीने तक परेशान रहेंगे ।

...क्रमशः...

टर्न-21/सुरज-संगीता/15.03.21

...क्रमशः...

श्री आबिदुर रहमान : यह सवाल आज अगर खड़ा नहीं होगा तो लोग तीन महीने तक परेशान रहते हैं, खड़े-खड़े सोते हैं, खड़े-खड़े लैट्रिन-बाथरूम किया करते हैं । इतना ही नहीं इतनी परेशानी के साथ चाहे वह अररिया टाउन में हो, 11 नंबर 12 नंबर वार्ड में, बेलवा में और यहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं, 3 महीने तक रोड के बगल में अपना बसेरा किया करते हैं । ऐसे-ऐसे लोग हैं, कम से कम 3 दर्जन लोग ऐसे हैं जिनके मकान जमीन के साथ नदी में विलीन कर गये लेकिन आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ उन्होंने दौड़कर छोड़ दिया और उन्होंने अपने साथ में जो भी किया और ये बड़े लम्बे-लम्बे दावे करते हैं,

इन लोगों की पकड़ यहां से जिले तक है । वे अपनी अगुआई किया करते हैं और कहीं कुछ काम धाम तो है नहीं और सभापति महोदय, हमारी बातों को सुनिए हम काफी परेशान रहते हैं और यह इलाका पश्चिमांतर इलाका है, बाढ़ पीड़ित इलाका है और छोटी-छोटी नदियां हमलोगों को परेशान किए हुए है ताकि हमलोग रोड के किनारे में रहते हैं...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय दो मिनट मात्र बचा है ।

श्री आबिदुर रहमान : हुजूर, और हमें थोड़ा सा समय दिया जाय । इतना ही नहीं हमलोगों का वश चले तो आपके सामने, पूरे सदन के सामने, पूरी आवाम हम आत्महत्या भी कर सकते हैं । अगर इस बार हमारा काम नहीं हुआ, हम तरह-तरह से परेशान हैं । बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं । जय हिन्द, जय बिहार, जय बिहार निवासियों ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, मुसाफिर पासवान जी । माननीय सदस्य, मुसाफिर पासवान जी, आपका समय तीन मिनट है ।

श्री मुसाफिर पासवान : सभापति जी, हम बहुत देर से सुन रहे थे । कल्याण विभाग पर सुने, समझे, बताये । आपका जो भी कुछ सुनना या पक्ष-विपक्ष ये दोनों आज भी अध्यक्ष जी के सामने बोले कि कल्याण विभाग में सबकुछ आता है । इसमें फूड कॉरपोरेशन भी आता है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग का परसेंट जाता है, लेवर जिसमें काम करता हो और सिर्फ बूढ़ा-बूढ़ी को कपड़ा दे देने से और उनको भेज देने से काम नहीं चलेगा । बिहार में 38 जिले हैं । 38 जिले में 16-16 मतलब जिला में एक ब्लॉक है और रेलवे से लेकर और गोदाम से लेकर और ट्रक पर लेकर एक-एक जिला में 6-6 हजार आदमी रहते हैं और उनको जाकर देखिए एक भी बीमारी नहीं हुई है । ये सब लोग मुंह में बांधे हुए हैं । अड़तीसों जिला में घूम आइए किसी के मुंह में नहीं बंधा हुआ है क्योंकि गर्मी खाता है वह, हुजूर और कुछ नहीं होता है उसको तो सबसे पहले हमारे गरीब आदमी की शादी ब्याह सबकुछ करा दिए, उनको वृद्धा पेंशन दे दिए, सबकुछ दे दिए लेकिन वह गरीब आपको घर तक खाना पहुंचाने का काम करता है ऑल इंडिया में, अठाइसों राज्य में और एक बिहार है, इसको आप चालू करवा दीजिए जबकि गरीब आदमी मारा जा रहा है, देह पर उसके कफन नहीं है, 50 किलो का बोरा ढोते-ढोते मारा जा रहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो । महोदय, आपसे हमारा निवेदन है कि बिहार हमारा राज्य है, हमको पहले यहां से स्टेट फूड कॉरपोरेशन, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का देखा जाय ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य संजय गुप्ता जी । माननीय सदस्य संजय गुप्ता जी । माननीय सदस्य संजय गुप्ता जी ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, डॉक्टर सत्येन्द्र यादव जी । एक मिनट आपका समय है ।

डॉक्टर सत्येन्द्र यादव : मैं समाज कल्याण विभाग द्वारा जो प्रस्तुत बजट है, उसके कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं । यह बात सर्वविदित है कि सत्ता पक्ष का दावा और सरकार का दावा कि बिहार में पूरा का पूरा स्वर्ग हो गया है, सबकुछ विकास के रास्ते पर है, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मेरी नजरों में और विपक्ष की नजरों में निश्चित रूप से बिहार के अंदर न कोई विकास हुआ है न कोई स्वर्ग आया है बल्कि मैं अंत में यह बात कहूंगा कि समाज कल्याण पर जो चर्चाएं चल रही हैं, यह किसी से छिपा नहीं है कि समाज के हाशिए पर खड़े लोग, विधवा, विकलांग और वृद्धा लोग जिनको हम 400 रुपया पेंशन देते हैं, आज एक कप चाय का दाम 5 रुपया है, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने नि:शक्त लोगों को सिर्फ 400 रुपया परमंथली पर रखना चाहते हैं । मेरी साफ समझ है कि अगर मानवीयता के प्रति आपको दया है तो 400 रुपया को 2000 रुपया में कल्याण मंत्री जी आप बदलिए । 2000 रुपया विधवा, विकलांग को पेंशन देने का इंतजाम कीजिए । दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कबीर अन्त्येष्टि की चर्चा हो रही है, सब लोग जानते हैं 3000 रुपया कबीर अन्त्येष्टि दाह-संस्कार के लिए दिया जाता है लेकिन 1000 रुपया में 500 बी0डी0ओ0 और 500 मुखिया की जेब में रह जाता है । 2000 रुपया में लकड़ी नहीं मिल सकती, कफन नहीं मिल सकता...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : आपका समय समाप्त हो गया है, कृपया आप बैठ जायं ।

डॉक्टर सत्येन्द्र यादव : मंत्री महोदय, 10 हजार रुपया कबीर अन्त्येष्टि के लिए दिया जाय...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, श्री संजय गुप्ता जी ।

डॉक्टर सत्येन्द्र यादव : सभापति महोदय, इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र की चर्चा हो रही है, सब लोग जानते हैं...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य, संजय गुप्ता जी ।

डॉक्टर सत्येन्द्र यादव : चर्चा है नीचे से ऊपर तक, आंगनबाड़ी सेविका से लेकर मंत्री तक लूट की राशि का बंटवारा होता है...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : माननीय सदस्य ई0 शशि भूषण सिंह जी ।

डॉक्टर सत्येन्द्र यादव : और इसीलिए हम चाहते हैं कि बिहार के विधायकों को भी...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : कृपया बैठ जायं, आपका समय समाप्त हो गया है ।

डॉक्टर सत्येन्द्र यादव : मॉनीटरिंग के अंदर इन्वॉल्व किया जाय, जिससे इस करप्शन को रोका जा सके ।

ई0 शशि भूषण सिंह : माननीय सदन के अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी तथा माननीय सदस्यगण बिहार विधान सभा, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूं । आज दिनांक 15.03.2021 को सदन में अपना वक्तव्य देने के लिए समय देने हेतु मैं अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं । साथ ही साथ आदरणीय लालू जी जो बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उनको मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने मुझे आर0जे0डी0 का टिकट देकर इस विधान सभा में भेजने का कष्ट किया और मैं आज सुगौली की जनता को भी नमन करता हूं जिन्होंने मुझे इस विधानसभा में भेजने का कार्य किया । उनके प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । आज मैं परिवहन के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं । बिहार राज्य में बिहार सरकार के द्वारा ही अभी चौदह चक्का, अठारह चक्का, बाईस चक्का सबों का जो परमिट दिया गया, पास किया गया और कुछ ही दिनों के बाद उसका परिचालन बंद कर दिया गया जिसके चलते 2 लाख परिवार रोड पर हैं और एक ट्रक के साथ 10 मजदूर कमाते हैं और कम से कम 20 लाख मजदूर रोड पर हैं, उनके जीवनयापन का आपके यहां कोई साधन नहीं है जबकि आप ही के द्वारा सारे उन ट्रक मालिकों को परमिट दिया गया और उन्होंने कर्जा लेकर ट्रक की खरीदारी की और बनवाया और आज उनके दरवाजे पर लगा हुआ है जिसके चलते वे लोग भुखमरी की कगार पर हैं और 20 लाख जनता भी भुखमरी की कगार पर हैं । साथ ही साथ मैं नल-जल योजना पर बोलना चाहता हूं । श्रीमान से अनुरोध करता हूं कि किसी भी जिले में, किसी भी ब्लॉक में कम से कम एक कमेटी बनाकर दिखवा लिया जाय कि जितनी भी नल-जल योजना हैं एक भी प्रखंड में सही सलामत हो तो उसके लिए जो भी हमें कष्ट दिया जायेगा, मैं सहने के लिए तैयार हूं । एक भी प्रखंड में नल-जल योजना सही नहीं है और साथ ही साथ हमारे जो वार्ड के सदस्य हैं, वे मरने की कगार पर हैं कि वार्ड सदस्य के नाम पर वह नल-जल योजना स्वीकृत किया गया और उसके पैसे का दोहन करके दूसरे को दे दिया गया । कम से कम सरकार के पास इतने इंजीनियर हैं कि कम से कम सभी इंजीनियरों को अगर एक-एक वार्ड का दे दिया जाता कि तुम लोग नल-जल लगाओ और उससे जो भी आमदनी होगी उसका समायोजन होगा तो कम से कम उतने इंजीनियर तो हमारे राज्य में काम करने जाते और आज

इंजीनियर की यह स्थिति है कि घास गढ़ने के लिए तैयार है और गांव में कम से कम क्षेत्र भ्रमण के दौरान...

सभापति (श्री प्रेम कुमार) : दो मिनट मात्र समय बचा है आपका ।

ई0 शशि भूषण सिंह : क्षेत्र भ्रमण के दौरान कम से कम 200 इंजीनियरों की हमसे भेंट हुई जो गाय खिला रहे हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं मॉल में काम कर रहे हैं, कहीं दुकान में काम कर रहे हैं । जब हमलोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे उस समय हमलोगों के दिल में कितना उत्साह बढ़ता था कि इंजीनियर होकर कुछ देश का काम करेंगे ।

...क्रमशः...

टर्न-22/मुकुल-राहुल/15.03.2021

क्रमशः

ई0 शशि भूषण सिंह: लेकिन आज इस राज्य में इंजीनियरों की तबाही देखने को मिल रही है । मैं चाहता हूं कि कम से कम इंजीनियरों को सही जगह पर लगाया जाए । बिहार में इतना कम है कि बाहर के लोगों को लाकर यहां पर काम करवाया जाता है । हम चाहते हैं कि इन्हीं इंजीनियरों को बेसिक कांट्रेक्ट पर लेकर काम कराया जाय तो ये अच्छा काम करेंगे और इससे बिहार का विकास होगा और बिहार का पैसा बिहार में ही रहेगा । देखने को मिलता है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करते हैं उनके ऊपर बी0डी0ओ0 को लगा दिया जाता है जिनको कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, उसके काम को देखने के लिए बी0डी0ओ0 को लगा दिया जाता है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आपका समय हो गया है ।

ई0 शशि भूषण सिंह: सभापति जी, हमें एक मिनट का समय दिया जाय ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): माननीय सदस्य, श्री सुर्यकान्त पासवान जी ।

ई0 शशि भूषण सिंह: सभापति जी, एक मिनट और समय दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि कम से कम इंजीनियर पर ध्यान देकर...

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आप कृपया बैठ जायं, आपका समय समाप्त हो गया है । सुर्यकान्त पासवान जी आपके पास एक मिनट का समय है ।

श्री सुर्यकान्त पासवानः सभापति महोदय, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, सरकार एक तरफ सभी वर्गों के समेकित विकास की बात करती है मगर दूसरी तरफ इतनी महंगाई में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से निम्न मानदेय पर सेवा ले रही है । मैं मांग करता हूं कि सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 21 हजार और 18 हजार

किया जाय । महोदय, पिछले तीन महीनों में महंगाई डेढ़ गुना तक बढ़ी है मगर राज्य के वृद्धजनों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई है । महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल इस राशि को बढ़ाया जाय । महोदय, एल0एन0एम0यू0 के एफिलिएटेड कॉलेज के छात्राओं को वर्ष 2018 से अभी तक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ नहीं मिला है । मैं सरकार से अतिशीघ्र मांग करता हूं कि इन कॉलेज के छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाय । महोदय, राज्य सरकार ने दलितों-महादलितों के विकास के लिए उन तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए विकास मित्र को बहाल किया मगर क्या हालत है, ये लोग कैसे घर-परिवार चलाते हैं सरकार कभी इस पर विचार की है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि विकास मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाय । महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से बखरी प्रखंड से सरकारी बस सेवा की शुरुआत करने की मांग करता हूं । महोदय, नल जल योजना की बात करें ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आपका समय समाप्त हो गया है कृपया आप बैठ जायं । श्री विजय कुमार मण्डल ।

श्री सुर्यकान्त पासवान: माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बेगूसराय जिला सुधाग्राम से नल जल योजना का कार्य शुरू किया था लेकिन आज उसकी हालत मरणासन्न पर है ।

सभापति (श्री प्रेम कुमार): आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री सुर्यकान्त पासवान: मैं आसन के माध्यम से मांग करता हूं कि बेगूसराय जिला के अन्तर्गत नल जल योजना का...

श्री विजय कुमार मण्डल: सभापति महोदय, मैं दिनारा विधान सभा, 210 की महान जनता को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे यहां पर भेजने का काम किया । मैं अपने नेता और इस देश के गरीबों के मसीहा, दलित-शोषितों को जगाने वाले नेता आदरणीय लालू यादव जी के चरण छूता हूं और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे समय दिया । मैं शुरुआत वीर कुंवर सिंह, डॉ0 राम सुभत्स सिंह, बाबू जगजीवन राम और शिवपूजन शास्त्री की धरती को नमन करता हूं । शेरशाह सूरी को नमन करता हूं जहां से शाहबाद की धरती से उन लोगों ने देश की सेवा करने का काम किया । माननीय सभापति महोदय, मैं शुरुआत करता हूं अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की उस उक्ति के साथ कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा था कि बिहार में एस्टीमेट घोटला हो रहा है और वह एस्टीमेट घोटाला कहां खड़ा है । इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि अभी बिहार में जो स्थिति है, जो भवन बने हैं, भवन में जो अवैध कब्जा है, जिनको-जिनको नहीं रहना चाहिए

उनको बड़े-बड़े मकान दिये जाते हैं और जो माननीय सदस्य सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों, रोड पर घूम रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किस स्थिति में यह सब हो रहा है । हुजूर, जो एम0एल0ए0 का फ्लैट बनाया गया है उसमें एम0एल0ए0 फ्लैट, आर ब्लॉक और एम0एल0ए0 क्लब तीनों का एक साथ टेंडर किया गया जिसके चलते बिहार में यह स्थिति बनी हुई है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं पहले आर ब्लॉक का तोड़ा जाता, यहां बनकर जब तैयार हो जाता, यहां के विधायकों को दे दिया जाता, एक ही बार तीनों को तोड़कर यह सारी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि इसमें एस्टीमेट घोटाला है और जो मांझी जी ने सवाल उठाया वे यहां पर हैं और उसमें इसकी बू आ रही है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि साढ़े चार सौ करोड़ की लागत से विधायकों का जो आवास बन रहा है उसमें जो स्टीमेट घोटाला हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए । बेली रोड़ पर जो संग्रहालय बनाया गया, बेशकीमती जमीन पर वह संग्रहालय बनाया गया है, उस जमीन पर बिहार की गरीब जनता के लिए कोई मार्केट बनाकर उनको रोजगार करने के लिए दिया जाता तो उससे बिहार की गरीब जनता को लाभ होता । महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो भवन निर्माण हो रहा है उसमें जहां-जहां भवन का निर्माण हुआ उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ । महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो स्कूल की बिल्डिंग बनी हैं वे सब ढह रही हैं, बिहार में कहीं भी स्कूल में बिल्डिंग नहीं है । बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही है ? जहां से हमारे गरीब बच्चे पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, लेकिन कहीं भी स्कूल में बिल्डिंग नहीं हैं और यहां बिहार को नया बिहार बताया जा रहा है । महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि परिवहन विभाग के द्वारा जो ओवरलोडिंग हो रही है जिससे सड़कें टूट रही हैं इस पर सरकार का क्या ध्यान है ? शिवसागर में जो टोल प्लाजा है वहां पर खुलेआम रंगदारी की जाती है और वहां पर सत्ता संरक्षित लोग बैठकर ट्रकों को रोक देते हैं और कुछ देर के बाद उन्हीं ट्रकों से पैसा लेकर फिर उसको पार करा दिया जाता है, ये क्या हो रहा है महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं ? महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में स्कूलों की जो स्थिति है, नागेश्वर पाठक उच्च विद्यालय सईसा जहां उसकी 32 एकड़ जमीन है, 50 लाख रुपया उसके फंड में है, लेकिन वह बिल्डिंग नहीं बन रही है और उसमें आज तक दिनारा में बलदेव उच्च विद्यालय है, हमारे सांसद हैं माननीय चोबे जी उन्होंने पैसा दिया बिल्डिंग बनाने के लिए और वह बिल्डिंग स्कूल को देने के पूर्व ही ढह गई, यह स्थिति है । महोदय, आपके

माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है । महोदय, पहले जो सिंचाई विभाग था उसके किनारे-किनारे जहां अनुमंडल कार्यालय था, उन लोगों के अनुमंडल में रहने के लिए था । विक्रमगंज का जो अनुमंडल कार्यालय है वह आज तक नहीं बना । विक्रमगंज अनुमंडल बहुत पहले बना था, लेकिन आज तक कार्यालय नहीं है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, सिंचाई विभाग का डाकबंगला कई जगहों पर था, जनगरा में था, नोखा में था फूली में था, मनोहरपुर में था, लेकिन आज सब ढह गया और आज तक वह नहीं बन रहा है । महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसका निर्माण किया जाय और वहां पर अधिकारियों को बैठाया जाय । महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बाल विकास परियोजना में जो घोटाला हो रहा है, बच्चों के पैसों को लेकर और कई सदस्यों ने इस सवाल को उठाया है इस पर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए । हमारे क्षेत्र दिनारा में, सूरजपुरा में और दावत में आज तक सी0डी0पी0ओ0 का पद खाली है वहां कोई नहीं है, दूसरा चला रहा है वहां पर पदस्थापित करने की कृपा की जाय । महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो कोचस का बस स्टैंड है वह अतिक्रमित है उसके बगल में बड़े-बड़े मकान बना लिए गए हैं उसकी जमीन पर, अगर उस जमीन को खाली करा दिया जाय तो वहां पर परिवहन विभाग का बड़ा स्टैंड खड़ा किया जा सकता है । महोदय, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय और उस पर बस स्टैंड का निर्माण कराया जाय । महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दिनारा विधान सभा में नटवार है जहां के व्यावसायियों ने तीन एकड़ जमीन दी है । महोदय, दिनारा एन0एच0 पर बसा हुआ है वहां पर दोनों हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है वहां पर उसका निर्माण कराया जाय ।

क्रमशः

टर्न-23/यानपति-अंजली/15.03.2021

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार मण्डलः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बिहार में यह हो रहा है इस पर रोक लगाई जाय और विकास की कड़ी को आगे बढ़ाया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब आप समाप्त कर दीजिए और शांति बनाये रखिये ।

श्री विजय कुमार मण्डल: महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से परिवहन विभाग में सुधार की मांग करता हूं और जो ओवर लोडिंग हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता हूं । महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉ॰ राम मनोहर लोहिया, जगदेव प्रसाद और विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने समाज में नई संरचना देने का काम किया और श्री लालू प्रसाद ने बिहार में गरीबों को जगाने का किया इसके लिए मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री मुरारी मोहन झा ।

श्री मुरारी मोहन झा: अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा भवन निर्माण के कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं बतलाना चाहता हूं महोदय, बिहार के विकास में खास कर जब से यह एन0डी0ए0 की सरकार, जब से सत्ता में आई है उस समय के कार्यकाल का और वर्ष 2005 से लेकर 2015 तक के कार्यकाल का अगर अध्ययन किया जाय तो स्वयं पता लग जाता है कि आज जो ये लोग आरोप लगाते हैं, आरोप-प्रत्यारोप करते हैं इनको स्वयं समझ आ जाता होगा । आज बिहार के किसी भी तरफ, किसी भी जिले में अगर निकल जायं तो चाहे वह सड़क का मामला हो, चाहे भवन का मामला हो चारों तरफ विकास स्वयं ही दिखता है । महोदय, बिहार राज्य में विकास के वर्तमान दौर में एन0डी0ए0 की सरकार ने विकास की अवधारणा के तहत अपनी परिस्थिति एवं पर्यावरण के अनुकूल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर नया बिहार बनाने के सरकार के निर्णय को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और विकास के लिए हरेक दौर में, प्रत्येक सभ्यता की उपलब्धियों को उस दौर के भौतिक और आधारभूत संरचना के निर्माण तभा भौतिक विकास से मापा जाता है । महोदय, हम इतिहास पर अगर नजर डालें तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय की आधारभूत संरचना अवशेष आज भी विराजमान हैं । महोदय, आधारभूत संरचनाएं किसी भी सभ्यता के महत्वपूर्ण तत्व हैं । महोदय, आधारभूत संरचनाएं किसी भी सरकार के विकास के दृष्टिकोण का परिचायक होती हैं । महोदय, बिहार राज्य प्राचीन काल से ही आधारभूत संरचनाओं के यथा भवन और वास्तुशिल्प के विकास का साक्षी रहा है और इन्हीं सब कारणों से अपनी गौरवशाली और शानदार परंपरा को नित्य आगे बढ़ाने के लिए भवन निर्माण विभाग अपनी पूरी ताकत के साथ प्रत्येक दिन नये आयाम गढ़ रहा है । महोदय और यही कारण है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा कई महत्वपूर्ण एवं वस्तुविद्

दृष्टिकोण से आधुनिक भवनों का निर्माण किया गया है । उदाहरण स्वरूप सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, बिहार संग्रहालय अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र, विधान मंडल भवन, सचिवालय का विस्तारीकरण, सरदार पटेल भवन और पटना उच्च न्यायालय ये सब ताजा उदाहरण हैं । महोदय, हमारी सरकार की मान्यता है कि भवन महज ईंट, सीमेन्ट, सरिया और बालू से बनी संरचना मात्र नहीं होती वरन् भवन ऐसी संरचना होती है जो अपने वास्तुशिल्प की वजह से हमारे मस्तिष्क को झकझोरती है । भवन नये विचारों के सृजन के लिये हमें प्रेरित करता है । भवन हमारी जनता की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और सपनों को पूरा करने में मदद करता है । महोदय, हमारी सरकार का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि विभाग के अधिकतर भवन हरित भवन हो सकें और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जल-जीवन-हरियाली के मापदंडों पर खरा उतर सकें । महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 में सफलतापूर्वक किये गये कुछ कार्य जो निम्न प्रकार हैं, मैं उसको सदन को बतलाना चाहता हूं । जैसे 61 करोड़ की लागत से पटना में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज का निर्माण पूरा करा दिया गया है, 633 करोड़ की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सह खेल अकादमी का निर्माण किया गया है...

अध्यक्ष: अब संक्षिप्त कर लें ।

श्री मुरारी मोहन झा: जो ऐतिहासिक फैसला है । महोदय, 145 करोड़ की लागत से बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य किया गया है, 164.31 करोड़ की लागत से पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन भवन, परिवहन विभाग का वर्कशॉप एवं अन्य भवन का निर्माण जो एक ऐतिहासिक कार्य है महोदय । 83.40 करोड़ की लागत से पटना के शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के आवास का...

अध्यक्ष: अब बैठ जायं ।

श्री मुरारी मोहन झा: महोदय, 164 करोड़ की लागत से दरभंगा में तारामंडल का निर्माण, महोदय, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बिहार सरकार के द्वारा भवन निर्माण के द्वारा करवाया गया है । जो एक बहुत ही उदाहरण स्वरूप बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है । जय हिन्द ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग अपना पक्ष रखेंगे ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विभाग का मंत्री होने के नाते आपके समक्ष बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं जो 2007 से पहले कल्याण विभाग के अंतर्गत आता था । 2007 के बाद समाज कल्याण के रूप में यह स्थापित हुआ और तब से यह अपने विभिन्न क्षेत्रों में खासकर के जो समाज में वृद्धजन हैं, गरीब हैं, विधवा हैं,

दिव्यांगजन हैं, कुष्ठ रोगी हैं, एच0आई0वी0 पॉजिटिव से ग्रसित हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, कई बीमारियों से असहाय हैं, बेसहारा हैं ऐसे लोगों के लिये यह विभाग कार्य करता है और यह मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी ने ऐसे विभाग का सिर्फ कार्य करने का नहीं बल्कि सेवा करने का अवसर मुझे दिया है । हम तमाम लोग जब समाज कल्याण विभाग की चर्चा होती है तो काम अनेकों हैं जिसकी चर्चा हम कम समय में सारी योजनाओं का नहीं बता सकते हैं लेकिन जो हमारे सामने बैठे हुए प्रतिपक्ष के साथी हैं वे मात्र दो बिंदु पर ही विशेष रूप से चाहे वह विभिन्न प्रकार की पेंशन हो या आंगनबाड़ी केन्द्र से जुड़ा हुआ मामला हो ।

...क्रमशः...

टर्न-24/सत्येन्द्र/15-03-21

...क्रमशः...

श्री मदन सहनी, मंत्री : इसके अलावा भी यहां बहुत सारा काम है, इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पेंशन के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे कई सदस्यों ने विस्तार से जो विभिन्न तरह की पेंशन हैं जिसमें हमारे माननीय सदस्य अमरेन्द्र पाण्डेय जी, सुश्री श्रेयसी सिंह जी ने विस्तार से उन पेंशन के बारे में बताया है । महोदय, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, वर्ष 2007 से पहले यह विभाग अस्तित्व में नहीं था, 2007 से लेकर 2021 तक का जो सफर है पेंशन का, उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो महोदय, 2007-08 में कुल पेंशनधारियों की संख्या 12 लाख 30 हजार थी वहीं आज 94 लाख 59 हजार हमारे कुल पेंशनधारी हैं और आपको हमें बताने में खुशी हो रही है...

श्री सत्यदेव राम : मंत्री जी, यह भी बतलाईयेगा कि कितने लोगों को पेंशन मिल रहा है ?

अध्यक्ष: बैठ जाईए सत्यदेव जी, आप पुराने सदस्य हैं, बिना आसन की अनुमति से आप डायरेक्ट मंत्री से प्रश्न न पूछिये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जरूरत महसूस की कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरूआत हो और उसकी शुरूआत हुई । महोदय, उस योजना के तहत 25 लाख लोगों को इसका लाभ दिया गया है और हमलोगों ने डी0बी0टी0 के माध्यम से चूंकि जब से यह व्यवस्था लागू हुई है, सिर्फ पेंशन में ही नहीं बल्कि अन्य किसी भी योजना में चाहे वह आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हो या डी0बी0टी0 के माध्यम से हो और चाहे वह किसानों के हित में हो या अन्य जो हमारे महिलाओं को जनधन योजना के तहत बैंक में खाता खुला, जितनी भी योजना में डी0बी0टी0 लागू किया गया तो अब सारे लोगों के खाते में राशि चली जाती है, चाहे वह सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के

हमारे साथी हों या गांव समाज में रहने वाले अन्य कोई भी राजनीति दल के लोग हों, किसी को पता नहीं चलता है कि उनके खाता में कब राशि चली गयी । इसी कारण लोगों को लगता है कि सरकार के द्वारा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिला रहा है लेकिन जो लाभार्थी हैं, वे लोग भी अब किसी के झांसे में आने वाले नहीं है जो बताते फिरेंगे कि हमारे खाता में राशि आ गयी है इसलिए हमारे साथियों को कभी कभी भ्रम हो जाता है। हमने अध्यक्ष महोदय बताया है कि हमारा सफर 2007-08 से शुरू हुआ 12 लाख से और आज हमलोग 95 लाख तक पहुंच चुके हैं 2021 में और यह क्रम जारी है । इसको हमलोग आगे भी हमारे साठ साल से ऊपर के आयु के जो भी वृद्ध होंगे, चाहे वे गरीब होंगे या अमीर होंगे, चाहे वह बी0पी0एल0 होंगे या ए0पी0एल0 होंगे, उनको हमलोग इस योजना से जोड़ने का काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्रम में ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप इधर बोलिये, समय कम है, बोलिये आप ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जो लॉक डाउन लगा, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ 85 लाख पेंशनधारियों के खाते में तीन माह की राशि एक साथ भेजने का काम किया है, 1025 करोड़ 77 लाख की राशि उन्होंने एक साथ डी0बी0टी0 के माध्यम से तीन माह के लिए राशि देने का काम किया, यह हमारी सरकार की गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता है । अध्यक्ष महोदय, जो हमारे गरीब बी0पी0एल0 के कमाऊ सदस्य हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, चाहे वह मृत्यु स्वाभाविक हो या दुर्घटना में हो, उनको हमारी सरकार 20 हजार रू0 उनके आश्रितों को देने का काम करती है। हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की, जो हमारे बी0पी0एल0धारी हैं जिनकी मृत्यु होती है तो 3 हजार रू0 उनके खाते में दी जाती है और प्रत्येक पंचायत में हमलोगों ने यह व्यवस्था की है कि पांच किस्त की राशि लगातार रहेगी और अगर किसी की मृत्यु होती है और एक किस्त भी राशि किसी को दे दी जाती है तो पटना से, मुख्यालय से उसकी दूसरी किस्त भेजने का काम हमलोग करते हैं और पांच किस्त की राशि हमेशा वहां जमा रहती है पंचायत के अंदर में । मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जो हमारे अन्तरजातीय विवाह करने वाले लोग हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए एक लाख की राशि दी जाती है और इस योजना के तहत हमलोगों ने 251 लोगों को इसका लाभ देने का काम किये हैं और जो दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है, इसके अन्तर्गत हमलोग 186 लाभुकों को इसका लाभ देने का काम किया है ।

अध्यक्ष: अब कन्कलूड कर लीजिये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं एक और जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है समाज कल्याण विभाग की, जो एक बुनियाद केन्द्र के रूप में स्थापित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसके अन्तर्गत अभी 51 जगह पर यह कार्यरत हैं, वहां जो गरीब लाचार व्यक्ति हैं, वृद्धजन है, दिव्यांगजन हैं, उनको अगर कान से सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई नहीं देता है और चलने फिरने में भी लाचार हैं तो उस जगह पर हमलोगों ने फिजियोथेरापिस्ट की व्यवस्था की है, जो एथेलमिक एक्सपर्ट हैं उनको हमलोगों ने वहां व्यवस्था किया है और वहां लोगों के आंख की जांच करके चश्मा देने का काम हमलोग करते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं उनका भी इलाज हमलोग करने का काम करते हैं, यह सारा काम हमलोग कर रहे हैं लेकिन यह अलग बात है कि इनको दिखाई नहीं देता है । मैं आपके माध्यम से सारे सदस्यों को जरूर यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल से लगातार बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसमें हमलोग भी इस बात से अपने आपको गर्व महसूस करते हैं कि इनके साथ हमलोगों को काम करने का अवसर मिला है। मैं सभी को अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आमंत्रित करूंगा, आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, पटना शहर में ही हमलोगों ने ऐसी व्यवस्था की है जहां लोगों को लाभ मिल रहा है । ईश्वर किसी को ऐसा संतान नहीं दे, बीमारी से ग्रसित वैसे बच्चे एक नहीं, दर्जनों बच्चों को हमलोग रखकर उनकी सेवा करने का काम करते हैं, जो बच्चे अपने से खा नहीं सकते हैं, नित्य क्रिया नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों की भी वहां व्यवस्था की गयी है । ऐसे मंद बुद्धि के भी बच्चे वहां रहते हैं और यह सारी व्यवस्था पटना के अंदर ही की गयी है । मैं आमंत्रित करूंगा, आप लोग चलिये और चलकर उसको देखिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है वह सदन को बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व में सात निश्चय पार्ट-2 के तहत वृद्धजनों के लिए जो आश्रय स्थल निर्माण की घोषणा की थी आज मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि इतने कम समय में हमलोग एक से डेढ़ महीने के अंदर में 139 स्थान पर वृद्धजन आश्रय स्थल की शुरूआत करने जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, अंत में चूंकि लगातार हमलोग देख रहे हैं कि सारे लोग को जब बोलने का मौका मिलता है तो शेरों शायरी और कविता पाठ करते हैं ।

अध्यक्ष: आप भी पढ़ेंगे, पढ़ लीजिये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: एक मिनट, तो मैं कविता पाठ या शेरों शायरी नहीं करूंगा बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ, मुझे ताज्जुब होता है आपको भी होता होगा, बिहार में इस बात की चर्चा

होती है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न क्षेत्र में इतना काम किये हैं और उसके बावजूद भी हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को दिखाई नहीं देता है तो मुझे भी ताज्जुब होता है कि 15 साल तक अध्यक्ष महोदय इन्होंने कैसे काम किया, उसी पर मैं दो लाईन आपके सामने में रखना चाहता हूँ।

(क्रमशः)

टर्न-25/मधुप/15.03.2021

अध्यक्ष : सुन लीजिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : दो लाईन कहना चाहता हूँ कि

''सड़क बनवा दूँगा, कहा होगा,
बिजली लगवा दूँगा, कहा होगा,
नरसंहार करवाना बंद करवा दूँगा, कहा होगा,
इलेक्शन की बात मत पूछो, इलेक्शन के नशे में था, कहा होगा ।''

बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण को प्रोसिडींग का पार्ट बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : रख दीजिए । दे दीजिए ।

(माननीय मंत्री का भाषण - परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर । माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण विभाग के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं 2021-22 के लक्ष्यों को सभा पटल पर रखने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ ।

महोदय, इस विधान सभा के माननीय 20 सदस्यों ने अपने सुझाव हमलोगों को दिये हैं, हमारे अभिभावक और जब हम कांग्रेस पार्टी में थे तो हमारे सी0एल0पी0 के लीडर विजय शंकर दूबे जी ने आज कटौती प्रस्ताव पेश किया है और हमारी नौजवान नेत्री सदस्या श्रेयसी सिंह जिसने इस देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, जिनको राष्ट्रपति ने अर्जुन अवार्ड देने का काम किया, उन्होंने भी अपना सुझाव दिया, उनका भी हम स्वागत करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार के लोगों ने 2005 के पूर्व 15 सालों के काल खंड में जैन परम्परा में वर्णित अवसर्पिणी काल को भी देखा है यानी कालचक्र का अवरोही भाग जिसमें वस्तुओं में हीनता आती है ।

लेकिन बिहार युग परिवर्तन का ध्वजवाहक रहा है । हमें वैशाली के गौरवशाली प्रजातंत्र की विरासत के साथ गौतम बुद्ध एवं भगवान महावीर की बौद्धिक चेतना से लेकर आचार्य चाणक्य की विद्वता के साथ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के कुशल प्रशासनिक क्षमता का धरोहर प्राप्त है ।

बिहार के इसी विरासत के मूर्त रूप, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः 2005 से युग परिवर्तन कर उत्सर्पिणी काल की नींव रखी गई ।

बिहार अब गंभीर चिंतन एवं अभिनव प्रयोगों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय Validation जंगलराज से सुशासन, बौद्धिक एवं शैक्षणिक पलायन की जगह Skill Development, जातीय उन्माद एवं हिंसा की जगह अभूतपूर्व मानव श्रृंखलाओं का निर्माण, सामाजिक भेदभाव की जगह समावेशी विकास, घोटालों की बाढ़ की जगह भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, सरकारी उदासीनता की जगह लोक सेवा को अधिकार का दर्जा देने वाला शासन तंत्र के रूप में पूरे देश के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन गया है ।

महोदय, इतिहास के किसी कालखंड का स्थापत्य कला उस काल की आर्थिक-सामाजिक एवं राजनीति व्यवस्था की सुदृढ़ता एवं शासन तंत्र की प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करता है ।

इस क्रम में हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक Town Planning, गुप्त काल, स्वर्ण युग एवं मुगलकाल शासक वर्ग के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप भव्य निर्माणों का काल रहा है ।

इस रूप से विगत पंद्रह सालों के माननीय नेता के नेतृत्व का यह काल बिहार के पुनर्जागरण, विकास, सुदृढ़ीकरण एवं संवर्द्धन का काल है ।

माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वर्तमान दौर में हम सतत विकास की अवधारणा के तहत पर्यावरण के अनुकूल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर नया बिहार बनाने के सरकार के निर्णय को फलीभूत करने हेतु प्रतिबद्ध हैं ।

भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार के सभी तरह के सरकारी कार्यालय एवं आवासीय भवनों के गुणवत्तापूर्ण और अत्याधुनिक तकनीक से समयबद्ध निर्माण करते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि प्राप्त करता रहा है ।

महोदय, पूरे देश की तरह बिहार में भी शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता सीमित है । पटना में भी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासों हेतु सीमित स्थल उपलब्ध है ।

लेकिन Innovation distinguishes between a leader and a follower. I feel enlightened and I feel proud that I have got a leader like Nitish Kumar who has got vision, who has got planning, who has created budget for the state like Bihar and who has created the future of this state.

अध्यक्ष महोदय, आवासों के निर्माण में विभाग भूमि के क्षैतिज प्रसार के बजाय उर्ध्वाधर विस्तार की नीति अपना रहा है, जिससे कि विभाग को अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता हो सकेगी ।

महत्वाकांक्षी गर्दनीबाग आवासीय योजना के तहत Minimum Space and Maximum Utilisation के तर्ज पर लगभग 57.97 करोड़ रूपये की लागत से मंत्रिगण हेतु आवास, 135.43 करोड़ रूपये की लागत से 432 ए टाईप आवास, 281.62 करोड़ रूपये की लागत से बी टाईप 752 आवास एवं 514.63 करोड़ रूपये की लागत से ऑफिसर्स इनक्लेव का निर्माण कराया जा रहा है ।

इसी तरह वर्तमान परिसरों के रिक्त होने से विभाग सरकार के अन्य परियोजनाओं के लिए वृहत् क्षेत्रफल की भूमि उपलब्ध करा सकेगा ताकि भविष्य में इन पर लोकोपयोगी संरचनाओं का निर्माण कराया जा सकेगा ।

महोदय, भवन निर्माण विभाग सात निश्चयों के माध्यम से बिहार में चतुर्दिक विकास हेतु मुख्यमंत्री के प्रयासों को निर्धारित समय सीमा के अंदर फलीभूत करने हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध है ।

सात निश्चय के तहत राज्य के 31 जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना होनी है । पूर्व से पूर्ण चार अभियंत्रण महाविद्यालय यथा बख्तियारपुर(पटना), सुपौल, जमुई तथा बांका के अतिरिक्त इस वर्ष भवन निर्माण विभाग के द्वारा कुल नौ यथा सहरसा, सासाराम, सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज, अररिया, कैमूर, बेगुसराय एवं पूर्णियाँ के अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेखपुरा, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण, मुंगेर, लखीसराय, मधुबनी, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, शिवहर, किशनगंज, जहानाबाद, अरवल, आरा, सिवान एवं नवादा में अभियंत्रण

महाविद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिन्हें दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में राज्य में कुल 10 पॉलिटेक्निक संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा तीन जिलों यथा खगड़िया, पश्चिम चम्पारण और भोजपुर में निर्माण कार्य प्रगति पर है । सात निश्चय के अतिरिक्त अन्य योजना मद से 21 राजकीय पॉलिटेक्निक पूर्व से निर्मित हैं । इस तरह कुल 31 राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण का कार्य भी विभाग के द्वारा कराया जा रहा है । कुल 66 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 21 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

पूर्व से पूर्ण 13 आई0टी0आई0 के अतिरिक्त इस वर्ष कुल आठ पुरूष आई0टी0आई0 यथा नालंदा, भेलारी(सासाराम), धमदाहा(पूर्णियाँ), शिवहर, मोहनियाँ(कैमूर), सहरसा सदर, नरकटियागंज(बेतिया) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं 37 आई0टी0आई0 के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

राज्य में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के क्रम में 7 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यथा बेगुसराय, मुँगेर, सीतामढ़ी, बक्सर, वैशाली, किशनगंज और सासाराम का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा 17 में कार्य प्रगति पर है ।

इस तरह से भवन निर्माण विभाग के द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ससमय निर्माण के लिए कार्य में तेजी लायी गयी है ।

विगत 15 वर्षों में भवन निर्माण विभाग ने भवनों के निर्माण में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही दृष्टि से उपलब्धियाँ हासिल की हैं । विभाग ने राज्य में जमीनी स्तर से लेकर वृहद परियोजनाओं (मेगा प्रोजेक्ट्स) का निष्पादन किया है और उत्तरोत्तर नवीन निर्माण कार्य कर रहा है । ये परियोजनाएँ तर्क, ज्ञान एवं स्वस्थ मस्तिष्क वाले समाज के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं । कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की एक झलक प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

महोदय, बिहार को महात्मा गाँधी के स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के बीजों का अंकुरण की धरती बनने का गौरव प्राप्त है । महात्मा गाँधी कहते थे My Life is my Message.

बापू की जीवनी, विचारों, बिहार में उनकी यात्रा एवं चम्पारण सत्याग्रह की प्रेरणा को समर्पित 7 एकड़ लगभग 78.93 करोड़ रूपया की लागत से 9675 Sq Meter Total built up area में State of Art Technology के समावेश से 6 मंजिला बापू टावर का निर्माण कराया जा रहा है । बापू के विचारों की तरह वास्तु कला का नायाब प्रयोग का स्मारक पूर्णरूपेण Copper Sheet से आवृत होगा ।

इसमें बापू के जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं से अपने आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने हेतु Orientation Center, High Speed glass elevators, ramp, exhibits एवं Souvenir Shop का प्रावधान है ।

महोदय, बच्चों एवं युवाओं में Scientific Temper का विकास किसी भी जागरूक एवं प्रगतिशील समाज के लिए अपरिहार्य है ।

बिहार हमारे पूर्व राष्ट्रपति, कर्मयोगी, वैज्ञानिक एवं विचारक ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करता रहा है ।

वे कहा करते थे कि You were born with wings. Don't Crawl. Learn to use them to fly and fly.....

कलाम साहब की भावना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु तथा उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में लगभग 397 करोड़ रूपया की लागत से साइंस सिटी का निर्माण कराया जा रहा है । इसके पूरे लैंडस्केप में सभी प्रक्रियाएँ Live exhibits का हिस्सा होगी । यह अनुभव हमारे नौनिहालों को ''कलाम'' बनने के लिए Wings of Fire प्रदान करेगा ।

...क्रमशः...

टर्न-26/आजाद/15.03.2021

..... क्रमशः ......

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, बोधगया, पूरे विश्व के मानस पटल पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति एवं बौद्ध धर्म के जन्मस्थली के रूप में बिहार को गौरवान्वित करता रहा है । सरकार लगभग 145 करोड़ की लागत से बोधगया में महाबोधि कल्चरल सेंटर का निर्माण करा रही है । बोधगया में स्टेट गेस्ट हाउस का निर्माण भी 128 करोड़ रू0 की लागत से किया जा रहा है ।

माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर को अक्षुण्ण रखने के साथ बुद्ध की धरती पर बुद्ध के संदेशों, जीवनी से आने वाली पीढ़ी को जागरूक करते रहने एवं वैशाली में खुदाई के दौरान प्राप्त भगवान बुद्ध के बहुमूल्य धरोहर

उनके अवशेष को बौद्ध वास्तु कला का अनुसरण करते हुए सुरक्षित 320 करोड़ की लागत से वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण करा रहे हैं ।

आधुनिक भारत के इतिहास में स्टोन मेसोनरी पर आधारित प्रथम स्तूप होगा । इस स्तूप की आयु 1000 वर्ष से ज्यादा होगी एवं भगवान बुद्ध के जीवन एवं वैशाली के महत्व को दर्शाने वाला अभिनव प्रयोग होगा ।

अध्यक्ष महोदय, विश्वस्तरीय संस्थाओं की श्रेणी में बिहटा में 248 करोड़ रू0 की लागत से दो एकेडमिक ब्लॉक, छात्रावास, 600 क्षमता के ऑडिटोरियम, स्पोर्टस फैसीलीटीज से युक्त डेवलपमेंट मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट का निर्माण कराया जा रहा है । यह गृह थ्री स्टार रेटिंग के मापदंडों से निर्मित किये जाने वाले इस भवन में Urban heat island effect का प्रभाव कम करने हेतु भी प्रावधान है ।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10वें गुरू गोविन्द सिंह जी के 350वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर किये गये कार्य से सम्पूर्ण विश्व का सिख समुदाय गौरवान्वित महसूस कर रहा है । इसी क्रम में 53.23 करोड़ की लागत से पटना में बहुद्देशीय प्रकाश पुंज के निर्माण के पश्चात् मालसलामी में 95.91 करोड़ रू0 की लागत से कम्यूनिटी हॉल का निर्माण कराया जा रहा है ।

कंगन घाट, पटना में लगभग 15 करोड़ रू0 की लागत से गुरू गोविन्द सिंह भवन का निर्माण कराया जा रहा है ।

महोदय, बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर कहते थे कि - Cultivation of mind should be ultimate aim of human existence.

बिहार सरकार की सजगता का परिणाम है कि एक तरफ राज्य में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रखंडों में 104 स्टेडियम-सह-खेल संरचनाओं के साथ कल्याण बिगहा में इन्डोर शूटिंग रेंज का निर्माण तो दूसरी तरफ प्राचीन मगध साम्राज्य के गौरवशाली अतीत वाले नगर राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी-सह-क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है । लगभग 740.82 करोड रू0 की लागत से 90 एकड़ के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 40,000 की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम के साथ कुश्ती एवं भारोत्तोलन, बॉली बॉल, बैंडमिन्टन मुक्केबाजी, Squash, Billiards, Archery, Shooting कबड्डी, जुडो, ताईक्वोन्डो जैसे खेलों हेतु छः स्पोर्टस कमप्लेक्स का निर्माण जारी है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अनुकूल माहौल एवं पर्याप्त अवसरों के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है । 2000 सीटों की क्षमता का प्रेक्षागृहों का निर्माण, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण में कराया जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट, बैठ जाइए ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण, समाज कल्याण, परिवहन विभाग का डिमांड है, प्रधान सचिव उनके हैं, मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं, बतावें ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : सब हैं । पहले एक बार सभी प्रधान सचिव का फोटो देख लीजिए, तब ऐसा बयान दीजियेगा, सब बैठे हैं ।

महोदय, सरकार नये निर्माण के साथ अपने धरोहरों को सहेज कर रखने हेतु प्रयासरत है । सरकार के द्वारा निर्मित बिहार म्यूजियम को निर्माण एवं वास्तुविदीय कौशल हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है । दूसरी ओर सरकार 71.50 करोड़ रू0 की लागत से पटना म्यूजियम का विस्तारीकरण एवं अप-ग्रेडेशन कर रही है ।

मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार में आजादी के बाद पहली बार इतने वृहद पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है ।

हमने पढ़ा था कि -

''पदं हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते''

Good qualities put their footprints everywhere.

जो व्यक्ति बड़ा होता है, वह नेता बड़ा होता है, वह योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है । हम अपने आपको गौरवशाली मानते हैं और महादलित परिवार से आते हैं और हमारे पिता जी को 1952 से लेकर 2000 तक नौ बार इस विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था । मुझे भी बिहार की जनता के आशीर्वाद से विधान सभा में दो बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है । मैं एक महादलित परिवार से आता हूँ, इसीलिए बताना चाहता हूँ कि लम्बे समय से इस प्रदेश में जो राजनीति दल के लोग थे, उन्होंने इस प्रदेश के वंचित समाज के लिए अतिपिछड़ों के लिए, दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम किया,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : लेकिन उनके लिए योजनाओं के निर्माण के लिए काम नहीं किया ।

अध्यक्ष : बैठिए । सबसे ज्यादा आप ही वरिष्ठ हैं । बैठिए आप, यह आदत ठीक नहीं है । अगर आप इस तरह से करेंगे, बैठिए आप ।

(व्यवधान)

आप बोलते रहिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि दलित राजनीति को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है । आजाद हिन्दुस्तान में कोई दलित नेता भी, कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने पिछले 15 सालों में दलितों के बजट को 40 गुना बढ़ाने का काम किया । जो लोग इस प्रदेश में दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, हम तो कहते हैं कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर, महात्मा गाँधी के बाद किसी ने उनके सपनों को साकार करने का काम किया है तो वह हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को समावेशी एवं सर्वांगीण विकास की अवधारणा का मूर्तरूप विभिन्न विभागों हेतु भवन निर्माण विभाग की प्राथमिकताओं में दिखता है ।

एक तरफ अल्पसख्यंक छात्र एवं छात्राओं हेतु 100 शैय्या वाले 55 छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति, एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय सह छात्रावास का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर कराया जा रहा है ।

अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत 100 सद्भाव मंडप का निर्माण कराया जा रहा है ।

राज्य के 101 प्रखंडों में लगभग 9 करोड़ प्रति इकाई की लागत से प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है । जिसमें 75 पूर्ण हो चुका है, शेष का कार्य प्रगति में है ।

81 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय-सह-आवासीय भवन का निर्माण का कार्य 12 करोड़ रू0 प्रति इकाई की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें 43 का कार्य पूर्ण है, शेष कार्य प्रगति में है ।

राज्य के 10 जिलों अररिया, पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी), शिवहर, पूर्णिया, पश्चिमी चम्पारण(बेतिया), कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा में बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण की योजना प्रति इकाई एक करोड़ की लागत से कुल 100 अदद् योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

महात्मा गॉंधी कहा करते थे कि –

"The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated."

और हमारे नेता ने महात्मा गॉंधी के सपनों को साकार करने के लिए पशुओं के प्रति भी सरकार की संवेदनशीलता जगजाहिर है । बिहार में पशु चिकित्सालयों का जाल बिछाया जा चुका है । अब सरकार 889.26 करोड़ रू0 की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण करा रही है ।

105 करोड़ रू0 की लागत से मुॅंगेर में वाणिकी महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

महोदय, सरकार शिक्षा में सुधारों के साथ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर रही है । सरकार पटना में 261.10 करोड़ की लागत से समेकित रूप से परीक्षा सम्पन्न करने हेतु परीक्षा परिसर का निर्माण करा रही है ।

(व्यवधान)

भवन निर्माण विभाग का स्वयं के योजना मद के बजटीय उपबंध से न्यायिक और गैर न्यायिक सरकारी भवनों के गुणवत्तायुक्त निर्माण का कार्य भी कराया जा रहा है । इन कार्यों का विभाग के द्वारा सतत् अनुश्रवण भी कराया जाता रहा है । अध्यक्ष महोदय, न्याय के साथ विकास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शासन का मूल मंत्र है ।

न्यायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी सरकार तत्पर रही है । 169.50 करोड़ रू0 की लागत से पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर आये थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि Rule of law जो है इस प्रदेश में, इस प्रदेश में Rule of law लाना चाहिए और माननीय नेता ने आग्रह किया था उस मंच से कि कानून का राज तभी कायम हो सकता है जब प्रगतिशील रूप से जो हम सतत् न्यायालय का यहां पर अनुश्रवण हो और जो क्रिमिनल एक्ट होते हैं, उसका स्पीडी ट्रायल हो और उसपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि Rule of law स्थापित होना चाहिए ।

महोदय, पिछले वर्ष वैश्विक आपदा कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व की तरह बिहार में भी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई । परन्तु इस विपदा की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किये गये उपायों की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है । भवन निर्माण विभाग के द्वारा भी विपरीत परिस्थितियों में भी भवन निर्माण कार्य बंद नहीं किया

गया । भवन के निर्माण कार्य को जारी रखा गया ताकि बिहार लौटने वाले श्रमिक भाइयों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें । इस दौर में बिहार वापस आने वाले बिहारी भाइयों के लिए क्वारेंटीन सेन्टर का भी निर्माण कराया गया । हमारे नेता मानते हैं कि -

''मुश्किलों के दौर में भी हौसला बनाये रखो ।
पत्थरों को फोड़ के भी फूल खिला करते हैं ।।''

सरकार की नीतियों के अनुरूप मात्र 20 मार्च, 2020 से लेकर फरवरी, 2021 तक बाहर से आये कामगारों को कार्य उपलब्ध कराते हुए 49 लाख 19 हजार 242 मानव दिवस का सृजन किया गया ।

...... क्रमशः ......

टर्न-27/शंभु/15.03.21

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : (क्रमशः) इस प्रकार से भवन निर्माण विभाग ने इस क्रम में मानवीय पक्ष को भी शामिल करने की कोशिश की है । महोदय, भवन निर्माण विभाग द्वारा- महोदय, जैसा कि मैंने चर्चा की है कि भवन निर्माण में मात्र संरचना का निर्माण ही नहीं होता है इस निर्माण कार्य में बिहार के कामगारों के लिए काम का भी सृजन करने का काम करती है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये आपलोग ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, मात्र भवन निर्माण विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के शासन अवधि में मार्च, 2019-20 तक इस विभाग ने 12 करोड़ 93 लाख 97 हजार 738 मानव दिवस सृजन का काम किया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री बोल रहे हैं सुनिए । आपलोगों को मौका मिला था । बोलिये मंत्री जी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार भवन निर्माण निगम के द्वारा कृषि महाविद्यालय किशनगंज, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन उद्यम संस्थान पटना, पटना व्यवहार न्यायालय परिसर, बगहा, बेतिया, गोपालगंज, सहरसा एवं कहलगांव में 58 कोर्ट कुल 813.6 करोड़ रूपये की लागत से 8.86 लाख मे0टन क्षमता के 554 पारंपरिक एवं फ्री फैब गोदाम, 191 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 620.85 करोड़, अनुमंडलों में 92 बुनियाद केन्द्र 201.02 करोड़, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत 560 आसनवाले 06 आवासीय उच्च विद्यालय 110.06 करोड़, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूर्णियां में 520 आसनवाले आवासीय उच्च विद्यालय 25.64 करोड़ एवं हस्तकरघा एवं रेशम भवन, भागलपुर 13.64 करोड़ का निर्माण कराया जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलते रहिये ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अंजुमन इस्लामिया, पटना 35.18 करोड़, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत समस्तीपुर एवं सासाराम में 520 आसनवाले आवासीय उच्च विद्यालय 51.28 करोड़, कुदरा कैमूर में बीज निगम के आधारभूत संरचना का कार्य 34.67716 करोड़, छज्जूबाग, पटना में बहुमंजिलीय आवासीय भवन 51.9203 करोड़, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत 720 आसनवाले कुल 38 विभिन्न आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण 1501.46 करोड़, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत 06 विभिन्न जिलों में जी श्री बहुद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण 63.35 करोड़ से कराया जा रहा है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

अध्यक्ष महोदय, निगम के द्वारा तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण, 12 विभिन्न जिलों में 200 आवासन क्षमता के वृद्ध आश्रय गृह का निर्माण, 11 विभिन्न प्रखण्ड सह अंचल सह आवासीय भवनों का निर्माण कार्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार एक्वेरियम तथा मत्स्य विकास भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 50 एवं 100 शैय्या वाले वृद्धाश्रम के निर्माण का कार्य भी लाल पहाड़ी लखीसराय के पुरातात्विक उत्खनन स्थल के संरक्षण का कार्य प्रगतिशील योजनाओं में है । निगम के द्वारा आधुनिक तकनीकों यथा पी0एम0आई0एस0 (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम), क्वालिटी मेनेजमैंट सिस्टम, जीयो टैगिंग एवं ऑनलाइन सेल्फी अटैडेंस के माध्यम से सभी कार्य स्थल पर कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का अनुश्रवण निगम मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है ।

हमारे युग दृष्टा एवं कालजयी सोच वाले नेता के संबंध में संस्कृत का यह श्लोक प्रासंगिक है कि-

''निश्चित्वा यः प्रक्रमते नान्तःवसति कर्मणः ।
अवन्धयकालो वश्यात्मा स वै पण्डित उच्यते ।।''

यानी जिनके प्रयास एक दृढ़ प्रतिबद्धता से शुरू होता है, जो कार्य पूर्ण होने तक आराम नहीं करते हैं, जो समय बर्बाद नहीं करते हैं और जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, वही बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान । वही प्रदेश को, देश को आगे लेकर चलते हैं । इस आर्यभट्ट की कर्मभूमि में एक अभियंता एवं बुद्धिमान मुख्यमंत्री होने का प्रभाव उनकी नीतियों एवं कृत्यों में सदैव झलकता है ।

अध्यक्ष महोदय,

‘‘थोड़ा सा और निखर जाऊं, यही मैंने ठानी है,
ऐ-जिन्दगी थोड़ा रूक, अभी मैंने हार नहीं मानी है ।’’

महोदय, उनका मानना है कि भवन महज ईंट, सीमेंट, सरिया और बालू से बने संरचना मात्र नहीं होते बल्कि कालखंड तथा अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति के साथ सरकार के विकास कार्यों को गति देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए हमारी जनता की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और सपनों को पूरा करने में मददगार करते हैं । उनके मार्गदर्शन में उनके नये बिहार की आधारशिला के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हम भवनों का निर्माण कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता ....

अध्यक्ष: मंत्री जी, अब संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: विपक्ष के लोग सब चले गये हैं हम उनके बारे में कहना चाहते थे, ये लोग इस समय हमेशा जो विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं और हमेशा उन्होंने अपने 15 साल के राजपाट को नहीं देखा कि किस तरह से 24 हजार करोड़ के बजट को माननीय नेता ने 2 लाख 18 हजार करोड़ करने का काम इस प्रदेश में शुरू किया है और इस प्रदेश में इनसे हम कहना चाहते हैं ।

‘‘लहजे में बद जुबानी, चेहरे पर नकाब लिये फिरते हैं,
जिनके खुद के बहीखाते बिगड़े हैं, वे हम सबका हिसाब लिये फिरते हैं ।’’

महोदय, हम बोलना चाहते हैं कि हम अपने इतिहास के पन्नों में राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं, ज्योतिबा फूले को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, ईश्वर चन्द विद्या सागर को पढ़ते हैं, जिन्होंने समय-समय पर आजादी से पहले और आजादी के बाद इस देश की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने का काम किया है । आजादी के बाद अकेले नेता नीतीश कुमार हैं, जिसने इस प्रदेश में और इस देश में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया । दहेज प्रथा पर प्रहार किया, बाल विवाह पर प्रहार किया, शराबबंदी पर प्रहार किया और हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए एक सीख देने का काम करते हैं । हम अपने माननीय नेता के बारे में कहना चाहते हैं -

‘‘बहुत सिरफिरी हवा है, तुम्हें संभलना ही होगा,
तुम ही आखिरी चिराग हो, तुम्हें जलना ही होगा ।’’

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं भवन निर्माण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 53 अरब 21 करोड़ 40 लाख 60 हजार रूपये के बजट का प्रस्ताव सदन के पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ । जिसमें स्थापना एवं

प्रतिबद्ध मद में 8788239000/- (आठ अरब अठहत्तर करोड़ बयासी लाख उनचालीस हजार रुपये) एवं रुपये 44425824000/- (चौवालीस अरब बयालीस करोड़ अठावन लाख चौबीस हजार रुपये) योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित है ।

हम माननीय अभिभावक विजय शंकर दूबे जी से आग्रह करते हैं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेते और सदन से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने के लिए एक नए बिहार का निर्माण करने के लिए इस मांग को अपना समर्थन देने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य, श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटायी जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''भवन निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 53,21,40,63,000/- (तिरपन अरब इक्कीस करोड़ चालीस लाख तिरसठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 33 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021 के 11:00 पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

भाषण प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस सप्तदश विधान सभा के द्वितीय सत्र में वितीय वर्ष 2021–22 हेतु बजट पर चर्चा के क्रम में मुझे भी कुछ बोलने का अवसर दिया गया है जिसके लिए मैं महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। महोदय, मैं बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज की चर्चा में अपने विचारों से हम सभी को अवगत करा रहे हैं। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग अपने चारो निदेशालयों जिन्हें हम आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त महिला विकास निगम और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अधीन गठित सोसायटी 'सक्षम' के माध्यम से बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं भिक्षुकों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन निरंतर किया जा रहा है।

महोदय विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए वितीय वर्ष 2021–22 के लिए विभाग को योजना मद में मांग संख्या–51 अन्तर्गत 809779.98 लाख (आठ हजार सनतान्वे करोड़ उनासी लाख अंठान्वे हजार) तथा स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय के लिए 6134.78 लाख (एकसठ करोड़ चौतीस लाख अठत्तर हजार) अर्थात विभाग को कुल **815914.76 लाख (आठ हजार एक सौ उनसठ करोड चौदह लाख छियत्तर हजार रू0)** का उद्व्यय प्राप्त है, जिसे सदन के पटल से स्वीकृत किया जाना है।

महोदय, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत चार महत्वपूर्ण निदेशालयों में से एक सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। महोदय, समाज कल्याण विभाग के द्वारा अक्टूबर, 2016 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेशनधारियों का पेंशन भुगतान डी0बी0टी0 मोड से करना प्रारंभ किया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महोदय, विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए सभी पेंशनधारियों का पूर्ण डाटाबेस ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

राज्य के वृद्धजनों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन हेतु एक महत्वपूर्ण योजना **'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना'** संचालित की जा रही है। इस योजना अन्तर्गत राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो और जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो, उन्हें 60–79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 400 (चार सौ) रूपये एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500 (पाँच सौ) रूपये का मासिक पेंशन प्रावधानित है, का संचालन किया जा रहा है। महोदय मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोरोना महामारी के दौरान भी पेंशन वितरण का कार्य निरंतर जारी रहा है। मार्च 2020 में ही लॉकडाउन के समय लगभग 85 लाख पेंशनधारियों को तीन माह (मार्च, अप्रैल तथा मई, 2020) का लगभग रू0 1,02,577/– लाख (एक हजार पच्चीस करोड सतहत्तर लाख रूपये) की राशि का अग्रिम भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाता में किया गया है।

वितीय वर्ष 2020–21 में सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (मुख्यमंत्री वृद्वजन पेंशन योजना सहित) में लगभग 94.62 लाख (चौरानवे लाख बासठ

हजार) पेंशनधारियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से फरवरी 2021 तक के पेंशन राशि का भुगतान किया गया है।

महोदय, इस निदेशालय के द्वारा दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में मृतक के पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता हेतु तीन योजनाएँ चलाई जा रही है जिसमें **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान एकमुश्त 20,000/– (बीस हजार) रूपया निकटतम आश्रित को दिया जाता है तथा **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना** अंतर्गत दुर्घटना या आपराधिक घटना में मृत्यु की स्थिति में उतनी ही राशि निकटतम आश्रित को दी जाती है। साथ ही **कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना** अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवार में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि क्रिया हेतु 3,000/– (तीन हजार) रूपया भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अन्तर्गत कुल 10,436 (दस हजार चार सौ छत्तीस), मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत 1075 (एक हजार पचहत्तर) एवं कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना अन्तर्गत 24,146 (चौबीस हजार एक सौ छियालीस) लाभुकों को ई–सुविधा के माध्यम से भुगतान किया गया है।

महोदय, दिव्यांगजनों के विवाह तथा अंतरजातीय विवाह के लिए **मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना** में पात्र लाभुकों को अब 1,00,000/– (एक लाख) रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है और पति–पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में दोनों को यह लाभ अलग–अलग दिया जाता है। साथ ही अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत पात्र लाभुकों को अब 1,00,000/– (एक लाख) रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है। अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत कुल 251 (दो सौ एकावन) लाभुकों को तथा दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अन्तर्गत 186 (एक सौ छियासी) लाभुको को भुगतान किया गया है।

महोदय, इस निदेशालय के अधीन एक सोसाइटी है ''सक्षम'' जिसके द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के अतिरिक्त **''बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुढ़ढीकरण परियोजना''** के तहत् वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं के लिए कई तरह की सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं। समाज के इन उपेक्षित वर्गों के कल्याण एवं उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक अनुमंडल में एक बुनियाद केन्द्र की स्थापना की गयी है और विभिन्न सुविधाओं से लैस मोबाईल थेरेपी वैन को प्रत्येक जिला में भेजा गया है। राज्य के सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय बुनियाद केन्द्रों पर 'बुनियाद संजीवनी सेवा' नामक मोबाईल आउटरीच थेरेपी वैन उपलब्ध करा दिया गया है। वैन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के लाभार्थियों (वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवाओं) को सेवाएं प्रदान की जा रही है। बुनियाद केन्द्रों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमतावर्धन होती है और दिव्यांग, वृद्ध तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल की सेवाओं का लाभ उन्हें आसानी से दिया जाता है। राज्य के सभी 101 अनुमण्डलों में बुनियाद केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 91 बुनियाद केन्द्रों का निर्माण कर हस्तांतरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, 10 अनुमण्डलों में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। बुनियाद केन्द्र के माध्यम से वृद्वजनों को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जांच एवं आधुनिक उपकरणों से उचित ईलाज किया जा रहा है। साथ ही उन्हें आवश्यक कानूनी एवं भावनात्मक परामर्श भी दिया जा रहा है। वृद्वजनों की आंखों का जांच कर चश्मा वितरण की जा रही है। सांस्थानिक सेवाओं के अतिरिक्त यह केन्द्र 'बुनियाद संजीवनी सेवा' (मोबाईल थेरेपी वैन) नामक विशेष वाहन से सुदूर क्षेत्रों में सेवाऍ प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह वाहन सामाजिक देखभाल से जुडे आवश्यक उपकरणों से लैस है। वाहनों में उपस्थित समर्पित टीम उन लाभुकों की पहचान कर सेवा प्रदान

करती है जो दूरी अथवा संसाधन हीनता के कारण बुनियाद केन्द्रों तक पहुचने में असमर्थ है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के दौरान सभी 101 बुनियाद केन्द्र पूरे लॉकडाउन अवधि के दौरान चालू रहे हैं। राज्य भर में 17 बुनियाद केन्द्रों को जिला प्रशासन के समन्वय में आईसोलेसन वार्ड के रूप में विकसित किया गया है। आईसोलेसन केन्द्र/आईसोलेसन वार्ड में प्रवासी व्यक्तियों के लिए बेड और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी और सभी केन्द्रों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया है। मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को भिक्षावृति के अभिशाप से मुक्त करना है। राज्य के 12 जिलों यथा पटना, गया, नालंदा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, सारण, अररिया, वैशाली एवं पूर्णियाँ में भिक्षाटन कर जीवनयापन कर रहे 10403 अति निर्धनों को चिन्हित कर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा वस्त्र वितरण, पहचान पत्र, आवासीय प्रमाणीकरण यू.आई.डी. आधार, बैंक खाता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता प्रमाणीकरण जैसे सामजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। भिक्षुकों में बचत की आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित बचत समूहों का गठन एवं संचालन किया जा रहा है। इसके 51 समूहों के अंतर्गत कुल 687 भिक्षुकों को संगठित किया गया है। भिक्षुकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। वैसे भिक्षुक जो जीविकोपार्जन के लिए स्वरोजगार करना चाहते हैं एवं सी बी एस जी का सदस्य हैं, उन्हें इस गतिविधि के माध्यम से 10 हजार रूपया तक प्रति व्यक्ति आर्थिक मदद दिया

जाता है एवं तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जाता है, अब तक 06 व्यक्तियों को लाभ दिया गया है।

महोदय, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के द्वारा जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है उनमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना जैसी कई योजनाएँ शामिल हैं। महोदय, पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत छः माह से छः वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है तथा समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएँ जैसी अन्य सेवाएँ भी प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 1,14,718 (एक लाख चौदह हजार सात सौ अठारह), आंगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के विरूद्व वर्तमान में संचालित कुल 1,11,115 (एक लाख ग्यारह हजार एक सौ पंद्रह) ऑगनबाडी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। पूरक पोषाहार के अन्तर्गत दूध तथा अंडा भी दिया जा रहा है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में केन्द्रांश एवं राज्यांश मिलाकर 179138.07 लाख (एक हजार सात सौ एकानवे करोड अड़तीस लाख सात हजार) का उदव्यय प्राप्त है।

महोदय, समाज कल्याण विभाग इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है कि आई0सी0डी0एस0 के तहत प्रदान की जा रही छः सेवाओं की मॉनिटरिंग और भी बेहतर ढंग से की जाय और इस दिशा में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन और सभी जिलों की पर्यवेक्षिकाओं को टैबलेट प्रदान किया गया है। पर्यवेक्षिकाओं को दिए गए

टैबलेट में 'ऑगन' ऐप है जिसके माध्यम से पर्यवेक्षिका आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर सीधे डैसबोर्ड पर रिपोर्ट भेज रही है।

महोदय, आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 आयु वर्ग के 28.96 लाख (अठाइस लाख छियानवे हजार) बच्चों को 400.00 रू0 (चार सौ रूपये) की दर से पोशाक की राशि उपलब्ध करायी गयी है।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण योजना **'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना'** अन्तर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुए वेज लॉस (wage Loss) के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र सभी गर्भवती/धातृ महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशर्त नगद लाभ पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से 5,000/– (पांच हजार) रू0 का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है। वर्तमान में कुल 2330089 (तेइस लाख तीस हजार नवासी) लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है।

महोदय, मुझे यह बताने में काफी खुशी हो रहा है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के मानदेय भुगतान को काफी आसान कर दिया गया है और डी0बी0टी0 मोड से सीधे उनके बैंक खातों में मानदेय भुगतान किया जा रहा है।

महोदय, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय की तरह समाज कल्याण निदेशालय की भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में जानकारी देना मैं जरूरी समझता हूँ। महोदय, **परवरिश** एक ऐसी ही योजना है। इस योजना अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं असाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों एवं

दुसाध्य रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता–पिता की संतान के अतिरिक्त वैसे भी अनाथ एवं बेसहारा बच्चे माने जायेगे जिनके माता–पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे के परवरिश करने में असमर्थ हो, को समाज में बेहतर पालन–पोषण एवं उनकी गैर सांस्थानिक देख–रेख को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लाभुक एवं अभिभावक के नाम से खोले गये संयुक्त बचत खाता में राशि सीधे हस्तांरित करते हुए दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों के पालन–पोषण हेतु सहायता राशि के रूप में 0–18 वर्ष तक के बच्चों के लिए रू0 1,000/–(एक हजार) प्रति माह की राशि दी जाती है। इस योजना का संचालन राज्य बाल संरक्षण समिति के माध्यम से किया जाता है। चालू वितीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 2155.00 लाख (एक्कीस करोड़ पचपन लाख रू0) का उदव्यय प्राप्त है तथा इस योजना के अन्तर्गत कुल 12208 (बारह हजार दो सौ आठ) बच्चों को आच्छादित किया गया है।

महोदय **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहन करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000 (साठ हजार) रूपये तक हो, की कन्या विवाह के समय मात्र 5000/– (पाँच हजार) रूपये का भुगतान कन्या के नाम DBT के माध्यम से किया जाता है। इस योजना अन्तर्गत 44,224 (चौवालीस हजार दो सौ चौबीस) लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

महोदय, मुझे यह बताने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने, जन्म निबंधन, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना** संचालित है। इसके तहत राज्य के सभी कन्याओं के जन्म से लेकर स्नातक तक के विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। संरक्षण–स्वास्थ्य–शिक्षा– स्वावलम्बन ये चार आयाम इस योजना के स्तम्भ है। इस योजना का कार्यान्वियन समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समेकित रूप से किया जा रहा है। इस विभाग के द्वारा कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खातें में रू0 2,000/– (दो हजार) दी जाती है तथा रू0 1,000/– (एक हजार) उक्त खातें में पुनः देय होगा। यह लाभ दो कन्या शिशु तक ही देय होता है। वितीय वर्ष 2020–21 में कुल 80.00 करोड का योजना उदव्यय/बजट उपबंध के विरूद्व 52.00 करोड व्यय कर 4,23,181 (चार लाख तेइस हजार एक सौ एकासी) कन्याओं को भुगतान किया गया है।

महोदय, समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है जिसमें राज्य बाल संरक्षण समिति के माध्यम से विभिन्न बच्चों एवं बच्चियों के लिए बाल गृह, बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह एवं विशेष गृह जैसे गृहो का संचालन किया जा रहा है। वहीं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के माध्यम से दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 23 बालक गृह, 11 बालिका गृह संचालित हैं, जिसमें अनाथ, बेसहारा, परित्यक्ता एवं बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। विधि विवादित बच्चों के लिए 14 पर्यवेक्षण गृह एवं 01 विशेष गृह

संचालित है। इसके अतिरिक्त 0–6 वर्ष तक के अनाथ बच्चों कें लिए 25 विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (SAA) संचालित है।

महोदय, विगत दो वर्षो में राज्य सरकार ने बाल संरक्षण से जुडी चुनौतियों के समाधान के लिए कई प्रयास किये है। इसी के तहत 18 वर्ष के उपरांत बच्चों को समाज के मुख्य धारा में समाहित करने के लिए ऑफ्टर केयर कार्यक्रम को एक प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में मान्यता देते हुए समाज कल्याण विभाग ने बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु विभिन्न आयामों को तलाशना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राज्य के विभिन्न बालिका गृहों में आवासित 14 बालिकाओं को बैंगलोर स्थित इको जुवेनाईल जस्टिस (Eco Juvenile Justice) के अन्तर्गत युरिंडियन एकेडमी (Eurindian Academy) में होटल मैनेजमेंट में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करने हेतु भेजा गया है।

महोदय, बालक, बालिका एवं शिशु के आवासन एवं पुनर्वास हेतु आश्रय गृहों के स्थापना एवं उनके समुचित संचालन के उद्देश्य से एक नयी योजना **'मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना'** की स्वीकृति दी गयी है। इसके अन्तर्गत राज्य के सभी नौ प्रमण्डलों के बारह जिलों में (प्रत्येक प्रमण्डल में कम–से–कम एक जिला) 'मुख्यमंत्री बाल आश्रय गृह' का निर्माण प्रकियाधीन है।

महोदय, समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला विकास निगम के द्वारा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है जिसमें 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' का उल्लेख करना मैं चाहूँगा। राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा संपोषित **'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना'** का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सेवा प्रक्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों यथा–कम्प्यूटर, ब्युटीशीयन, हाउस कीपींग,

सेल्स मैनेजमेंट, रोगी परिचारिका, नर्सरी, मोबाईल रिपेयरिंग में महिलाओं एवं किशोरियों का कौशल उन्नयन किया जा रहा है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महिला हेल्प लाईन, महिला अल्पावास गृह, रक्षा गृह आदि का संचालन किया जा रहा है।

महोदय, राज्य में जेंडर संवेदीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेंडर रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की गई है। सेंटर के माध्यम से विभिन्न विभागों एवं संगठनों के कर्मियों का जेंडर संवेदीकरण हेतु निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट–2 अन्तर्गत वृद्वजनों हेतु आश्रय स्थल गृह योजना आच्छादित है। सक्षम बिहार स्वावलंबी बिहार के अन्तर्गत विभाग से संबंधित स्वस्थ शहर विकसित शहर के तहत वृद्वजन आश्रय स्थल गृह का संचालन किया जाना है जिसके अन्तर्गत वृद्वजनों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जायेगा तथा इसके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जायेगी। वृद्वाश्रम संचालन में गुणात्मक सुधार लाने, उनके गुणवत्ता एवं क्षमता में वृद्वि करने तथा पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से एक नयी योजना **'मुख्यमंत्री वृद्वजन आश्रय स्थल योजना'** प्रस्तावित है।

उक्त नयी योजना के अन्तर्गत राज्य के निराश्रित, उपेक्षित, बेसहारा एवं अन्य नागरिकों को आश्रय सहित अन्य सुविधाओं के माध्यम से उन्हें स्वस्थ एवं गरिमापूर्ण जीवन–यापन में सहायता प्रदान किया जाना है। उसके अन्तर्गत राज्य के सभी जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक, चाहें वह निर्धन न हो, के विभिन्न स्तरों की समस्याओं को समेकित रूप से समाधान करने, उन्हें विभिन्न प्रकार के समयानुकूल आवश्यक सुविधाएँ यथा– स्वास्थ्य, मनोरंजन, योग तथा आजीविका के लिए क्षमतावर्धन एवं अन्य क्रियाकलाप में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। उक्त योजना समाज कल्याण

विभाग अन्तर्गत सोसाइटी 'सक्षम' के माध्यम से राज्य के सभी जिला मुख्यालय में वृद्वजनों के आश्रय हेतु 100 बेड (50–50 की दो यूनिट) तथा सभी जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त अन्य अनुमण्डलों में 50 बेड (एक यूनिट) के आवासन क्षमता वाले आश्रय स्थल का संचालन किया जाना है। तात्कालिक रूप से 01 अप्रैल 2021 से जिला स्तर पर संचालन हेतु बुनियाद केन्द्र के कर्मियों के अतिरिक्त अन्य मानव बल आउटसोर्स (Pay-roll management) के माध्यम से संचालित किया जाना है। जिला स्तर पर संचालन में प्राप्त अनुभव एवं आवश्यकता के आधार पर अनुमण्डल स्तर पर भी वृद्वजन हेतु आश्रय स्थल का संचालन किया जाना है।

महोदय, सरकार की लोक कल्याणकारी अवधारणा को मजबूत करने और उसका औचित्य बनाए रखने के लिए समाज कल्याण विभाग योजनाबद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयासरत है और मुझे विश्वास है कि इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग भी हमे मिलता रहेगा। इसलिए महोदय, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मेरे द्वारा जो मांग रखी गई है उसे पारित करने का अनुरोध करता हूँ तथा इसी के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।

धन्यवाद।